राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 214

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 11 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रानी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित

>> 15

कश्मीर में इंटरनेट पर बेमियादी पाबंदी ठीक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम व्यवस्था ▶ कोर्ट ने कहा, उचित वजहों से खतरे की आशंका पर भी लगाई जा सकती है धारा 144

एक हफ्ते के भीतर संचार सेवाओं व अन्य पाबंदियों की समीक्षा का दिया आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आधुनिक युग की जरूरतों में इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दूरगामी फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति व व्यापार के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाना संवैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाना संविधान में संरक्षित है। इंटरनेट पर बेमियादी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने पाबंदी लगाने के आदेश की समीक्षा का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, धारा 144 न सिर्फ खतरा होने बल्कि खतरे की आशंका पर भी लगाई जा सकती है लेकिन ऐसा आदेश जारी करने के पीछे तर्कसंगत और वास्तविक आधार होने चाहिए। बार-बार धारा 144 का आदेश जारी करना शक्ति का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमना, आर. सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने यह आदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। ये याचिकाएं कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दाखिल की थीं। धारा 144 शांति भंग की आशंका पर मजिस्ट्रेट के आदेश से जारी होती है जिसमें एक जगह चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 130 पृष्ठ का विस्तृत फैसला दिया है।

शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया है कि वह धारा 144 लागू करने के आदेश और इंटरनेट सेवा आदि निलंबित करने के सारे आदेशों को प्रकाशित कराए, ताकि प्रभावित लोग उन आदेशों को हाईकोर्ट या संबंधित अदालत में चुनौती दे सकें। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और इंटरनेट के जरिए व्यापार करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की आजादी) और 19(1)(जी) (व्यापार की आजादी) के तहत संरक्षित अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) और (6) के तहत लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे करते समय आनुपातिक सिद्धांत यानी टेस्ट आफ प्रपोशनेलिटी का ध्यान रखा जाएगा।

कोर्ट ने कहा, इंटरनेट सेवा का बेमियादी निलंबन की टेलीकाम सर्विस रूल में मनाही है। नियम के तहत ऐसा आदेश आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। इंटरनेट सेवा का निलंबन तय समय से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में तय नियमों के मुताबिक इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के आदेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक नियम की यह कमी पूरी नहीं होती तब तक निलंबन नियम 2(5) के तहत समीक्षा समिति गठित की जाएगी और यह समिति नियम 2(6) के तहत सात कार्य दिवस के भीतर निलंबन आदेश की समीक्षा करेगी। साथ ही कहा कि जो आदेश इस फैसले में तय नियमों के मुताबिक न हो वे तत्काल रद किए जाएं। अगर भविष्य में ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत हो तो इस फैसले में तय व्यवस्था का पालन किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन जगहों पर जहां इंटरनेट सेवा चालू नहीं है, सरकारी वेबसाइट, स्थानीय वेबसाइट, ई बैंकिंग सुविधा, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाएं बहाल करें। सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश की स्थिति स्पष्ट करने हुए कोर्ट ने कहा,धारा 144 की शक्ति सिर्फ उपचारत्मक ही नहीं निरोधक भी है। इस धारा का प्रयोग खतरे की आशंका पर भी किया जा सकता। हालांकि खतरा आपातकालिक होना चाहिए और ऐसे खतरे को रोकना इसका उद्देश्य होना चाहिए।

सरकारी व स्थानीय वेबसाइट, ई बैंकिंग सुविधा, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाएं बहाल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट — फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां...

कोर्ट का काम स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कायम रखना है। स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच हमेशा टकराव रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी ज्यादा जरूरत है, दोनों के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है।

इंटरनेट मूलभूत अधिकार से संबद्ध है लेकिन चूंकि किसी ने भी इसे भूलभूत अधिकार घोषित करने की मांग नहीं की है। इसलिए हम इसे मूलभूत अधिकार नहीं कह रहे हैं, पर यह तय है कि यह संवैधानिक अधिकार है।

देश में शरणार्थी बने पंडितों ने राजनयिकों को सुनाया दर्द

जम्मू : 'यह रैन बसेरा है, घर नहीं। हमारा सिर्फ कत्ल नहीं हुआ,वजूद मिटाया गया। हम घाटी लौटना चाहते हैं। यह तभी होगा जब दिल में इस्लामिक आतंकवाद का खौफ न हो, यह बात 15 देशों के राजनयिकों के समक्ष विस्थापित पंडितों ने कही (पेज-7

पाक ने आतंक फैलाया, कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने भेदभाव

जम्मू : पाकिस्तान ने घुसपैठ वगोलाबारी कर जम्मू में आतंक फैलाया तो कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने जम्मू वासियों का हक मारा। कश्मीरी पंडित घर से बेघर हो गए और पश्चिमी पाकिस्तान के निवासी अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भेदभाव खत्म होगा और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। (पेज-7)

सरोकार

गाड़ी कितनी भी खराब हो, ठीक करना जानती है...

कांगड़ा : जिंदगी की गाड़ी कतई ठीक नहीं थी, सिर से मां-बाप का साया छिन जाने के बाद भाई ने सहारा दिया। ट्रैक्टर चलाना सीख जिंदगी की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी। और अब कोई भी गाड़ी कितनी ही खराब हो, स्नेहलता उसे ठीक करना सीख गई है। (पेज-6)

जागरण विशेष

नदी किनारे बसे गांव ने ऐसे दी सूखे को मात

रायपुर : छत्तीसगढ़ का बगदई गांव नदी के किनारे बसा है, लेकिन यहां के किसान पानी को तरसते थे। गांव के युवकों ने खेतों के किनारे तालाबनुमा गड्ढे तैयार कर नदी के पानी से इन्हें लबालब कर दिया, तो समस्या दूर हो गई। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

भारत की चिंता, कहीं सिरदर्द न बन जाए श्रीलंका

नई दिल्ली : श्रीलंका में चीन समर्थक गोताबाया राजपक्षे की सरकार बनने के साथ ही भारत की आशंका सही साबित होती दिख रही है। चुनाव जीतने के बाद राजपक्षे ने भले ही भारत की यात्रा की हो लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की नई सरकार चीन के हितों के अनुरूप काम शुरू कर चुकी है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

उप्र एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग का सरगना मेरठ से गिरफ्तार

मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस के त्वरित कार्यबल (एसटीएफ) ने सॉल्वर गैंग के सरगना नकल माफिया अरविंद राणा उर्फ गुरुजी को गुरुवार रात मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। 25 हजार के इनामी अरविंद को दिल्ली में चल रही फायर सर्विस भर्ती में सेंधमारी के लिए जाते समय दबोचा गया।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

पेट्रोलियम मांग में चीन को पछाड़ देगा भारत

नई दिल्ली : भारत की आयातित क्रूड पर निर्भरता बढ़ने लगी है। 2020 के मध्य तक भारत में क्रूड की मांग चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय इनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए भारत के पास तेल का रणनीतिक भंडार ज्यादा दिनों का होना चाहिए ताकि वह वैश्विक अस्थिरता का सामना कर सके।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

युद्ध छेड़ने के ट्रंप के अधिकार पर रोक का प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन : अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से युद्ध के प्रति अनिच्छा जता दी। सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमला करने के अधिकार पर भी प्रतीकात्मक रोक लगा दी। यह प्रस्ताव अभी सीनेट में भी जाना है, जहां इसके पारित होने की उम्मीद बहुत कम है।

सायरस मिस्त्री की बहाली पर कोर्ट ने लगाई रोक

- शीर्ष अदालत ने एनक्लैट के फैसले को गलत पाते हुए रोक लगाई
- ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ टाटा संस ने दायर की है याचिका

साइरस मिस्त्री फाइल फोटो।

ट्रिब्यूनल का आदेश हमें पहली नजर में ही सही नहीं लगा। याचिका में पद पर मिस्त्री की बहाली की कोई मांग नहीं थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने आगे बढ़कर यह आदेश सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जो की ही नहीं गई थी।
– सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सायरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन के पद पर बहाल करने के एनक्लैट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले में खामियां हैं। एनक्लैट के फैसले के खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सीजेआइ एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की।

एनक्लैट ने सायरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सायरस मिस्त्री को राहत देते हुए 18 दिसंबर के फैसले में सायरस को टाटा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही चेयरमैन के रूप में चंद्रशेखरन की नियुक्ति को गैरकानूनी बता दिया था। टाटा संस ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को सिरे से नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। टाटा संस का कहना था, 'मामले को नतीजे तक पहुंचाने के बजाय ट्रिब्यूनल के फैसले ने कभी ना खत्म होने वाली समस्या का बीज बो दिया और शेयरधारकों के बीच टकराव की स्थिति बना दी।' टाटा संस ने कानूनी पहलुओं को आधार बनाकर भी फैसले पर सवाल उठाया था।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सायरस इन्वेस्टमेंट की ओर से पेश अधिवक्ता सीए सुंदरम ने अदालत से कहा कि एनक्लैट के फैसले पर रोक लगाने के बजाय नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा जाना चाहिए। मिस्त्री के वकील एक अंतरिम व्यवस्था चाहते थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश में खामियां मिली हैं। फिलहाल अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाते हुए सायरस मिस्त्री व अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

कब क्या हुआ?

- **24 अक्टूबर, 2016 : सायरस को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया। रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने**
- **20 दिसंबर, 2016 : मिस्त्री परिवार की दो कंपनियों, सायरस इंवेस्टमेंट्स और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने टाटा संस के बोर्ड के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया**
- **12 जनवरी, 2017 : टीसीएस के तत्कालीन सीईओ एवं एमडी एन चंद्रशेखरन टाटा संस के चेयरमैन बने**
- **06 फरवरी, 2017 : मिस्त्री की टाटा संस के निदेशक मंडल से भी छुट्टी**
- **17 अप्रैल, 2017 : एनसीएलटी मुंबई ने मिस्त्री परिवार की दोनों इंवेस्टमेंट कंपनियों की अपील खारिज की**
- **27 अप्रैल, 2017 : दोनों कंपनियों ने एनसीएलटी की तरफ से अपील खारिज किए जाने को एनसीएलएटी में चुनौती दी।**
- **21 सितंबर, 2017 : एनक्लैट ने दोनों निवेश कंपनियों की अपील स्वीकार की, लेकिन मिस्त्री की अन्य याचिकाएं खारिज कर दीं।**
- **29 अगस्त, 2019 : एनक्लैट ने मिस्त्री की तरफ से निजी क्षमता पर दायर याचिका मंजूर की और इसकी सुनवाई दो इंवेस्टमेंट कंपनियों की मुख्य याचिकाओं के साथ करने का फैसला किया।**
- **18 दिसंबर, 2019 : एनक्लैट ने मिस्त्री को वापस टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बनाने का आदेश दिया।**
- **10 जनवरी, 2020 : सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लैट के फैसले पर रोक लगाई। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद।**

जेएनयू हिंसा में आईशी घोष समेत नौ छात्रों की पहचान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सात छात्र वामपंथी संगठनों से तो दो दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े
- क्राइम ब्रांच ने सभी को भेजा नोटिस, जल्द होगी पूछताछ

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में रविवार (5 जनवरी) को हुई हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को नौ छात्रों की तस्वीर जारी की है, जिनमें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष भी शामिल हैं। इनमें सात छात्र वाम संगठनों से जुड़े हैं, जबकि दो दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस ने हिंसा के मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। नोटिस भेजकर उनसे जबाव मांगा है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टिर्की ने प्रेसवार्ता कर बताया कि हिंसा में शामिल अब तक नौ लोगों की पहचान की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हुई है। फुटेज में ये छात्र हाथों में डंडा लिए और पथराव करते दिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच जल्द ही इन लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। अभी तक 32 लोगों से पूछताछ की गई है।

इनकी हुई पहचान : डीसीपी ने बताया कि पहचाने गए लोगों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष, पूर्व छात्र चुनचुन कुमार, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र पंकज मिश्रा, संस्कृत के शोध छात्र योगेंद्र भारद्वाज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज के छात्र प्रिया रंजन, स्टडीज ऑफ कोरियन लैंग्वेज के विकास पटेल, स्कूल ऑफ सोशल साइंस-सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज के डोलन समांता, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सुचेता तालुकदार व एमए के छात्र वास्कर विजय शामिल हैं। इनमें विकास पटेल व योगेंद्र भारद्वाज दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े हैं, जबकि बाकी सात का संबंध वामपंथी छात्र संगठनों से हैं।

वाट्सएप ग्रुप बनाकर मारपीट के वीडियो शेयर किए : डीसीपी जॉय टिर्की के अनुसार, योगेंद्र भारद्वाज ने रविवार को घटना के वक्त यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का वाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके बाद इस ग्रुप में मारपीट के वीडियो शेयर किए गए थे।

हिंसा में 37 लोग हुए थे घायल : दरअसल, गत रविवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने जेएनयू परिसर में घुसकर पेरियार, साबरमती, नर्मदा हॉस्टल और परिसर के कुछ अन्य जगहों पर छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में छात्र, शिक्षक व सुरक्षाकर्मियों समेत कुल 37 लोग घायल हुए थे, जिनमें आईशी घोष भी शामिल हैं। पुलिस ने अलग-अलग ग्यारह मुकदमे दर्ज किए हैं।

पुलिस बरत रही सावधानी : मामले की जांच में पुलिस बहुत ही सावधानी बरत रही है। डीसीपी जॉय टिर्की सहित 64 पुलिसकर्मियों की टीम जांच में जुटी है। डीसीपी ने बताया कि चूंकि जेएनयू परिसर से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है लिहाजा वायरल वीडियो, स्थानीय छात्र, शिक्षक और लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यह जांच भी हो रही है कि कहीं बाहरी छात्र तो कैंपस में नहीं आए थे।

निर्दोष पर नहीं की जाएगी कार्रवाई : दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता (पीआरओ) एमएस रंधावा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने पर छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पुलिस सतर्क है कि किसी निर्दोष को न पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जिन छात्रों की तस्वीर जारी की गई है वे लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन कर राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। अधिकांश पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

नई दिल्ली में शुक्रवार को डीसीपी (क्राइम) जॉय टिर्की (बाएं) ने जेएनयू हिंसा में आईशी घोष की तस्वीर जारी की। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रेट्र

जेएनयू की जंग (विशेष) पेज>>5

कन्नौज में ट्रक-बस की भीषण टक्कर, 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जले

जागरण संवाददाता, कन्नौज : उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जयपुर जा रही स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 10 से अधिक लोग जिंदा जल गए। 22 यात्री जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसा शुक्रवार को जीटी रोड पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का डीजल टैंक फट गया और दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री को भी मौके पर जाकर लोगों की हरसंभव मदद मुहैया कराने को कहा है है। यह दुर्योग ही है कि 13 जून 2018 को दिल्ली से फर्रुखाबाद लौटते हुए इसी ट्रैवल्स की बस इटावा में डिवाइडर से टकरा गई थी। इसमें मौके पर ही 17 लोगों की मौत हो गई थी।

26 किमी बाद ही हादसा पेज>>15

बर्फबारी से निखरा सरोवर नगरी का सौंदर्य

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ताजी बर्फबारी के बाद ठंड की चुभन भले ही गहरी हो गई हो लेकिन इस सरोवर नगरी का सौंदर्य और निखर गया है। खिली धूप में बर्फ से लकदक पहाड़ियां खूब चमक बिखेर रही हैं। इसके बीच प्रसिद्ध नैनी झील का आकर्षण देखते ही बनता है। यहां के इस खूबसूरत नजारे को निहारता युवक। दामोदर लोहनी

शोध में दावा

देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से हलकान है, ठंड के मौसम में यह खतरनाक स्तर को भी पार कर जाती है, हालांकि सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वह नाकाफी ही साबित हो रहे हैं

ट्रैफिक-निर्माण कार्यों से जहरीली है दिल्ली-एनसीआर की हवा

नई दिल्ली, आइएएनएस : ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय में हुए हालिया शोध में दावा किया गया है कि ज्यादा ट्रैफिक, निर्माण व घरेलू कार्यों में मशीनों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली ऊष्मा के कारण दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की हवा प्रदूषित हो रही है। इसी कारण हवा में प्रदूषण के बेहद घातक कण घुले हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जहरीली हवा के लिए ग्लोबल वार्मिंग या कोई वैश्विक कारण नहीं, स्थानीय हालात ही ज्यादा जिम्मेदार हैं।

सरे विश्वविद्यालय में हुए शोध को सस्टेनेबिल सिटीज एंड सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 12 स्थानों से चार साल तक प्रदूषण के आंकड़ों को एकत्रित किया। अध्ययन में इस बात का पता चला कि इन क्षेत्रों में प्रदूषित कण पीएम 2.5 और पीएम10 (नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड और ओजोन गैस) हैं। इन सबके प्रभाव से देश का यह हिस्सा सर्वाधिक प्रदूषित है।

- सरे विश्वविद्यालय में किए गए शोध में किया गया दावा
- शोध के मुताबिक, प्रदूषित हवा के लिए स्थानीय कारण मुख्य वजह
- दिल्ली, हरियाणा,उप्र के 12 वर्षों से चार साल तक लिए आंकड़े

दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए मॉस्क लगाना मजबूरी बन गया है। फाइल फोटो

शोधकर्ता प्रशांत कुमार ने कहा, पर्यावरण परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एजेंडा ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सभी देशों में सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारे विश्लेषण से दिल्ली में प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की अहम भूमिका का पता चलता है। इसमें वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों से भी तापमान बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। दिल्ली क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर इसका बेहद बुरा असर होता है।

प्रशांत कुमार ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के महीनों में बुरा असर पड़ने का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक चले अध्ययन के बावजूद यह ट्रेंड स्पष्ट है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है। हवा में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म कण (पीएम2.5 और पीएम 2.5-10) जाड़े के महीनों में अत्यधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आसपास के इलाकों में जलाई गई पराली के धुएं से भर जाती है। घरों से पैदा होने वाली ऊष्मा से भी प्रदूषण में इजाफा होता है। हवा की गति भी वायु प्रदूषण की तीव्रता के लिए जिम्मेदार है। अनुसंधान टीम ने शोध की अवधि में इन जिलों के मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर भी पाया कि प्रदूषण के लिए स्थानीय स्रोत ही अधिक जिम्मेदार हैं।

भारत में सालाना छह लाख लोगों की होती है मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, वायु प्रदूषण से वर्ष 2016 में पूरे विश्व में करीब 42 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में सालाना छह लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। विश्व में वायु प्रदूषण के कुछ उच्चतम स्तर दिल्ली में देखे जा सकते हैं।

चंदा कोचर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 78 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार के मामले में आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उनकी 78 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली है।

शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि चंदा कोचर व उनके परिवार की संपत्तियों को जब्त करने के लिए मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थाई आदेश जारी किया गया था। जब्त संपत्तियों में कोचर का मुंबई स्थित फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की एक कंपनी की कुछ संपत्तियां शामिल हैं। जब्त संपत्तियों का मूल्य 78 करोड़ रुपये है।

चंदा कोचर के खिलाफ यह कार्रवाई 2012 में आइसीआइसीआइ बैंक से विडियोकॉन इंडस्ट्रीज को मिले 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में की गई है। विडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा दीपक कोचर की कंपनी में किए गए निवेश में गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर, 2018 में इस्तीफा दे दिया था।

- मनी लांड्रिंग केस में आरोपित हैं आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ
- बैंक की कर्जदार विडियोकॉन पर कोचर के पति को फायदा पहुंचाने का आरोप

चंदा कोचर (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्ज देने में भ्रष्टाचार का दर्ज किया था केस पेज>>3

13.82 लाख मतदाता 2015 विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़े हैं, जबकि 89,777 कर्मचारी मतदान के दौरान तैनात किए जाएंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 11 जनवरी 2020

वार ▸ पूर्व विधायक शोएब इकबाल को पार्टी में शामिल करने को लेकर आप पर भाजपा का हमला

विपक्ष खेल रहा है तुष्टीकरण का 20-20 : पात्रा

कांग्रेस-वामपंथियों पर ममता बनर्जी का बयान वोट बैंक बचाने की कोशिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शोएब इकबाल को पार्टी में शामिल करने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शोएब इकबाल के खिलाफ आपराधिक मामलों और उनके बेटे मुहम्मद इकबाल के शरीयत की वकालत करने के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वोट बैंक की खातिर आप तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ रही है। पात्रा के अनुसार आप ही नहीं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एएआइएमआइएम, सपा, बसपा और वामपंथी पार्टियां मुसलमान भाइयों को भड़का कर पूरे देश में हिंसा और आगजनी का माहौल बना रही हैं। पात्रा ने इसे 'वोटबैंक के लालच में विपक्ष तुष्टिकरण का 20-20 मैच' बताया।

कांग्रेस के पूर्व विधायक शोएब इकबाल को आप में शामिल किए जाने पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल

संबित पात्रा। (फाइल)

मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह वही शोएब इकबाल हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल जेल में डालना चाहते थे, जिन पर हत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही शोएब इकबाल के बेटे मुहम्मद इकबाल ने शरीयत की पैरवी करने का भाषण दिया था।

भाजपा प्रवक्ता के अनुसार वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष की आपसी कलह सामने आने लगी है। बंगाल में हिंसा के लिए कांग्रेस व वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराने और सोनिया गांधी की बुलाई विपक्ष की बैठक का बहिष्कार करने के ममता बनर्जी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे चचेरे-ममेरे भाई-बहन आज एक-दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा रोकने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सत्ता में आने के बाद पेंशन देने के सपा नेताओं के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है।

भाजपा ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की शहादत की परिभाषा बताते हुए संबित पात्रा ने कहा कि वह सेना प्रमुख बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहती हैं, लेकिन जो लोग आगजनी कर रहे हैं, उन्हें शहीद बताती हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को कोटा जाने की चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास दंगाइयों से मुलाकात करने का समय है, लेकिन कोटा की उन माओं से मिलने का समय नहीं है जिनके नौनिहाल लगातार काल के गाल में समा रहे हैं।

सिसोदिया का पलटवार, अपराधी हैं शोएब तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शोएब को अपराधी कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर उन्हें अपराधी मानती है, तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जेल से बाहर खुलेआम वह अब तक कैसे घूम रहे हैं। दरअसल, आप में शामिल होते ही कोई भी नेता भाजपा के लिए अपराधी बन जाता है। मटिया महल से पांच बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने गुरुवार को आप की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद भाजपा ने उन पर हत्या व दंगा कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस पर पलटवार करते हुए पार्टी मुख्यालय में सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की नजर में आप के नेता या आप में शामिल होते ही नेता अपराधी कैसे हो जाते हैं? शोएब हत्या के आरोपित होने के बाद भी छह साल से खुलेआम घूम रहे हैं, तो यह भाजपा के लिए शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस केंद्र के पास

आप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया। दिल्ली पुलिस आप से अगर संभल नहीं रही तो छोड़ दीजिए, हम चलाकर दिखाएंगे। राजधानी में यदि कहीं कोई अपराधी होगा, चाहे वह हमारी पार्टी में हो या फिर आपकी पार्टी में सभी को जेल भेजकर दिखाएंगे। लेकिन ऐसे चुनावी जुमले मत छोड़िए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आप पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, लेकिन वास्तव में इसका मास्टर कौन है। यह बताने की जरूरत नहीं हैं।

केजरीवाल के कामों का हिसाब देगी टीम जयहिंद

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

पार्टियों की रणनीति

- हरियाणा के आप कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुटे
- दुष्यंत चौटाला की जजपा का जवाब देते नजर आएंगे आप कार्यकर्ता

दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की टीम केजरीवाल सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने दिल्ली चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को रोहतक में बैठक बुलाई है। इसमें दिल्ली चुनाव में काम करने वाली टीमें फाइनल होंगी तथा उन्हें दिल्ली की अलग-अलग विधानसभा सीटें सौंपी जाएंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा करने के बाद नवीन जयहिंद ने हरियाणा के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। आउटर दिल्ली की करीब एक दर्जन सीटें ऐसी हैं, जो हरियाणा की सीमा से सटी हैं। दिल्ली में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी भी यदि ताल ठोंकती है तो जजपा और आप कार्यकर्ता एक-दूसरे के सामने डटे नजर आएंगे।

आप की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष पंडित नवीन जयहिंद ने बताया कि राज्यसभा सदस्य डॉ. सुशील गुप्ता और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय से भी सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के पार्टी कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। शनिवार की मीटिंग में विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली टीम का भी गठन होगा। यह टीम अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर केजरीवाल सरकार के कामों का प्रचार-प्रसार करेगी।

नवीन जयहिंद के अनुसार, हरियाणा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। मुफ्त बिजली-पानी, मुफ्त इलाज व दवाइयां, मुफ्त सीटी स्कैन व एमआरआइ, मोहल्ला क्लीनिक, निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज, महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर, शहीद के परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता, किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा और बेहतरीन सरकारी स्कूलों के मुद्दों पर आप कार्यकर्ता लोगों से वोट मांगेंगे।

ट्विटर वार

- भाई मनोज तिवारी जी, हरियाणा में उपमुख्यमंत्री को बिना बिजली के काम करना पड़ता है। दिल्ली में आप हजार यूनिट मुफ्त देने की फेंक रहे हैं। कम से कम अपने राज्यों में बिजली तो पूरी दे दो भाजपाइयों, फ्री का सपना मत देखो तुमसे न हो पाएगा
  -संजय सिंह, आम आदमी पार्टी
- 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली का बुरा हाल। प्रदूषण और गंदा पानी इसका उदाहरण है। इसका सबसे बड़ा सुबूत तो यह है कि उनको अंतिम दो महीनों में मुफ्त की घोषणाएं और करोड़ों रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने पड़े, यहां तक कि टेलीविजन पर प्रायोजित झूठे कार्यक्रम करवाने पड़ रहे हैं।
  -विजय गोयल, भाजपा
- कल तक एनआरसी और दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई पर पानी पी-पी कर केजरीवाल को कोसनेवालों का आज अचानक हृदय-परिवर्तन! कोई गहरा राज है या मजबूरी? आखिर कौन सी डील है?
  -मुकेश शर्मा, कांग्रेस

चुनावी हलचल

प्रदेश कांग्रेस ने बनाया उत्तर-पूर्व प्रकोष्ठ

नई दिल्ली : दिल्ली में बड़ी संख्या में रह रहे उत्तर-पूर्व के लोगों को कांग्रेस के साथ स्थायी तौर पर जोड़ने की नीयत से उत्तर-पूर्व प्रकोष्ठ का गठन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह दिल्ली में संगठन को और मजबूती प्रदान करेगा। वहीं, उन्होंने प्रदेश कार्यालय में भाजपा व आप के कई दलित नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दलित नेता व पूर्व सांसद डॉ. उदित राज व मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। चोपड़ा ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी पदाधिकारियों और नेताओं को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। (जासं)

48 घंटे में पूरा हुआ आप का क्राउड फंडिंग अभियान

नई दिल्ली : आप का क्राउड फंडिंग अभियान 48 घंटे के भीतर ही पूरा हो गया। हालांकि इसके लिए पार्टी ने चंदा जुटाने के लिए एक महीने का समय दिया था। लेकिन दो दिन के भीतर ही तय लक्ष्य पूरा हो गया। इसके बाद अभियान बंद कर दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी शुरुआत की थी। विधानसभा चुनाव में फंड की कमी न होने पाए इसलिए ऑनलाइन फंड रेजिंग अभियान की शुरुआत की गई थी। (जासं)

20 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी तय आज जारी हो सकती है सूची

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विस चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस 20 उम्मीदवारों की सूची शनिवार रात जारी कर सकती है। इन सीटों में से ज्यादातर पर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन एक-दो सीटों पर कुछ बड़े नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है। पार्टी पुराने दिग्गजों के साथ-साथ इस बार अनेक जगह जिलाध्यक्षों और कुछ सीटों पर नेताओं के बच्चों पर भी दांव लगा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तीन दिन से लगातार चल रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 30 से 35 पर एक-एक नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। इन सभी नामों को शनिवार शाम होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में रखा जाएगा। संभावना है कि इनमें से ज्यादातर नामों को स्वीकृति दे दी जाएगी। हालांकि, पहले चरण में पार्टी लगभग 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम ही घोषित करने पर विचार कर रही है।

सूत्र बताते हैं कि इन सीटों में से ज्यादातर पर पार्टी ने पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों पर ही भरोसा जताया है। कई सीटों पर नए नाम सामने आए हैं तो कई सीटों पर पार्टी ने अपने पदाधिकारियों पर दांव खेला है।

पहली सूची में शामिल कुछ प्रमुख सीटें और संभावित उम्मीदवार

सीट	संभावित नाम
कृष्णा नगर	डॉ. एके वालिया
सीलमपुर	चौ. मतीन अहमद
चांदनी चौक	अलका लांबा
हसन अहमद	मुस्तफाबाद
बवाना	सुरेंद्र कुमार
जंगपुरा	तलविंद्र मारवाह
सुल्तानपुर माजरा	जयकिशन
समयपुर बादली	देवेंद्र यादव
वजीरपुर	हरिकिशन जिंदल
आदर्श नगर	मुकेश गोयल
बल्लीमारान	हारून यूसुफ
बिजवासन	विजय लोचव
हरी नगर	सुभाष सेतिया
मॉडल टाउन	कुंवर करण सिंह / आकांक्षा ओला
तिलक नगर	पी एस बावा
तिमारपुर	कप्तान सिंह

पहली सूची में जिन सीटों पर नाम जारी किए जाएंगे, उनमें चांदनी चौक का नाम भी शामिल है।

प्रत्याशी घोषणा के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का भाजपा को इंतजार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे भाजपा नेताओं को इस बार मकर संक्रांति व लोहड़ी के त्योहार का बेसब्री से इंतजार है। मकर संक्रांति के दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची भी लोहड़ी या मकर संक्रांति के दिन आने की संभावना जताई जा रही है।

वर्ष 1993 से प्रत्येक विधानसभा चुनाव में उतरने वाले नेताओं से लेकर नए कार्यकर्ता भी इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पिछले कई माह से टिकट के दावेदार वरिष्ठ नेताओं के दरबार की परिक्रमा कर रहे थे। इसके साथ ही पार्टी कार्यालय से लेकर अपने क्षेत्र में पोस्टर व होर्डिंग्स लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इसे लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार को लेकर लिखित राय पार्टी हाईकमान के पास भेज दी है। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पेटी रखकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कराई थी। अब इसे पार्टी हाईकमान के पास खोला जाएगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक-दो दिनों में मतपेटी खोलकर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली जाएगी।

थरूर ने भाजपा व आप पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. शशि थरूर ने कहा है कि दिल्ली की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी के गोपनीय गठजोड़ को सबक सिखाएगी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अबकी बार दिल्ली में झाड़ू का झांसा-कमल ने फांसा... जनता के बीच खूब अच्छे से चल रहा है।

थरूर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 'दिल्ली के दिल की बात-कांग्रेस के साथ' संवाद कार्यक्रम के शुभारंभ करने आए थे। इसके तहत उन्होंने पार्टी का वॉट्सअप नंबर 9625777907 व मिस कॉल के लिए 1800121555558 नंबर भी जारी किया। साथ ही पार्टी की वेबसाइट एवं फेसबुक एकाउंट भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों से दिल्ली के दिल की बात कर रही है। हम चाहते हैं कि लोग हमें सुझाव दें।

उन्होंने कहा कि आज छात्रों पर आक्रमण हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था संकट में है। हमने सीएए का हमेशा विरोध किया। यह संविधान के खिलाफ है। गांधी, आंबेडकर, सरदार पटेल के विचारों के खिलाफ है। हम सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि संविधान के लिए विरोध कर रहे हैं। सभी लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। ये मुद्दा सभी वर्गों के

'दिल्ली के दिल की बात-कांग्रेस के साथ' का शुभारंभ करते (बाएं से) कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा, रोहन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, शशि थरूर, शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूजा बाहरी। जागरण

लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीर की आजादी का मतलब वहां की पाबंदियों को हटाने से है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि केजरीवाल चाहते हैं कि वे सीएए समर्थक और सीएए विरोधी दोनों के वोट ले लें। पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें कौन रोक रहा है घायलों से बात करने और मिलने से। वह शीला दीक्षित के बारे में ट्वीट करते थे कि वह हेल्पलेस सीएम हैं, लेकिन वे खुद आज हताश और असहाय मुख्यमंत्री लग रहे हैं।

थरूर व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में आम आदमी के सुझावों को शामिल करके उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि दिल्ली के सभी वर्गों तक पहुंचकर सीधा संवाद करेगी।

थरूर ने कहा कि वह एक-दो दिन में जामिया विवि का दौरा करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस दौरान उनके साथ सोशल मीडिया व डिजिटल कम्युनिकेशन विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहन गुप्ता, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी व रिसर्च विभाग की प्रमुख पूजा बाहरी भी मौजूद थीं।

कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन की बारीकियां सिखा रहे नड्डा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बूथ सम्मेलन के बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें चुनाव प्रबंधन की बारीकियां सिखा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को त्रिनगर, वजीरपुर, सदर, तिमारपुर एवं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ भाजपा ही ऐसा दल है, जिसके पास बड़ी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की समस्याएं हल करने के लिए आप सरकार ने काम नहीं किया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संदेश को घर-घर पहुंचाना है। भाजपा हमेशा सकारात्मकता की ओर चलती है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों तक, फिर आम आदमी पार्टी ने पांच सालों तक इस मामले को लेकर लोगों को गुमराह किया।

घोषणापत्र में सफाई को मुख्य मुद्दा बनाएगी आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में इस बार प्रदूषण, यमुना, परिवहन पर प्रमुख रूप से बात होगी। इस बार आप का घोषणा पत्र 70 प्वाइंट एजेंडा पर आधारित नहीं होगा। घोषणा पत्र में दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर सबसे अधिक फोकस होगा। हालांकि सफाई व्यवस्था नगर निगमों का काम है लेकिन आप का मानना है कि सफाई व्यवस्था बदतर होने से दिल्ली की छवि खराब होती है। इसलिए आप की सरकार इस बारे में भी कदम उठाएगी।

क्या-क्या होगा घोषणापत्र में

11 हजार नई बसें : दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बार चुनाव घोषणापत्र में 11 हजार नई बसें लाने का एजेंडा होगा। घोषणापत्र में इसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में 4,300 बसें सड़कों पर उतारे जाने की योजना बनाई थी। इनमें स्टैंडर्ड साइज की एक हजार बसें आनी हैं। 429 बसें आ चुकी हैं, शेष बसें भी चुनाव के बाद आएंगी। सूत्रों के अनुसार, आने वाले कार्यकाल में 11 हजार बसें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रहेगा।

प्रदूषण रोकने के लिए ठोस योजना : दिल्ली में प्रदूषण गंभीर समस्या बन गई है। सरकार ने अपने इस कार्यकाल में प्रदूषण रोकने के लिए बहुत कुछ किया है पर बहुत सफलता नहीं मिल सकी है। आम आदमी पार्टी अगले कार्यकाल में प्रदूषण को लेकर ठोस योजना लाएगी और बताएगी कि प्रदूषण पर किस तरह नियंत्रण पाया जाएगा।

यमुना की सफाई : यमुना की सफाई ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली में वर्षों से चला आ रहा है। अब तक कई सौ करोड़ रुपये यमुना की सफाई के लिए खर्च हो चुके हैं पर बहुत तेजी से काम नहीं हो सका है। इस समय दिल्ली में 950 एमजीडी पानी की आपूर्ति होती है। आप सरकार ने शोधित होने वाले सीवर के पानी को अपने प्रयासों से बढ़ाकर 450 एमसीडी किया है। शेष पानी यमुना में बगैर शोधित किए गिर रहा है जिससे यमुना साफ नहीं हो पा रही है। यमुना में गिरने वाला सीवर का पूरा पानी शोधित होगा।

दो विचारधाराओं के बीच है यह चुनाव : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह चुनाव दो पार्टियों नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ शिक्षा का बेहतर मॉडल पेश करने वाली आप सरकार है। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस हैं, जो गांधी-नेहरू को पढ़ाने और नहीं पढ़ाने पर ही विवाद करते रहे हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कराए गए उनके कार्यों के दम पर दिल्ली की जनता एक बार फिर केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने आप सरकार के शिक्षा के मॉडल की पड़ोसी राज्यों से तुलना करते हुए फिर से भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, भाजपा शिक्षा पर क्यों नहीं बोल रही है? उनके आरोपों का भी जवाब नहीं दे रही। भाजपा ने नगर निगमों या पड़ोसी राज्यों में कुछ कार्य कराए हैं,तो जनता के सामने लाए।

सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल है। जिसमें सभी सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ने बच्चों को अपने परिवारों से जोड़ा और देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान देने के लिए तैयार किया।

नेशनल कैपिटल

राइट्स तैयार करेगा देश के दूसरे सबसे बड़े हैलीपोर्ट की डीपीआर

कुंदन तिवारी, नोएडा

नोएडा में बनने वाले हैलीपोर्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) राइट्स की ओर से तैयार की जाएगी। कंपनी का चयन नोएडा प्राधिकरण की ओर से कर लिया गया है। इसकी पुष्टि नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कर दी है। दिल्ली के बाद यह हैलीपोर्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा हैलीपोर्ट होगा, जिसमें चार हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियां संचालन शुरू कर सकती हैं। फरवरी में आयोजित होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कंपनी पर मुहर लगा दी जाएगी। इसके बाद आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में डीपीआर को पास कर निर्माण कंपनी के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 में परियोजना को शामिल कर पिछली बोर्ड बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है। सेक्टर-151ए में 10 एकड़ जमीन चिह्नित हो चुकी है। यह जमीन 31 जनवरी तक ली जाएगी। इसके निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दे दिए हैं। परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर तैयार की गई है।

हैलीपोर्ट में आठ हैलीपेड बनाए जाएंगे। यह हैलीपोर्ट देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। यहां से किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए हैलीकाप्टर के लिए बुकिंग की जा सकेगी। देश में चार एजेंसियां है जो हैलीकाप्टर सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें पवन हंस और एसआइटीसी के अलावा दो अन्य शामिल हैं। इसमें पवन हंस का कार्यालय नोएडा सेक्टर-एक में स्थित है।

सेक्टर-151ए स्थित हैलीपोर्ट पर हैलीकॉप्टर उतरने के लिए आठ हेलीपेड बनाए जाएंगे। बुकिंग के लिए केबिन बनेंगे, पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। राइटस कंपनी की ओर से बनाई जाने वाली डीपीआर को आइआइटी से क्लीयरेंस के बाद राज्य सरकार के पास संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।

एसटीएफ करेगी गौरव चंदेल हत्याकांड की जांच : आइजी

जासं, नोएडा : गुरुग्राम से घर लौट रहे निजी कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर गौरव चंदेल की लूट के बाद हुई हत्या के मामले में अब एसटीएफ जांच करेगी। हत्याकांड के पांचवें दिन शुक्रवार को मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता सी मेश्राम व आइजी आलोक सिंह गौरव चंदेल के स्वजनों से मिलने पहुंचे। आइजी ने हत्याकांड का पर्दाफाश न होने पर स्थानीय पुलिस की फटकार लगाई और आगे की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से कराने का आश्वासन स्वजनों को दिया। दोनों अधिकारी दोपहर करीब 12 बजे गौरव के गौर सिटी स्थित घर 5 एवेन्यू पहुंचे। डेढ़ घंटे तक स्वजनों से बात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने कहा हत्याकांड के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। परिवार में आर्थिक परेशानी है। इस समस्या को भी आगे ले जाएंगे।

फर्जी दस्तावेज पर यात्रा करने की कोशिश पर दंपती गिरफ्तार

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने आइजीआइ एयरपोर्ट पर फर्जी दस्तावेज पर यात्रा करने वाले दंपती को टर्मिनल-3 के पास सुरक्षा जांच के दौरान गिरफ्तार किया। चेक-इन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों ने पासपोर्ट चेक-इन डेस्क पर छोड़ दिया था। पासपोर्ट की जांच करने में पता चला कि पासपोर्ट फमीदा और अजहर अजीज अतनानी के रूप में हुई। दोनों भारतीय हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट से टोरंटो जाने वाले थे। जांच में पता चला कि दोनों यात्री पहले से ही एयर एशिया की फ्लाइट में सवार हैं, जोकि मुंबई जा रही है। दोनों यात्रियों को एयरलाइंस से उतारा गया और गहनता से जांच की उनके पास से आधार कार्ड बरामद हुए, जिनमें दोनों की पहचान भाविका पटेल और उर्वेश पटेल के रूप में हुई और दोनों के आधार में अहमदाबाद गुजरात का पता लिखा था।

अतीत के आईने से

23 मार्च 1952 को पहली बार दिल्ली के विस चुनाव में छह निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे, जहां दो सीटें थी, रीडिंग रोड क्षेत्र से जनसंघ के अमीन चंद व कांग्रेस के प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती विधानसभा सदस्य घोषित किए गए थे

जब एक सीट से जीते कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवार

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

एक विधानसभा क्षेत्र और दो सदस्य निर्वाचित, वे भी दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों से! इस बात पर किसी को भी हैरानी हो सकती है। लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना भी आसान नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में यह संभव भी नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पहली बार दिल्ली विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव की। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह थी कि छह निर्वाचन क्षेत्रों से दो-दो उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें से एक सीट से कांग्रेस और जनसंघ दोनों के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए थे।

हालांकि बाद में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में ऐसा मौका दोबारा नहीं आया क्योंकि विधानसभा जल्दी ही भंग कर दी गई और दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था भी बदल गई। दरअसल, पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 के तहत मार्च 1952 में पहली बार दिल्ली विधानसभा अस्तित्व में आई। इसके लिए 23 मार्च 1952 को पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें 42 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 58.52 फीसद मतदान के साथ पांच लाख 21 हजार 766 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। छह निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे, जहां दो सीटें थीं। ये छह निर्वाचन क्षेत्र थे रीडिंग रोड, सीताराम बाजार तुर्कमान गेट, पहाड़ी धीरज बस्ती जुल्लाहान, रैगरपुरा देव नगर, नरेला व महरौली। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार रीडिंग रोड क्षेत्र से जनसंघ के अमीन चंद व कांग्रेस के प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती विधानसभा सदस्य घोषित किए गए। अन्य पांच क्षेत्रों से कांग्रेस के दो-दो उम्मीदवार जीते। इस तरह 42 विधानसभा क्षेत्रों के 48 सीटों पर उम्मीदवारों का चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस के 39 व जनसंघ के पांच व अन्य के पांच सदस्य विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे थे। इस तरह पहली विधानसभा का गठन हुआ। चौ. बह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री

दिल्ली विधानसभा। फाइल फोटो

बने। तब प्रशासनिक बागड़ोर मुख्य आयुक्त के हाथ में होती थी। मंत्री परिषद की भूमिका मुख्य आयुक्त के सलाहकार और जनता की नुमाइंदगी की थी। जनता क्या चाहती है, इसे विधानसभा के सदस्य मुख्य आयुक्त के समक्ष रखते थे। साथ ही विधानसभा को कानून बनाने का भी अधिकार था। इसके करीब चार साल सात माह बाद वर्ष 1956 में राज्य मान्यता अधिनियम लागू हुआ। तब दिल्ली को पार्ट सी राज्य की सूची से हटाकर केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस तरह विधानसभा भंग कर दी गई। सितंबर 1966 से दिल्ली के राजकाज में एक बार फिर बदलाव हुआ। इसके साथ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन हुआ और शासन की कमान उपराज्यपाल को मिली।

इसके बाद वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी (नेशनल कैपिटल टेरिटरी) घोषित कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम लागू किया गया और विधानसभा के गठन का फैसला लिया गया। लिहाजा, वर्ष 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली में पहली राज्य सरकार सत्ता में आई। उसके बाद अब तक छह बार चुनाव हो चुके हैं और अब सातवें विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है।

**अंग्रेजी हुकूमत के वक्

10 जनवरी, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए थे। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति के लिए एक संधि की जरूरत महसूस की जा रही थी। बाद में सोवियत संघ यानी रूस की पहल पर दोनों देशों के बीच यह करार हुआ।

ईडी ने कर्ज देने में भ्रष्टाचार का दर्ज किया था केस

प्रथम पृष्ठ से आगे

ईडी ने आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज के मामले में भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं के मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि विडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपये न्यूपावर रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि आइसीआइसीआइ बैंक से लोन मिलने के छह महीने बाद धूत ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के एक ट्रस्ट को नौ लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया था।

न्यूज गैलरी

रोहिंग्याओं के खिलाफ अर्जियों की सुनवाई मार्च में होगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को म्यांमार भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। करीब 40 हजार रोहिंग्या घुसपैठिए जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कुछ हस्तक्षेप याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। इनमें से एक हस्तक्षेप याचिका संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रोहिंग्याओं को एक साथ बड़ी संख्या में भेजने का केंद्र का फैसला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत अस्वीकार्य है। भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार हो और कानूनी राहत पाने का समान अवसर मिले। दो रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़े ज्यादातर विवाद इस मसले से जुड़े हैं। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के समूह ने गाया वंदे मातरम

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के एक समूह ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत-वंदे मातरम गाया। कोर्ट के लॉन में उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। इससे कुछ दिन पहले प्रशांत भूषण और कामिनी जायसवाल समेत अन्य वकीलों ने लोगों को संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाने के लिए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया। उल्लेखनीय है कि इस कानून के तहत पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। (एएनआइ)

रेलवे के अफसरों ने काडर विलय के खिलाफ उठाई आवाज

विरोध ▶ रेलमंत्री को सौंपे ज्ञापन, प्रति पीएमओ को भेजी

रेल मंत्रालय ने कहा, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, अफसरों से मांगे सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की आठ सेवाओं का विलय कर एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में तब्दील करने के सरकार के निर्णय का रेलवे के तमाम जोनों और डिविजनों ने मुखर विरोध किया है। तेरह जोनों से संबंधित तकरीबन 60 डिविजनों के सैकड़ों अधिकारियों ने इस संबंध में रेलमंत्री पीयूष गोयल को अपने हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन सौंपे हैं। अपने ज्ञापनों में अधिकारियों ने कहा है कि काडर विलय के एकतरफा निर्णय से भविष्य में ट्रेन संचालन की संरक्षा खतरे में पड़ेगी तथा दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।

कुल 209 पन्नों के ज्ञापनों की प्रतियां पीएमओ के अलावा कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी भेजी गई हैं। ज्ञापनों में 24 दिसंबर 2019 को सरकार की ओर से रेलवे की आठ सेवाओं को भंग कर एक नई आइआरएमएस सेवा बनाने के निर्णय की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि यद्यपि वह निर्णय 7 दिसंबर, 2019 को संपन्न हुई दो दिवसीय 'परिवर्तन संगोष्ठी' में बनी सहमति के आधार पर लिया गया है। चूंकि उस संगोष्ठी में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व नहीं था और विलय का निर्णय मुख्यतया महाप्रबंधकों की सहमति तथा इंजीनियरिंग सर्विस से जुड़े अधिकारियों के फायदे को ध्यान में रखकर लिया गया। इससे सिविल सर्विस के 2500 अधिकारियों का कैरियर प्रभावित होगा।

उत्तर रेलवे के अंबाला डिविजन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे के लगभग सभी महाप्रबंधक इंजीनियरिंग सर्विस के हैं। संगोष्ठी के लिए गठित सभी 12 समूहों का नेतृत्व महाप्रबंधक कर रहे थे और केवल उन्हें ही बोलने की अनुमति थी। महाप्रबंधकों ने गैर-इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित किसी अधिकारी को विरोधी विचार रखने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे में पूरी परामर्श प्रक्रिया को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है।

लगभग सभी ज्ञापनों में विलय के परिणामस्वरूप रेलवे की संरक्षा (सेफ्टी) को खतरे की बात कही गई है और विशेषज्ञता के अभाव में उपकरणों के विफल होने और दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया गया है। सूत्रों के अनुसार, ज्ञापन मिलने के बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने ये कहते हुए प्रतिनिधिमंडल की आशंकाओं को खारिज कर दिया वे लोग देशहित के बजाय व्यक्तिगत हितों को तरजीह दे रहे हैं। काडर मर्जर का निर्णय इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। रेलवे ऐसे अधिकारियों के बगैर भी चल सकती है।

इस संबंध में पूछे जाने पर रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अब इस तरह के ज्ञापनों से निर्णय बदलने वाला नहीं है। वैसे भी जहां कुछ अधिकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वहीं कइयों ने इसका समर्थन भी किया है। इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफीसर्स फेडरेशन ने काडर मर्जर के पक्ष में ज्ञापन दिया है। भारतीय रेल की ग्रुप-ए सेवा के 8400 अधिकारियों में से 3700 अधिकारी इस फेडरेशन के सदस्य हैं। इसके बावजूद मंत्रालय ने विरोधी अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से ईमेल पर अपने सुझाव भेजने को कहा गया था। अब तक 900 सुझाव प्राप्त भी हो चुके हैं। काडर विलय के तौर तरीके तय करते वक्त इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।'

आनंद विहार, बिजवासन स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रस्ताव मांगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्टेशन की नई इमारत और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाएगा निर्माण
- मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल तथा रेजीडेंशियल कांप्लेक्स भी बनाए जाएंगे

प्रतीकात्मक फोटो

रेलवे ने दिल्ली के दो स्टेशनों-आनंद विहार और बिजवासन के अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास एवं व्यावसायिक सुविधाओं के विकास के लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (आइआरएसडीसी) लि. की ओर से मांगे गए वित्तीय प्रस्तावों (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल-आरएफपी) के तहत चुनी जाने वाली कंपनियों को इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वहां उपलब्ध जमीन का मिश्रित उपयोग करने का मौका मिलेगा। अर्थात स्टेशन की नई इमारत और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ उन्हें वहां कमर्शियल स्पेस (मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल तथा रेजीडेंशियल कांप्लेक्स आदि) तैयार करने और उन्हें लीज पर उठाने का मौका भी मिलेगा। कंपनियों को उक्त जमीन 99 वर्ष की लीज पर दी जाएगी।

प्रस्ताव के तहत आनंद विहार स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के लिए 1.70 लाख वर्ग मीटर, बिजवासन में 4 लाख वर्ग मीटर तथा चंडीगढ़ स्टेशन पर 2.32 लाख वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होगी। रेलवे का इरादा इन स्टेशनों को पूरी तरह से बदलकर एयरपोर्ट जैसा लुक देने का है।

इससे पहले अभी हाल ही में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन ने डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन-आरएफक्यू) मांगा था। इसमें अमृतसर स्टेशन के विकास पर 375 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। आरएफक्यू प्रस्तावों के जरिये कंपनियों की तकनीकी पात्रता का आकलन किया जाता है। तकनीकी तौर पर सक्षम कंपनियों से बाद में आरएफपी प्रस्तावों के जरिये वित्तीय बोली लगाने को कहा जाता है। स्टेशनों के पुनर्विकास में रेलवे को सबसे ज्यादा लीज प्रीमियम देने वाली कंपनी का चयन किया जाता है।

स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत अभी तक देश में केवल दो रेलवे स्टेशनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज और गुजरात के गांधीनगर स्टेशन के ही पुनर्विकास का कार्य आगे बढ़ सका है। हबीबगंज के रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य जून, 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। जबकि गांधीनगर का कार्य इस वर्ष के अंत तक संपन्न होने की संभावना है।

भारत की चिंता, सिरदर्द न बन जाए श्रीलंका

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- सरकार बदलते ही तेजी से बढ़ने लगा चीन का असर
- अगले हफ्ते एक साथ कोलंबो पहुंच रहे हैं रूस व चीन के विदेश मंत्री
- हंबनटोटा पोर्ट के संयुक्त उपयोग की संभावना देख रहे हैं दोनों देश

श्रीलंका में चीन समर्थक गोताबाया राजपक्षे की सरकार बनने के साथ ही भारत को जो आशंका थी वह सही साबित होती दिख रही है। चुनाव जीतने के बाद राजपक्षे ने भले ही भारत की यात्रा की हो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे नववर्ष पर बात भी की लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की नई सरकार चीन के हितों के अनुरूप काम शुरू कर चुकी है। ऐसे में अगले हफ्ते वहां एक साथ चीन व रूस के विदेश मंत्री के पहुंचने पर भारत के भीतर काफी उत्सुकता है। यह पहला मौका होगा जब पड़ोसी देश में दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन वहां हंबनटोटा पोर्ट के संयुक्त इस्तेमाल की संभावना तलाश रहे हैं।

अभी तक जो सूचना आ रही है चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कुछ ही घंटे के लिए कोलंबो में रहेंगे, लेकिन दोनों श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्द्धने से मिलेंगे। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, एक साथ होने वाले इस दौरे को फिलहाल ईरान व अमेरिका के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर सूचनाएं आ रही हैं, वे कहीं से भी भारत के लिए सुखद नहीं है। हाल ही में रूस के एक युद्ध पोत ने हंबनटोटा की सुविधाओं का इस्तेमाल किया है और श्रीलंका के कुछ मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा है कि वह हंबनटोटा को लेकर चीन को और ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में हैं। ऐसे में अगले हफ्ते एक ही दिन श्रीलंका के विदेश मंत्री गुणावर्द्धने के साथ रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की होने वाली मुलाकात के बाद क्या बयान आते हैं, इसको लेकर भारत की दिलचस्पी रहेगी।

यह बताने की जरूरत नहीं कि हंबनटोटा पोर्ट की लीज चीन को मिली हुई है। चीन यहां बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाना चाहता है। श्रीलंका की पूर्व सिरीसेना सरकार ने उस पर फैसला टाल दिया था लेकिन नई सरकार उसे मंजूरी दे सकती है। दिसंबर, 2019 में भारत से लौटने के बाद राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा था कि हंबनटोटा पोर्ट पर चीन से समझौते की समीक्षा नहीं की जाएगी। मताला एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि इसे उनकी सरकार अकेले ही विकसित करेगी। सनद रहे कि सिरीसेना सरकार के कार्यकाल में भारत-श्रीलंका के बीच इस पोर्ट को लेकर बातचीत चल रही थी।

चीन-पाक सैन्य अभ्यास को देख अरब सागर में आइएनएस विक्रमादित्य तैनात

- इस कदम से भारत ने दोनों पड़ोसी देशों के दिए स्पष्ट संकेत

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन और पाकिस्तान के नौ दिनी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के मद्देनजर भारत ने अरब सागर में विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य को तैनात किया है। भारत के इस कदम का मकसद दोनों पड़ोसी देशों को स्पष्ट संकेत देना है।

सैन्य सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में जब विक्रमादित्य को इस सामरिक मिशन पर तैनात किया गया था तब इस पर नौसेना मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी भी सवार थे। चीन-पाक ने सोमवार से ही उत्तरी अरब सागर में 'सी गार्जियन' के नाम से संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इसमें पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट समेत कई युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विक्रमादित्य को सामरिक उद्देश्य से अरब सागर में भेजा गया है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया।

वहीं, नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि नौसेना उपाध्यक्ष एमएस पवार ने अरब सागर में आइएनएस विक्रमादित्य के ऑपरेशंस की समीक्षा की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह युद्धपोत अपने नाम के अनुरूप युद्ध में हमेशा विजेता रहेगा। स्मरण रहे कि सितंबर, 2019 में भारतीय नौसेना ने देश के विशेष आर्थिक जोन से चीनी सेना के एक युद्धपोत को खदेड़ा था और चेतावनी दी थी कि ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

आइएनएस विक्रमादित्य फाइल फोटो

बता दें कि रूस निर्मित आइएनएस विक्रमादित्य को 2013 में नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन वजनी यह पोत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक पोतों में शुमार है और इसे तैरता युद्धक्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 284 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है जो किसी 20 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर 30 युद्धक विमान तैनात हो सकते हैं। दरअसल, चीन उत्तरी अरब सागर में लगातार उपस्थिति बढ़ा रहा है और पाक में ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है।

अब कहीं से भी कर सकते हैं साइबर क्राइम की रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विशेष पोर्टल देश को समर्पित, इस पर दर्ज शिकायतों पर राज्य करेंगे कार्रवाई

अब आप देश में कहीं भी हुए साइबर क्राइम की रिपोर्ट एक पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसी खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया।

गृह मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लांच कर दिया गया है। एक बार इस पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संबंधित जांच एजेंसी को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाएगा और वह इसकी जांच शुरू कर देगी। देश को यह पोर्टल समर्पित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देशभर के 700 पुलिस जिले और 3,900 से अधिक थाने इस पोर्टल से जोड़े जा चुके हैं। इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा जिससे साइबर अपराधों की जांच और अपराधियों को सजा दिलाने में आसानी होगी। इस पोर्टल में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर किसी का पीछा करना या परेशान करने जैसे मामलों का विशेष ध्यान रखा गया है। भविष्य में इस पोर्टल पर चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से बचने के लिए ऑनलाइन सलाह ले सकेगा या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया की जानकारी ले सकेगा।

वहीं, दिल्ली में बना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए समेकित रूप से काम करेगा। अभी तक 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर खोलने के लिए सहमति दे चुके हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार व विधि आयोग को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार व विधि आयोग को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने का आदेश देने की मांग वाली याचिका गत वर्ष तीन सितंबर को खारिज कर दी थी। ध्यान रहे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में जनसंख्या के प्रति सचेत कर चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह नोटिस भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। उपाध्याय ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शुक्रवार को अपनी याचिका पर खुद बहस करते हुए उपाध्याय ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट बहुत गंभीर मुद्दा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरुआत में उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी।

उन्होंने कहा कि संविधान समीक्षा आयोग ने वर्ष 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसके 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बना। वर्ष 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इसे तीन जनवरी 1977 को लागू किया गया। इसके तहत 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया, लेकिन सरकारों ने आज तक कानून नहीं बनाया।

उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि देश में 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और 20 फीसद लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है। यानी 25 करोड़ लोग बिना आधार के हैं। इसके अलावा लोग गैरकानूनी रूप से भी देश में रह रहे हैं। यानी देश की कुल जनसंख्या 125 करोड़ की बजाय 150 करोड़ से ज्यादा है। याचिका में कहा गया है कि हमारे देश में दुनिया की मात्र दो फीसद जमीन है। पीने योग्य पानी मात्र चार फीसद है, जबकि जनसंख्या 20 फीसद है। जल, जंगल व जमीन, रोटी, कपड़ा व मकान, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण तथा बढ़ते अपराध जैसी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की खराब स्थिति का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। याचिका में आग्रह किया गया है कि संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने संबंधी सरकार को निर्देश दिया जाए।

मनी लांड्रिंग मामले में फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ आरोपपत्र

जासं, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से जुड़े घोटाले का आरोपपत्र शुक्रवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में दाखिल किया। इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह के अलावा रेलिगेयर के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को भी आरोपित बनाया गया है। तीनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया गया है। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ समन जारी कर 20 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।

शिविंदर व मलविंदर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने रेलिगेयर से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। शिविंदर सिंह और मलविंदर रेलिगेयर फिनवेस्ट के भी पूर्व प्रमोटर हैं। इन पर अपने पद पर रहते हुए कंपनी में करीब एक हजार करोड़ रुपये के फंड का हेरफेर करने के आरोप हैं।

सीडीएस के नवसृजित सैन्य मामलों के विभाग में होंगे कुल 40 सचिव

02 संयुक्त सचिव कामकाज में करेंगे सीडीएस की मदद

13 उपसचिव और 25 अवर सचिव भी देंगे अपनी सेवाएं

17 एकल सैन्य कमान हैं देश में, अंडमान और निकोबार में ही एक संयुक्त कमांड

बिपिन रावत फाइल फोटो

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के बाद सरकार ने शुक्रवार को उनके नेतृत्व वाले नवसृजित सैन्य मामलों के विभाग के औपचारिक ढांचे को मंजूरी दे दी। इस विभाग में कुल 40 सचिव होंगे।

सैन्य मामलों के विभाग में दो संयुक्त सचिव, 13 उपसचिव और 25 अवर सचिव होंगे जो सीडीएस को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मदद करेंगे। विभाग में सिविल के साथ-साथ सैन्य अधिकारी भी होंगे। जनरल रावत तीनों सेनाओं को सही मायने में योजना, खरीद, रसद, रणनीति और प्रशिक्षण के मामले में एकीकृत बनाएंगे। वह सरकार के इकलौते सैन्य सलाहकार होंगे, साथ ही साथ वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। यद्यपि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का अपनी-अपनी सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होगा, लेकिन पदानुक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) स्पष्ट रूप से सभी समान अधिकारियों में प्रथम होंगे। देश में इस समय 17 एकल कमांड्स हैं और कोई भी सैन्य बल अपनी कमांड नहीं छोड़ना चाहता। भारत में अभी तक सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही एक संयुक्त कमांड है।

सैन्य मामलों का विभाग रक्षा मंत्रालय का पांचवा विभाग होगा। वर्तमान में मंत्रालय में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग हैं। सैन्य मामलों का विभाग सशस्त्र बलों, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, टेरीटोरियल आर्मी, सेना के लिए खरीद (पूंजीगत और संयुक्त खरीद को छोड़कर), सेनाओं की संयुक्त योजना और एकीकरण के जरिये उनकी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम देखेगा। यह विभाग सेनाओं में स्वदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगा क्योंकि वर्तमान में भारतीय सेनाएं काफी हद तक आयातित सैन्य उपकरणों और हथियारों पर निर्भर हैं।

एनसीआरबी के आंकड़े

आधी से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18-30 साल, 27.8 फीसद की आयु 18 वर्ष से भी कम रही

हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग, 100 में से 94 अपराधी जानकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2018 में महिलाओं के साथ हुए अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस वर्ष हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग रही, जबकि आधी से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18-30 वर्ष के बीच रही। यही नहीं, 94 फीसद मामलों में अपराधी जानकार ही रहा।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में दुष्कर्म के कुल 33,356 मामले दर्ज किए गए, जिनमें पीड़िताओं की संख्या 33,977 रही। इनमें 72.2 फीसद पीड़िताएं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की थीं, जबकि 27.8 फीसद की उम्र इससे कम रही। 51.9 फीसद दुष्कर्म पीड़िताओं (17,636) की उम्र 18-30 साल रही, जबकि 18 फीसद पीड़िताएं (6,108) 30-45 वर्ष की रहीं। 2.1 फीसद पीड़िताओं (727) की उम्र 45-60 वर्ष के बीच रही, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की 0.2 फीसद (73) महिलाएं भी दुष्कर्म का शिकार बनीं। इसी प्रकार 14.1 फीसद पीड़िताओं (4,779) की उम्र 16-18, जबकि 10.6 फीसद (3,616) की उम्र 12-16 वर्ष के बीच रही। 6-12 वर्ष की 2.2 फीसद (757) व छह साल से कम उम्र की 0.8 फीसद (281) बालिकाएं भी दुष्कर्म की शिकार हुईं।

मप्र में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा, उप्र तीसरे स्थान पर : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में राजस्थान में नाबालिगों से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा (5,433) मामले दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान (4,335) दूसरे व उत्तर प्रदेश (3,946) तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र में इस प्रकार के 2,142, छत्तीसगढ़ में 2,091, केरल में 1,945, असम में 1,648, दिल्ली में 1,215, हरियाणा में 1,296, झारखंड में 1,090 व बंगाल में 1,069 मामले दर्ज किए गए।

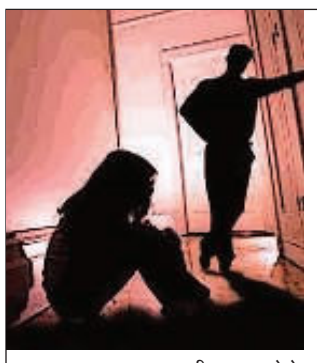

प्रतीकात्मक फोटो

31,320 मामलों में जानकारों ने ही किया विश्वासघात

दर्ज दुष्कर्म के 33,356 मामलों में से 31,320 में जानकारों ने ही विश्वासघात किया। 15,972 मामलों में अपराधी पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी, नियोक्ता या अन्य जानकार पाए गए, जबकि 12,568 मामलों में दोस्त, ऑनलाइन फ्रेंड या लिव-इन पार्टनर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 2,870 मामले ऐसे भी थे, जिनमें आरोपित परिवार का ही सदस्य रहा। सिर्फ 2,036 मामलों में ही अपराधी अज्ञात रहा।

बंद पड़े हैं महिलाओं की मदद के लिए खोले गए 133 वन स्टॉप सेंटर्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश भर में स्थापित 728 वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) में से सिर्फ 595 ही काम कर रहे हैं। यानी, 133 केंद्र बंद पड़े हैं। इन केंद्रों को हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए स्थापित गया था। हालांकि, वर्ष 2018 के दौरान इन केंद्रों ने 2.27 लाख महिलाओं की मदद भी की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित 1.10 लाख महिलाओं ने ओएससी की मदद ली। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 16 हजार, जबकि मध्य प्रदेश में 13 हजार महिलाओं को ओएससी की मदद हासिल हुई। इनमें ज्यादातर महिलाएं दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की पीड़ित थीं। इन्हें ओएससी के जरिये कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, ओएससी दुष्कर्म, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों की पीड़िताओं को कानूनी, मेडिकल, काउंसलिंग और आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

13 से 22 जनवरी तक होगी 13वें चरण के चुनावी बांड की बिक्री। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये इसकी बिक्री करेगी। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 11 जनवरी 2020

मरांडी की घर वापसी तय, शुभ मुहूर्त का इंतजार

सियासत ▶ 15 जनवरी या उसके बाद कभी भी भाजपा में शामिल होंगे बाबूलाल, शीर्ष नेताओं के संपर्क में

झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की मिल सकती है कमान

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी लगभग तय मानी जा रही है, इंतजार बस शुभ मुहूर्त का है, जो खरमास के बाद से शुरू हो रहा है। बाबूलाल फिलहाल राज्य के बाहर हैं और भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि वे कहां हैं इसकी पुष्टि उनके करीबी भी नहीं कर पा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार बाबूलाल मरांडी 15 जनवरी को विधिवत भाजपा की सदस्यता दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में लेंगे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप सकता है। भाजपा ने अब तक यह पद रिक्त रखा है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि खरमास के बाद ही भाजपा में विधायक दल का नेता का चयन किया जाएगा। हालांकि, उनके समक्ष प्रदेश अध्यक्ष जैसे अन्य विकल्प भी खुले रहेंगे।

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम ने भाजपा और बाबूलाल को इस कदर तोड़ दिया है कि उनके पास अब एक-दूसरे से जुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने 5 जनवरी को झाविमो की कार्यसमिति को भंग कर दिया था, तभी से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों ने ज्यादा जोर पकड़ लिया है। हालांकि बाबूलाल की पार्टी में वापसी को लेकर प्रदेश भाजपा में सन्नाटा है। इस मामले से सभी खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने ऐसी किसी भी जानकारी ने इन्कार किया, लेकिन इतना अवश्य कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी जैसे नेता भाजपा में वापस आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए।

बाबूलाल मरांडी। फाइल

चुनाव से पूर्व ही तैयार हो गया था मिलन का प्लॉट

बाबूलाल की घर वापसी का प्लॉट विधानसभा चुनाव से पूर्व ही तैयार हो गया था। तब तक दोनों दलों को बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। यह माना जा रहा है कि भाजपा बहुमत से जितना पीछे रहेगी उसकी भरपाई बाबूलाल की पार्टी के विलय से पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाजपा को चुनाव में महज 25 और झाविमो को तीन सीटें ही हासिल हुईं।

क्या बन रहे भावी समीकरण

झाविमो की कार्यसमिति भंग हो चुकी है ऐसे में अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हो गए हैं। वे चाहें तो अपनी पूरी पार्टी का विलय भाजपा में कर सकते हैं।

हालांकि, ऐसी स्थिति में भी उनके विधायकों के पास अलग राह पकड़ने का विकल्प खुला रहेगा। पार्टी में बाबूलाल के अलावा प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मिलाकर कुल तीन विधायक हैं। यदि शेष दोनों विधायक एक साथ किसी अन्य दल में शामिल होना चाहें या अन्य दल बनाना चाहें तो बहुमत इसकी इजाजत देता है।

अगर बाबूलाल भाजपा में अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो भाजपा उन्हें विधायक दल का नेता घोषित कर सकती है। ऐसी स्थिति में भाजपा के पास सत्तापक्ष को चुनौती देने के लिए एक मजबूत आदिवासी चेहरा होगा।

आदिवासी नेता की भरपाई करना चाहती है भाजपा

राज्य ब्यूरो, रांची : कभी विपरीत परिस्थितियों में भाजपा को अलविदा कहने वाले बाबूलाल मरांडी अब एक बार फिर झारखंड में भाजपा के तारणहार बनेंगे। इसकी पूरी तैयारी या यूं कहें कि पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। दरअसल झारखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में पिटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुटा है। इसके लिए उसे बाबूलाल मरांडी से बेहतर कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके तत्काल बाद बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। इस मिशन में कई विश्वस्त नेताओं को लगाया गया। हालांकि, बाबूलाल मरांडी की मुलाकात भाजपा के किसी नेता से नहीं हुई है, लेकिन यह तय हो गया है कि वे भाजपा में शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी को भाजपा में शामिल करने के पीछे भाजपा का व्यापक उद्देश्य भी है। दरअसल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमोनीत गठबंधन की शानदार जीत ने भाजपा को चिंतित कर दिया है। हेमंत सोरेन का झारखंड के बाहर आदिवासी चेहरा के तौर पर विकसित होना भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जाहिर है वे कांग्रेस का साथ देंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा को एक मजबूत और स्वीकार्य चेहरे की दरकार थी जो बाबूलाल मरांडी के तौर पर उसे वापस मिलेगा। दरअसल झारखंड में जब बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक उदय हुआ तो शुरुआत में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को हराने में कामयाबी पाई थी। इसी की बदौलत वे राष्ट्रीय राजनीति में उभरे। उन्हें बिहार से कटकर बने झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें भाजपा छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। बाबूलाल मरांडी कभी झारखंड की राजनीति में अप्रासंगिक नहीं हुए। 2014 के चुनाव में उन्होंने विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने में कामयाबी पाई, लेकिन भाजपा ने उनके छह विधायकों तोड़ लिया। इससे भाजपा से उनकी दूरी भी अवश्य बनी।

संपूर्णानंद संस्कृत विवि के छात्रसंघ में एनएसयूआइ ने जमाया कब्जा

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▶ एबीवीपी का पैनल दरकिनार, प्रियंका ने जीत पर किया ट्वीट

वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के आए नतीजों में इस बार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) का पूरा पैनल जीत गया है। इसे लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। सत्र 2018-19 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और हरिश्चंद्र पीजी कालेज के छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का कब्जा था। संस्कृत विश्वविद्यालय में तो विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल ही जीता था।

वहीं इस बार संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के चुनाव में राछासं ने बाजी पलटने में कामयाब रहा। संस्कृत विवि से विद्यार्थी परिषद का पूरी तरह सफाया हो गया। एनएसयूआइ के शिवम शुक्ल-अध्यक्ष, चंदन कुमार मिश्र-उपाध्यक्ष, अवनीश मिश्र- महामंत्री व रजनीकांत दुबे-पुस्तकालय मंत्री निर्वाचित हुए हैं। दिसंबर में हुए काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ चुनाव में भी एनएसयूआइ महामंत्री पद जीत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा। विद्यापीठ के छात्रसंघ चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद को महज एक पद उपाध्यक्ष का ही हाथ लगा।

प्रियंका ने किया ट्वीट : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआइ की शानदार सफलता पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर खुशी व्यक्त की। कहा कि मुझे अपने छात्र साथियों पर गर्व है।

कम होती गई एबीवीपी की धार

केंद्र व राज्य में भाजपा के सत्ता में आने से विद्यार्थी परिषद ने छात्रहितों के तमाम मुद्दों पर आंदोलन की धार कमजोर कर दी। पिछली बार सभी विश्वविद्यालयों में शुल्क बढ़ाया गया, लेकिन परिषद के कार्यकर्ता ज्ञापन तक की सीमित रह गए। जबकि अन्य संगठनों ने इस मुद्दे पर छात्रों के साथ आंदोलन किया। चुनाव में इसका खामियाजा विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को भुगतना पड़ा। एनएसयूआइ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवम शुक्ल ने कहा कि हमने चुनाव विवि के पठन-पाठन को दुरुस्त करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, यहां शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं जिन्हें अविलंब भरने की हमारी मांग है। एबीवीपी के पैनल से अध्यक्ष पद के पराजित हर्षित पांडेय संगठन ने अंतिम क्षण में प्रत्याशियों का चयन किया जिसके चलते हार का मुंह देखना पड़ा। आठ जनवरी को चुनाव था और छह जनवरी को दावेदारी तय की गई। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र जगदंबा मिश्र का कहना है कि पिछली बार एबीवीपी के जीते प्रत्याशी सालभर परिसर से कटे रहे।

पंजाब में महंगी बिजली पर आप का धरना, पुलिस का लाठीचार्ज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब में महंगी बिजली और प्राइवेट थर्मल कंपनियों से किए समझौते रद करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ पुलिस ने एमएलए होस्टल के बाहर बेरीकेड लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार की।

आप विधायक दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आप वर्करों व पुलिस के बीच करीब आधा घंटा जोरआजमाइश हुई। पुलिस लाठीचार्ज व पानी की बौछार से लहरागागा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके जसबीर सिंह कुदनी और बसीपठाना से संतोख सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई। वहीं करीब दो दर्जन वर्कर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने सांसद भगवंत मान, दस विधायकों समेत करीब 120 वर्करों को हिरासत में ले लिया। हालांकि वह विधायक रुपिंदर कौर रूबी के साथ सीएम कोठी के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए।

भगवंत मान बोले, कैप्टन व सुखबीर मिले हुए हैं : सांसद भगवंत मान ने कहा कि बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल आपस में मिले हुए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार सस्ती बिजली दे रही है, जबकि पंजाब में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से मिलीभगत के कारण कैप्टन सरकार समझौते का रिव्यू नहीं करवा रही है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, रेत माफिया और केबल माफिया के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, प्रिंसिपल बुद्ध राम, मीत हेयर, विधायक सरबजीत कौर माणूके व मास्टर बलदेव सिंह ने भी धरने को संबोधित किया।

आप के मीडिया इंचार्ज मनजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि दो दर्जन से अधिक वालंटियरों को चोटें लगी हैं। जसबीर सिंह व संतोख सिंह की आंख में गंभीर चोट लगी है जोकि अस्पताल में दाखिल हैं।

छत्तीसगढ़ के महापौर चुनावों में कांग्रेस ने जीता मैदान, भाजपा का सूपड़ा साफ

नईदुनिया, रायपुर

▶ सभी दस सीटें कांग्रेस ने जीतीं, बहुमत के करीब रहते कोरबा में हारी

▶ चुनाव से पहले चार-चार निगमों में काबिज थी कांग्रेस-भाजपा, दो महापौर थे निर्दलीय

छत्तीगसढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने दम दिखाया और दस के दस नगर निगमों में अपना महापौर और सभापति बनाने में सफल रही। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जब सभी नगर निगम में महापौर और सभापति एक ही पार्टी के बने हों।

कोरबा में कांग्रेस उम्मीदवार राजकिशोर ने भाजपा की प्रत्याशी ऋतु चौरसिया को महज एक वोट से हराया। वहीं, सभापति का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी श्यामसुंदर सोनी ने पांच वोट से जीता। 67 वार्ड वाले कोरबा नगर निगम में भाजपा के 31 पार्षद, कांग्रेस के 26 व दस अन्य चुनकर आए थे। भाजपा बहुमत के करीब थी, लेकिन कोरबा नगर निगम में आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दूसरी बार कांग्रेस ने कोरबा के महापौर व सभापति के पद पर कब्जा जमाया है। भाजपा को छोड़ अन्य दलों के वोट हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रही। जिन दस निगमों में चुनाव हुआ वहां पहले चार-चार सीटों पर भाजपा-कांग्रेस और दो में निर्दलीय काबिज थे।

एक में क्रास वोटिंग, दो में मैदान में उतरी ही नहीं भाजपा: छत्तीसगढ़ के दस नगर निगम में पहली बार जनता के बजाय पार्षदों के वोट से महापौर चुनने के दौरान भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विधानसभा राजनांदगांव के नगर निगम में भाजपा से एक पार्षद अधिक कांग्रेस के पास थे, लेकिन जब मतदान हुआ तो भाजपा के महापौर उम्मीदवार को अपनी पार्टी के एक पार्षद का साथ नहीं मिला। कोरबा में भाजपा बढ़त में थी, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस के बेहतर चुनावी मैनेजमेंट ने जीत दिलाई। हालांकि, यहां भाजपा को अपने पार्षदों के साथ दो अन्य पार्षदों के भी वोट मिले। बिलासपुर और चिरमिरी नगर निगम में भाजपा चुनाव मैदान में ही नहीं उतर पाई, जबकि रायपुर, धमतरी, जगदलपुर, दुर्ग, रायगढ़ और अंबिकापुर में कांग्रेस को बढ़त थी, जिससे वह अपना महापौर बनवाने में सफल रही।

नपा उपाध्यक्ष समेत भाजपा के दस पार्षदों ने दिया इस्तीफा: छह जनवरी को क्रॉस वोटिंग में बेमेतरा नगर पालिका की सत्ता गंवाने के बाद शुक्रवार को नगरपालिका उपाध्यक्ष पंचू साहू सहित भाजपा के 10 पार्षदों ने बेमेतरा कलेक्टर को इस्तीफा सौंप दिया। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने कहा है कि इस्तीफे पर धारा-40 के तहत सुनवाई की जाएगी। बता दें कि चुनाव वाले दिन वोटिंग के तत्काल बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा के 12 पार्षदों की बैठक कर इस्तीफा लिखवाया था। भाजपा पार्षदों में किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया था कि क्रास वोटिंग में वे शामिल रहे। अब पार्टी ने पार्षदों से इस्तीफा कलेक्टर को भिजवाए हैं।

मोमेंटम झारखंड की जांच पर बोले रघुवर, सांच को आंच क्या

जागरण संवाददाता, रांची

▶ कहा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, पूरा कार्यक्रम पारदर्शी ढंग से हुआ

▶ दी चुनौती, सरकार जब चाहे उनकी जांच करा लें

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मोमेंटम झारखंड से राज्य का नाम विश्व पटल पर ऊंचा हुआ है। इसके माध्यम से देश-दुनिया के निवेशकों ने यह जाना कि झारखंड निवेश के लिए कितना अनुकूल है। यहां सरकार, संसाधन और आधारभूत संरचना की स्थिति अच्छी है।

शुक्रवार को जस्टिस एलपीएन शाहदेव की पुण्यतिथि के मौके पर रघुवर ने मीडिया से स्पष्ट कहा कि मोमेंटम झारखंड में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरा कार्यक्रम पारदर्शी ढंग से हुआ। इस आयोजन के बाद कई कंपनियों ने झारखंड में निवेश किया है। इससे बड़ी संख्या में झारखंड के बच्चे-बच्चियों को रोजगार मिला है। शिकायत कोई भी किसी की कर सकता है। अब सरकार उनकी है, जब चाहें, जैसे चाहें, जांच करा लें। सांच को आंच क्या?

बता दें कि मोमेंटम झारखंड के आयोजन के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री समेत आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव संजय कुमार, उद्योग निदेशक के रविकुमार, सीआइआइ के राहुल सिंह और तत्कालीन ओएसडी सुनील कुमार वर्णवाल शामिल हैं।

रघुवर दास। फाइल

मनोहर बोले, विज्ञान भी नहीं देता सगोत्रीय विवाह की इजाजत

जागरण संवाददाता, पंचकूला : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सगोत्र विवाह पर रोक के मुद्दे पर खाप पंचायतों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी स्पष्ट हो चुका है कि सगोत्र विवाह नहीं करना चाहिए। उसी तरह भाईचारा वाले गांवों में (आसपास के गांव) विवाह नहीं करना चाहिए। यह सामाजिक मान्यता है। हम इस पर चलेंगे तो भाईचारा बना रहेगा, खराब नहीं होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को 'महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा' विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात में महिलाओं एवं युवतियों को बहन और पुरुषों को भाई बोला जाता है। इस प्रकार का वातावरण यदि बनाए रखेंगे, तो किसी के मन कुविचार नहीं आएंगे और अपराध नहीं होंगे।

मालूम हो कि हरियाणा में सगोत्रीय विवाह बड़ा मुद्दा रहा है। एक ही गोत्र में विवाह को सगोत्र विवाह माना गया है। इसका निषेध चिकित्सा विज्ञान की सेपरेशन ऑफ जींस की मान्यता पर आधारित है।

ट्रस्ट गठन से पहले नृत्य गोपालदास को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

जागरण संवाददाता, अयोध्या

▶ श्रीरामजन्मभूमि न्यास अध्यक्ष की हिफाजत को लेकर सरकार ने उठाया कदम, एसएसपी को भेजी सूचना

राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट गठन से पहले श्रीरामजन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इससे उनके इर्द-गिर्द सुरक्षा घेरा और कड़ा हो जाएगा। उनके आश्रम की सुरक्षा और हमराह के लिए अलग-अलग सुरक्षा दस्ते होंगे। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करना यह दर्शाता है कि सरकार महंत नृत्यगोपालदास की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। बता दें जेड श्रेणी में 22 जवानों का सुरक्षा कवच होता है। इसमें एनएसजी के चार या पांच कमांडो और पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर निर्माण के लिए 9 फरवरी तक ट्रस्ट गठन कर लेने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। इससे पहले 20 जनवरी को प्रयागराज में विहिप के मार्गदर्शक मंडल के संतों की बैठक है, जिसमें महंत नृत्यगोपालदास का शामिल होना तय माना जा रहा है। ट्रस्ट गठन में संतों की भूमिका और मंदिर निर्माण दोनों ही मुद्दों को लेकर यह बैठक काफी अहम है। संभावना है कि ट्रस्ट गठन में महंत नृत्यगोपालदास की अहम भूमिका हो सकती है, जिससे पहले सरकार उन्हें पुख्ता सुरक्षा से लैस करना चाहती है। सुरक्षा बढ़ाए जाने की सूचना एसएसपी आशीष तिवारी को शासन से प्राप्त हो चुकी है। महंत नृत्यगोपालदास की सुरक्षा अभी वाई श्रेणी की है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान तैनात हैं।

महंत नृत्यगोपालदास। फाइल

महबूबा का बढ़ा संकट, छह और नेताओं ने छोड़ी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ महबूबा को किनारे कर आगे बढ़ने को तैयार पार्टी के दिग्गज

▶ तीसरे मोर्चे की छतरी के नीचे एक साथ आ सकते हैं तमाम नेता

कश्मीर में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का संकट बढ़ रहा है। पार्टी के नौ वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन के एक दिन बाद ही शुक्रवार को पूर्व विधायक यावर मीर और पांच अन्य नेताओं ने पीडीपी छोड़ने का एलान कर दिया। इस्तीफे और निष्कासन के इस सिलसिले से साफ है कि महबूबा मुफ्ती को किनारे कर पार्टी के बड़े नेता नई परिस्थितियों में आगे बढ़ने को तैयार हैं।

खास बात है कि दो दिन पहले पार्टी के कई पूर्व विधायकों ने महबूबा के एजेंडे से किनारा कर 370 के बाद के हालात में आगे बढ़ने का एलान कर दिया। यह नेता उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से भी मिले और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे और विकास की मांग उठाई। गुरुवार को कई बड़े नेताओं ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात कर हालात सामान्य होने का दावा किया। उधर पीडीपी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग ने सीधा महबूबा को निशाने पर ले लिया है।

इस पर पीडीपी ने आठ पूर्व विधायकों दिलावर मीर, नूर मोहम्मद शेख, अब्दुल रहीम राथर, रफी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पाडर, जावेद हसन बेग, राजा मंजूर, चौधरी कमर हुसैन और एक पूर्व एमएलसी जफर मनहास को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिलावर मीर पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में एक हैं और वर्ष 2002 में मुफ्ती सरकार में मंत्री थे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पार्टी बेग पर कार्रवाई का साहस नहीं जुटा पाई।

इन नेताओं ने भी दिया इस्तीफा : यावर मीर के इस्तीफे के कुछ ही देर बाद पीडीपी की युवा इकाई के नेता शौकत गयूर अंद्राबी, नजीर अहमद खान, डॉ. समी उल्लाह, मुंतजिर मोहिउद्दीन और शाह मोहम्मद तांत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है।

महबूबा मुफ्ती। फाइल

पीडीपी में कुछ लोगों को कश्मीरी अवाम और संगठन की चिंता नहीं हैं। वह पीडीपी को लोकतांत्रिक तरीके से आम कश्मीरी अवाम की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाना चाहते हैं।

- यावर मीर, पूर्व पीडीपी विधायक

मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी तो पार्टी अध्यक्ष की नीतियों के खिलाफ बोला है, उन्होंने भी स्टेटहुड की मांग की है। उनके खिलाफ कोई नही बोला। वह पार्टी संरक्षक हैं, क्या हमारे निष्कासन पर उनसे सहमति ली गई है।

-अब्दुल मजीद पाडर, पूर्व विधायक एवं पीडीपी से निष्कासित नेता

जदयू के दही-चूड़ा भोज में होगा दिग्गजों का जुटान

राज्य ब्यूरो, पटना : जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह 15 जनवरी को दही-चूड़ा का भोज देंगे। लंबी अवधि से वह पटना में मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन करते रहे हैं। कुछ दिनों तक राजधानी स्थित पटना क्लब में यह आयोजन हुआ। पिछली बार की तरह इस बार यह आयोजन वशिष्ठ नारायण सिंह के हार्डिंग रोड स्थित आवास पर होगा।

जदयू के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की काफी उपस्थिति रहती है। दूसरे दल के नेताओं को भी आमंत्रित करने का भी चलन रहा है। दही-चूड़ा भोज के आयोजन में सब्जियों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। वशिष्ठ नारायण सिंह के आयोजन में आलू दम के साथ कद्दू की सब्जी, तिलकुट और खाजा परोसा जाता रहा है।

खुलेंगे राज

मप्र के राज्यपाल लिख रहे हैं पुस्तक, कई रोचक तथ्य हैं शामिल, देश को चौंकाएंगे दिग्गज नेताओं के रोचक संस्मरण, फरवरी माह के अंत तक पुस्तक छपने की संभावना

नेहरू ने बता दिया था कांग्रेस के बाद कौन करेगा देश पर राज

राजीव सोनी, भोपाल

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की जल्द प्रकाशित होने वाली पुस्तक देश के सियासी और सामाजिक जगत में हलचल मचाने के साथ कई रोचक तथ्यों का राजफाश करेगी। इसमें चौंकाने वाला तथ्य प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने चीन से युद्ध के बाद यह भान करा दिया था कि कांग्रेस के बाद देश का नेतृत्व जनसंघ (अब भाजपा) करेगा। पूर्व में टंडन की 'अनकहा लखनऊ' नामक पुस्तक विवादित व सुर्खियों में रह चुकी है।

राज्यपाल टंडन ने अपने लगभग 70 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के दौरान संपर्क में आए देश-विदेश की दिग्गज शख्सियतों के साथ अपने संस्मरणों के जरिये कुछ ऐसी बातें भी लिपिबद्ध की हैं, जो मौजूदा धारणाओं को तोड़ती हैं। इसमें सभी दलों के नेताओं से जुड़े छोटे-छोटे संस्मरण हैं, जिनके जरिये उनके मन में झांकने की कोशिश भी दिखती है। नेहरू के बारे में वह लिखते हैं कि संस्कार और शिक्षा से अंग्रेज और व्यवहार से उन पर मार्क्सवाद-पूंजीवाद का असर दिखता था, लेकिन सबके सामने उनका समाजवादी स्वरूप रहा। चौंकाने वाली बात यह भी है कि चीन से हुई 1962 की लड़ाई हारने के बाद नेहरू मन से टूटने लगे थे। अस्वस्थ भी रहे, इस बीच वह कुछ समय मित्र पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा भी करते थे, तब उनकी चिंता थी कि इतनी विभिन्नताओं वाले इस देश को मेरे बाद कौन संभालेगा? कोई पार्टी नजर नहीं आती। वहां मौजूद लोगों ने कुछ विकल्प सुझाए, जिन पर उनकी प्रतिक्रिया 'नॉट सो' थी। अंतिम समय नेहरू के दिमाग में जनसंघ ही विकल्प के रूप में रहा। यह बात नेहरू ने जब अपने सहयोगी मंत्री कृष्णमेनन से कही, तब वहां लखनऊ के पत्रकार सलीमुद्दीन उस्मान भी मौजूद थे। उस्मान ने भारी विस्मय के साथ टंडन को स्वयं यह किस्सा सुनाया था। पुस्तक में नेहरू की गुरु गोलवलकर से चर्चा का ब्योरा भी चौंकाएगा।

लालजी टंडन। फाइल

जनसंघ, आरएसएस भी शामिल

जनसंघ का निर्माण, उसके प्रति युवाओं का आकर्षण, द्वारका प्रसाद मिश्र की सभाएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद नेताविहीन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध पर भी टंडन की कलम चली है। आजादी के बाद कांग्रेस की उपयोगिता खत्म होने और उसकी पुण्याई के दोहन की चर्चा भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जल्द देहावसान, नेहरू मंत्रिमंडल में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और डॉ. बीआर आंबेडकर के न आने और फिर महात्मा गांधी की नाराजगी के बाद आंतरिक सरकार में दोनों को शामिल किए जाने की कहानी भी चौंकाएगी।

एक व्यक्ति, जिसने देश के टुकड़े करा दिए

लखनऊ कांग्रेस अध्यक्ष रहे खलीउलजमा का प्रस्ताव ही बंटवारे का आधार बना था। पाकिस्तान जाकर वह मंत्री-गवर्नर भी रहे। विभाजन के बाद उनके लखनऊ लौटने के संस्मरण भी इस पुस्तक में हैं। टंडन ने बंटवारे पर सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की नाखुशी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग भी लिखे हैं। बसपा सुप्रीमो कांशीराम और मायावती के साथ खट्टे-मीठे रिश्ते और नवाबों की विरासत लखनऊ के मौजूदा स्वरूप से लेकर ऐतिहासिक प्रसंगों के जरिये ऐसे दृष्टांत भी हैं।

भाजपा बोली-मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश न बनाए कांग्रेस

नईदुनिया, भोपाल

▶ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र

मध्य प्रदेश में शराब के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व जुटाने के लिए शराब ठेकेदारों के लिए सहयोगी दुकानें खोलने का प्रावधान करने पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराब माफिया को नए वर्ष का तोहफा दिया है। कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश न बनाए।

शिवराज ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार फैसला वापस ले, अन्यथा हम जनता के साथ आंदोलन करेंगे। शराब की लत के कारण अपराध बढ़ते हैं। दुष्कर्म से लेकर कई अपराध शराब के नशे के कारण होते हैं। मुझे प्रदेश के भविष्य व माताओं-बहनों की चिंता है, इसलिए इस फैसले का विरोध कर रहा हूं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि बुजुर्गों के लिए घर पर राशन पहुंचाने से पहले मुख्यमंत्री घर-घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर देना चाहते हैं, ताकि सरकार की आय बढ़ाने की आड़ में कांग्रेस के नेताओं व मंत्रियों की आमदनी बढ़ाई जा सके। शराब की सहयोगी दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने के प्रावधान का भाजपा के विरोध पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक भी नई शराब दुकान 2019-20 में नहीं खोली गई। शिवराज सरकार में 400 नई दुकानें खोली गई थीं।

छात्रों को सियासी मोहरा बनाने का गढ़

वैचारिक वर्चस्व की राजनीतिक लड़ाई में जेएनयू में पीछे छूट रहा शैक्षणिक एक्सीलेंस

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर। ● फाइल फोटो

दो-तीन साल पहले की बात है जेएनयू में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसने देश को झकझोर दिया था। देश के खिलाफ नारेबाजी को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। हालांकि सबने इसे नकार दिया लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच हुई और कुछ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार है। उनमें से एक ने चुनाव मे भी ताल ठोकी और पराजित हुआ। दरअसल अब केवल केरल में सिमटी वाम विचारधारा के लिए जेएनयू एक ऐसा ग्राउंड है जहां कैडर तैयार होते हैं। यही कारण है कि इस बार जब फिर से फीस वृद्दि को लेकर आंदोलन भड़का और नए छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोका गया तो बताया जाता है कि उसके परिणामस्वरूप मारपीट की घटना हुई। नेताओं का फिर से जमावड़ा हो रहा है। पर चिंता की बात यह है कि जेएनयू को शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली संस्थान बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि जेएनयू खुद के लिए संसाधन जुटाकर स्वायत्त हो पाए। कई सवाल खड़े होते हैं और हम सबको इस पर विचार करना होगा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जेएनयू में छात्रों के विवाद को सियासत के खिलाड़ी भले सत्ता के खिलाफ बढ़ते असंतोष का रंग देने में जुटे हों मगर इतिहास गवाह है कि वैचारिक लड़ाई के नाम पर इस विश्वविद्यालय को हमेशा विवादों का अड्डा बनाया गया है। राजनीतिक वजहों से इस विवाद में मौजूदा सरकार को लपेटने की कोशिश हो रही है लेकिन हकीकत यह भी है कि पूर्व की गैर राजग-भाजपा सरकारों के दौर में भी छात्रों को वैचारिक घुट्टी की आड़ में सियासी मोहरा बनाने की चाल कई बार चली गई है।

देश में उच्च शिक्षा और शोध के उत्कृष्ट संस्थान के तौर पर स्थापित जेएनयू में हर साल सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं अपने सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ आते हैं। मगर एक खास वैचारिक वर्चस्व को कायम रखने की सियासी लड़ाई में छात्रों को भटकाने का निरंतर ऐसा प्रयास हुआ है ताकि इस उम्दा संस्थान को शैक्षणिक उपलब्धियों से ज्यादा राजनीति के अखाड़े के रूप में जाना जाए। जेएनयू को सियासत का अखाड़ा बनाने की शुरुआत तो इसकी स्थापना के शैशवकाल में ही हो गई थी जब विचारधारा की आड़ में वाम छात्र संगठनों के चंद छात्रों की उदंडता के चलते 1981 में विश्वविद्यालय को काफी समय तक के लिए बंद करना पड़ा था।

तब वाम छात्र संगठन से जुड़े एक छात्र ने वाइस चांसलर के साथ मारपीट तक कर डाली थी। जेएनयू से जुड़े कई पुराने और मौजूदा प्रोफेसर और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि प्रारंभ से ही इस संस्थान को सियासी हित साधने का जरिया बनाया गया है जिसका हजारों आम छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर होता है। वामपंथी छात्र संगठनों ने तो 2005 में जेएनयू गए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भी निशाना बनाते हुए खूब विवाद किया था। इन संगठनों के नेताओं की ओर से वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर आतंकी अफजल गुरू की फांसी के दिन को यादगार बनाने से लेकर देश के खिलाफ नारे लगाने जैसी घटनाओं की याद तो अभी लोगों के जेहन में पुरानी नहीं पड़ी है।

जेएनयू के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर डॉ. कपिल कपूर विवि के सियासी अखाड़ा बनने की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि करीब 37 साल पहले 1983 में भी आज जैसे ही माहौल बने थे। छात्रों ने कुछ इसी तरह का उपद्रव किया था। उस समय एडमिशन को एक साल के लिए बंद करते हुए छात्रावासों को खाली करा लिया गया था। साल भर बाद छात्रों को छात्रावास में नए सिरे से प्रवेश दिए गए और तब स्थिति सामान्य हो पाई थी। जेएनयू की गरिमा और शैक्षणिक उत्कृष्टता का स्तर बनाए रखने के लिए छात्रों के मौजूदा विवाद को देखते हुए कुछ लोगों ने तो 1983 का ही अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को थोड़े समय के लिए बंद करने की सलाह भी दी। मगर सरकार ने जेएनयू को बंद करने की इन सलाहों को सिरे से ठुकरा दिया है। बेशक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह नजरिया प्रशंसनीय है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों और आलोचनाओं के भय से विश्वविद्यालय को बंद करना उन हजारों छात्रों से अन्याय होता जिनका पठन-पाठन इससे प्रभावित होगा।

जेएनयू में 33 साल तक प्रोफेसर रहे डॉ. कपिल कपूर कहते हैं कि जेएनयू को एक तरह का आइलैंड बना दिया गया है। जहां छात्र पढ़ाई को छोड़ कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त रहते हैं और वे अलग-अलग राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं। वहीं जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके सोपोरी मौजूदा हालत पर कहते हैं कि छात्रों के साथ संवाद फेल होने से यह आंदोलन काफी लंबा खिंच गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे आंदोलन से पढ़ने वाले छात्रों को नुकसान होता है। सोपोरी कहते हैं कि जेएनयू में जिस लेफ्ट-राइट ग्रुप की चर्चा हो रही है वह पहले भी थे मगर अहम बात यह है कि छात्र को छात्र की नजर से ही देखा जाना चाहिए और मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार के अनुसार विवि के एक्सीलेंस के लिए जरूरी है कि वहां खुली बहस हो। रही बात सरकार की आलोचना की, तो जेएनयू ने सभी सरकारों के कामों की आलोचना की है और उन्होंने खुद यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की मुखर आलोचना की थी। इसीलिए वीसी को अपना अहंकार छोड़कर शिक्षकों, छात्रों से बात करनी चाहिए तभी माहौल शांतिपूर्ण हो पाएगा।

जेएनयू को सियासत का अखाड़ा बनाए जाने पर अपनी क्षोभ का इजहार करते हुए यहां के संस्कृत और वैदिक स्कूल के सहायक प्रोफेसर हरिराम मिश्र कहते हैं कि अब अभिभावकों और करदाताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वह उनका ही पैसा है। उनके मुताबिक वैसे आंदोलन तो कई बार हुए, लेकिन पहली बार विवि की साइंस लैब को बंद करना पड़ा है। ऐसे में यह समझना होगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी ही विचारधारा ने कोलकाता विवि को बर्बाद कर दिया है। जेएनयू में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जो आंदोलन के जरिए राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह के विरोध के जरिए वे रातों-रात चर्चा में आ जाएंगे। लेकिन इन्हें समझना होगा, कि डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ कोई नेता नहीं बन सकता है। मिश्र इस विश्वविद्यालय में वार्डन भी रहे हैं और इसके अनुभव के आधार पर वे दावा करते हैं कि यहां कुछ खास विचारधारा के छात्र तो मदिरा का रोजाना सेवन करने से बाज नहीं आते। मगर यह दुहाई देने से नहीं चूकते कि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं।

संस्थान की प्रतिष्ठा में साल दर साल लगातार हो रही गिरावट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जेएनयू की देश और दुनिया में प्रतिष्ठा रही है। इस विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता से लेकर समाज के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रतिभाएं भी दी हैं। शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का तो जैसे कोई सानी नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनमें लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। स्थिति यह है कि जिस जेएनयू में कभी 90 फीसद से ज्यादा बच्चे किसी न किसी फेलोशिप को हासिल करते थे, वहीं अब यह प्रतिशत 65 फीसद के आसपास रह गया है।

अब विवि से दूर-दूर तक वास्ता न रखने वाले गैर-जरूरी विषयों पर एक वर्ग आंदोलन या नारेबाजी करने लगता है। विश्वविद्यालय की साख में गिरावट की जो और बड़ी वजहें है, उनमें कक्षाओं का न लगना प्रमुख है। इस साल भी आंदोलनों के चलते लगातार सत्तर दिनों तक कक्षाएं नहीं लगी। अच्छे शिक्षकों की भी कमी देखी जा रही है। वैसे भी विवि की साख को बढ़ाने के पीछे शिक्षकों का बड़ा हाथ होता है। पहले जेएनयू में शिक्षक और छात्रों का औसत प्रत्येक दस छात्र पर एक शिक्षक का होता था, वही अब बढ़कर प्रत्येक 15 छात्र पर एक शिक्षक का हो गया है। हालांकि इस सब के बाद भी नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) की रैंकिंग में विवि शीर्ष पर बना हुआ है।

विवि के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसके सोपोरी कहते हैं कि इस तरह के आंदोलन का असर जेएनयू की साख पर असर पड़ेगा। अभी तो जेएनयू की रैंकिंग काफी अच्छी है। लेकिन यदि मौजूदा हालात नहीं सुधरी, यह रैंकिंग कब तक बनी रहेगी, इसे लेकर चिंता है। यदि अच्छे शोध और रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो पाएंगे और टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो विवि की छवि पर असर पड़ेगा।

गिरती साख

- 90 फीसद के मुकाबले 60-65 फीसद को मिलती है फेलोशिप
- कम लग रही कक्षाएं, छात्र-शिक्षक अनुपात भी घटा

दूसरे विश्वविद्यालयों की कीमत पर हो रही राजनीति

अरविंद पांडेय ● नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय फिर से विवादों में है। देश के एक प्रीमियम शैक्षणिक संस्थान के लिए यह दुखद है। इस बार विवाद की शुरुआत वैसे तो छात्रावास की फीस में बढ़ोत्तरी को लेकर हुई लेकिन जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यूटिलिटी और सर्विस जैसे शुल्क को वापस लेने और गरीब बच्चों के लिए रूम रेंट को आधा करने के बाद भी जेएनयू को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है वह सोचने को मजबूर करता है। यह सवाल खड़ा करता है कि देश के 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आखिर जेएनयू में ही आंदोलन, प्रदर्शन और भारत विरोधी नारे लगाने की ज्यादा घटनाएं क्यों होती हैं। क्या एक खास विचारधारा यहां किसी दूसरी विचारधारा को पनपने से रोकने का प्रयास करती है? दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मुकाबले जेएनयू को ही प्राथमिकता क्यों मिलनी चाहिए? क्या इन सभी विश्वविद्यालयों में समानता नहीं होनी चाहिए? क्या विश्वविद्यालय को अपना कुछ संसाधन जुटाने लायक नहीं बनाना चाहिए?

यह पहला मौका नहीं है जब जेएनयू विवादों के साये में है। सत्तर दिन से ज्यादा का समय निकल जाने के बाद भी फीस को लेकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई- लिखाई ठप है। विश्वविद्यालय में फिलहाल 8800 छात्र हैं और बताया जा रहा है कि हर आंदोलन में बमुश्किल छह-सात सौ छात्र ही शामिल होते हैं जो बाकी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मौजूदा समय में जेएनयू का सालाना बजट करीब 600 करोड़ रुपये है और इस हिसाब से वहां के हर छात्र पर सालाना औसतन खर्च सात लाख रुपये है। इसके साथ ही जेएनयू में पढ़ने वाले 71 फीसद से ज्यादा छात्रों को मौजूदा समय में कोई न कोई फेलोशिप या छात्रवृत्ति मिल रही है। अब एक नजर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) पर डालते हैं। यहां का सालाना बजट 1200 करोड़ रुपये है और यहां 32 हजार छात्र हैं। ऐसे में बीएचयू के एक छात्र पर औसतन सालाना खर्च लगभग साढ़े तीन लाख रुपये आता है। यानी जेएनयू के मुकाबले आधा। दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर भी नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि जेएनयू किस तरह प्रीमियम दर्जा प्राप्त है लेकिन उसकी उर्जा को वाम विचारधारा रोकती है। जेएनयू के छात्रावासों की फीस अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और बीएचयू जैसे ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कम ही है। जेएनयू में बढ़ोत्तरी के बाद छात्रावास में रहने के लिए छात्रों को अब सालाना करीब 36 हजार रुपये चुकाने होंगे, इनमें सालाना 36 सौ रुपये कमरे का किराया भी शामिल है। पहले उन्हें सालाना 32,620 रुपये देने होते थे। वहीं गरीब (बीपीएल) छात्रों को सालाना करीब 34 हजार रुपये देने होंगे। जबकि डीयू में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास के लिए सालाना करीब 48 हजार रुपये देने पड़ते हैं, जबकि बीएचयू में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास के लिए 35 हजार रुपये से ज्यादा देने होते हैं। जेएनयू प्रशासन का मानना है कि छात्रावास की फीस में यह बढ़ोत्तरी तब की गई है, जब यहां कमरे का किराया हर महीने सिर्फ दस रुपए था। जो कि दूसरे विवि की तुलना में ना के बराबर है। हालांकि मंहगी होती शिक्षा में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी को ठीक नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे लेकर सरकार खुद पर दोहरी मार नहीं पड़ने देना चाहती है। एक तरफ जहां उस पर किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी न करने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति देने का दबाव भी है। पिछले साल ही सरकार ने फेलोशिप में बढ़ोत्तरी की है। जिसके तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 28 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपये किया गया है, वहीं सीनियर रिसर्च फेलोशिप को 31 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया है।

गौरतलब है कि फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दखल दिया। साथ ही विवि प्रशासन की ओर से लगाए गए यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को छात्रों पर थोपने के बजाय इसकी अदायगी यूजीसी से करने के निर्देश दिए थे।

फेलोशिप और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)

विश्वविद्यालय	लाभार्थी
जेएनयू	71.00
दिल्ली विवि	11.00
जामिया विवि	5.00
बीएचयू	9.00
इलाहाबाद विवि	5.63
अलीगढ़ विवि	7.57

हर छात्र पर औसतन सालाना सात लाख रुपये खर्च करती है सरकार

जेएनयू और दूसरे केंद्रीय विवि में छात्रावास फीस (रुपए में सालाना)

विश्वविद्यालय	रूम रेंट	स्थापना चार्ज	यूटीलिटी चार्ज	सर्विस चार्ज	अन्य चार्ज	मैस चार्ज
जेएनयू (वृद्धि के पहले)	120	2,200	–	–	300	30,000
जेएनयू (वृद्धि के बाद)	3,600	2,200	माफ	माफ	300	30,000
जेएनयू (बीपीएल छात्रों से)	1,800	2,200	माफ	माफ	300	30,000
दिल्ली विश्वविद्यालय	500	–	500	7,650	6,750	32,400
बीएचयू	2,860	–	–	–	–	32,400
अलीगढ़ विवि	1,200	–	2,700	–	–	13,200
इलाहाबाद विवि	2,500	–	8,000	2,000	1,500	21,000
जामिया विवि	800	–	1,600	1,000	1,100	27,000

(नोट: फिलहाल जेएनयू ने हर महीने 600 रुपए यूटीलिटी और 17 सौ रुपए सर्विस चार्ज तय किया था)

जावडेकर बोले-बेनकाब हुए वामपंथ समर्थक छात्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच से साफ हो गया है कि वामपंथी पार्टियों से संबद्ध संगठनों के छात्र पांच जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा में शामिल थे। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाकपा, माकपा और आप को लोगों ने खारिज कर दिया। अब वे अपना निहित स्वार्थ साधने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जेएनयू में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं वाम दल : ईरानी: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि वामपंथी पार्टियां जेएनयू में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'जेएनयू में वाम साजिश बेनकाब हुई। उन्होंने उत्पात मचाया, सार्वजनिक संपत्ति तबाह की, नए छात्रों को नामांकन कराने से रोका, परिसर को राजनीतिक युद्ध भूमि की तरह इस्तेमाल किया।'

पीयूष गोयल ने दिल्ली पुलिस की सराहना की: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जेएनयू हिंसा की त्वरित जांच के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की। पुलिस ने पांच जनवरी को परिसर में हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट में नौ संदिग्धों की पहचान की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने त्वरित जांच की है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष जांच टीम का नेतृत्व कर रहे दिल्ली पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्केय पिछले दो दिनों में केवल चार घंटे सो सके। इस संवेदनशील मामले की जांच में उन्होंने अत्यंत आधुनिक डिजीटल तकनीक का इस्तेमाल किया।

लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाई भाकपा, माकपा और आप कर रही छात्रों का इस्तेमाल

प्रकाश जावडेकर। फाइल

डाटा, सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट में याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा के मामले से जुड़े सुबूतों, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज व वीडियो और डाटा को संरक्षित रखने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जेएनयू के तीन प्रोफेसरों द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। प्रो. अमीत परामेस्वरन, प्रो. अतुल सेन और प्रो. शुक्ला विनायक सावंत की ओर से दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि यूनिट अगेंस्ट लेफ्ट और फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस जैसे वाट्सएप ग्रुप के डाटा को भी संरक्षित रखा जाए। ताकि जेएनयू के अंदर हुई हिंसा की जांच में मदद मिल सके।

अधिवक्ता अभिक चिमनी, मानव कुमार और रोशिनी नांबोदरी के माध्यम से दायर की गई याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि वह सुबूतों को संरक्षित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को निर्देश दे। गौरतलब है कि 5 जनवरी को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर छात्र-छात्राओं की पिटाई करने के साथ ही हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की थी।

फीस वृद्धि का विवाद सुलझने के आसार बढ़े

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दखल के बाद सुलझता दिख रहा है। पिछले करीब 70 दिनों से चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए मंत्रालय में शुक्रवार को पूरे दिन बैठकों का दौर चला। सबसे पहले कुलपति सहित विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जबकि शाम को आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। इस बीच विवि प्रशासन ने यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को हटाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि इसे लेकर सहमति पहले ही बन चुकी थी।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू हिंसा पर पुलिस की रिपोर्ट के संबंध में ट्वीट किया और कहा कि विश्वविद्यालय को हिंसा और राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में विवि के कुछ छात्र संलिप्त पाए गए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विवि परिसर में हिंसा और अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने आंदोलित छात्रों से आंदोलन खत्म कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है। वहीं छात्रों ने एचआरडी मंत्रालय पर भरोसा जताते हुए सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन वह अभी भी वीसी को हटाने की मांग पर कायम हैं। सचिव से मुलाकात के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष ने कहा, 'हमने अपनी बात रख दी है। मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हम बैठक करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आंदोलन खत्म करना है या नहीं।'

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कुलपति के साथ बैठक कर छात्रों के साथ संवाद बहाली पर जोर दिया। साथ ही जिन मुद्दों पर पूर्व में सहमति बनी है, उसकी छात्रों तक सही जानकारी भी देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुलपति ने बताया कि छात्रों से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज न लिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

आंदोलित छात्रों ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बातचीत में विवि पर यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को वापस न लेने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि इसे लेकर अब तक विवि ने कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। कुलपति और छात्रों के साथ अलग-अलग हुई बैठक की जानकारी देते हुए खरे ने बताया कि छात्रों की वैसे तो कई मांगे है, लेकिन मुख्य मांग फीस बढ़ोतरी की है। इसमें से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को वापस ले लिया गया है। अब उन्हें सिर्फ रूम रेंट ही देना होगा। ध्यान रहे कि छात्रों के होस्टल के सिंगल सीटर रूम का मासिक किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये और डबल रूम का दस रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे से मुलाकात के बाद बाहर निकलते जेएनयू के वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार। प्रेट्र

कार्यक्रम

अपराह्न 3.30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, मंत्री फिरहाद हकीम करेंगे स्वागत, शाम में करेंसी बिल्डिंग व मिलेनियम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

ममता बनर्जी और मोदी की आज हो सकती है मुलाकात

जागरण संवाददाता, कोलकाता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। यह उनका दूसरी बार पीएम बनने के बाद पहला कोलकाता दौरा है। इस दौरान राजभवन में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मुलाकात कर सकती हैं।

पीएम का कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। खबर है कि पीएम अपराह्न करीब 3.30 बजे विशेष विमान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा राज्य सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता पीएम का स्वागत करेंगे। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पीएम रेस कोर्स मैदान पहुंचने के बाद कार से राजभवन जाएंगे। पहले पीएम को शाम पांच बजे एयरपोर्ट आना था, लेकिन अंतिम समय में इसमें परिवर्तन किया गया है। राजभवन से प्रधानमंत्री शनिवार शाम 5.30 बजे बीबीडी बाग स्थित करेंसी बिल्डिंग पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की ओर से जीर्णोद्धार किए गए इस हेरिटेज बिल्डिंग सहित कुल तीन इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मिलेनियम पार्क जाएंगे, जहां हावड़ा ब्रिज पर लगे लाइट एंड साउंड सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। यहां से पीएम का बेलूर मठ जाने का कार्यक्रम है। वहां से लौटकर पीएम राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसी दौरान सीएम ममता बनर्जी उनके साथ मुलाकात कर सकती हैं। रविवार सुबह 11 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में पीएम शिरकत करेंगे।

नरेंद्र मोदी।

ममता बनर्जी। सभी फाइल

माकपा महिला मोर्चा ने निकाली रैली

जागरण संवाददाता, हावड़ा : कोलकाता यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेलूरमठ जाने के विरोध में बाली-बेलूर माकपा के महिला मोर्चा की ओर से शुक्रवार को इलाके में एक रैली निकाली गई। इस दौरान माकपा महिला समर्थकों ने पीएम मोदी के इस दौरे का विरोध किया। वहीं 'मोदी गो बैक' के नारे भी लगाए। रैली में शामिल महिला समर्थक 'मोदी गो बैक' लिखा पोस्टर थामे हुए थी। बेलूर बाजार से शुरू हुई रैली आसपास के विभिन्न इलाकों से होते हुए बाली खाल स्थित बस स्टैंड पहुंच संपन्न हुई। रैली में महिला समर्थकों के अलावा पार्टी नेता राजन राय, समीरन चटर्जी समेत स्थानीय स्तर पर लोग भी शामिल हुए।

डीसीपी सहित 64 पुलिसकर्मियों की टीम कर रही है जांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वायरल वीडियो के माध्यम से की जा रही आरोपितों की पहचान

जेएनयू कैंपस में रविवार को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस खासी सावधानी बरत रही है। चूंकि मामला प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ा है, इसलिए शुक्रवार को नौ आरोपितों की तस्वीरें जारी करने के बाद पुलिस अब आगे की जांच में भी फूंक-फूंककर कदम रख रही है। मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टर्की सहित 64 पुलिसकर्मियों की टीम जांच कर रही है।

डीसीपी जॉय टर्की ने बताया कि चूंकि पुलिस को जेएनयू परिसर से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है लिहाजा वायरल वीडियो, स्थानीय छात्र, शिक्षक और लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस यह जांच भी कर रही है कि स्थानीय छात्रों के साथ कहीं बाहर से भी तो कुछ छात्र कैंपस में नहीं आए थे।

रंधावा ने कहा-निर्दोष पर नहीं की जाएगी कार्रवाई : दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने पर छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पुलिस सर्तक है कि किसी निर्दोष को ना पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जेएनयू हिंसा मामले में शुक्रवार को जिन छात्रों की तस्वीर जारी की गई है वे लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन कर राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। अधिकांश पर दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और नई दिल्ली जिले में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है।

11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित हुआ था नागरिकता संशोधन कानून। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 11 जनवरी 2020

गुजरात विस में सीएए के समर्थन में प्रस्ताव पारित

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में बताया कि 1947 में महात्मा गांधी व 2014 से पहले कांग्रेस खुद इस तरह के कानून का समर्थन कर चुकी है।

देश में जहां एक ओर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध व समर्थन में शहर गांवों तक प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं गुजरात सरकार ने सीएए को वैधानिक रूप से राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस के भारी विरोध व हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने बहुमत के साथ सीएए के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराया। सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई व जैन समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है।

जडेजा ने कहा कि महात्मा गांधी ने 26 सितंबर, 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू, जैन, सिख आदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत आने का अधिकार है। कांग्रेस खुद पहले सीएए जैसे कानून के पक्ष में थी।

बर्मा में जन्म पर रूपाणी का जवाब: विशेष सत्र से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने कहा कि मुख्यमंत्री रूपाणी का जन्म बर्मा में हुआ था। वहीं निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी कहा कि गुजरात की छह करोड़ जनता से नागरिकता का सबूत मांगने वाले मुख्यमंत्री रूपाणी जनता को अपने भारतीय होने का सबूत देंगे। इस पर खुद रूपाणी ने अपने बचाव में कहा कि उनके माता-पिता के पास भारतीय पासपोर्ट था जिसके चलते उनका नाम जन्म के साथ ही भारतीय के तौर पर दर्ज हो गया था।

यह पाकिस्तान की संसद नहीं: कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने सीएए के विरोध में अपने खून से लिखा प्ले कार्ड विधानसभा में दिखाया तो अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा यह पाकिस्तान की संसद नहीं है। विधायक को इस तरह सदन में प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए।

अनेक राज्यों में रैलियां निकाल लोगों को किया जागरूक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग भी सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड और बंगाल सहित अन्य राज्यों में लोग घर-घर जाकर लोगों को कानून के बारे में सही जानकारी देकर भ्रम को दूर कर रहे हैं।

इसके साथ ही रैली, पदयात्रा और हस्ताक्षर अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश रैली निकाली गई। एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने विपक्षी पार्टियों से लोगों को आगाह किया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अनेक तरह के जागरूकता आयोजन किए गए। मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा, हरियाणा में पदयात्रा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में रैली और पंजाब में बाइक रैली निकाली गई।

सीएए के समर्थन में लखनऊ सहित कई जिलों में भाजपा समेत विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली और गोष्ठी आयोजित कीं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे। यहां जनसभा में कहा कि देश के तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए टुकड़े-टुकड़े गैंग जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गैरल हसन ने कहा कि देश के किसी मुसलमान को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। श्रावस्ती में अधिवक्ता परिषद ने कानून से संबंधित पत्रक बांटे। गोंडा और गाजियाबाद में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अयोध्या में भी लोगों को सीएए का महत्व बताया गया।

हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में चंबा-कांगड़ा सांसद किशन कपूर की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली। पालमपुर में एक जागरूकता कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में देश की कुछ पार्टियां लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है।

मध्य प्रदेश के बड़वानी और आगर में सीएए के समर्थन में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों लोग उमड़े। बड़वानी में दस हजार से अधिक तो आगर में लगभग 15 हजार लोग यात्रा में शामिल हुए। बड़वानी के एसपी डीआर तेनीवार ने बताया कि बिना अनुमति रैली निकाले जाने पर शुक्रवार देर शाम सांसद गजेंद्र पटेल, बड़वानी विधायक प्रेमसिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी सहित पांच हजार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सांसद अरुण साव की अगुवाई में नागरिक जागरण मंच के बैनर तले जनजागरण रैली निकाली गई। इसमें लोगों ने 300 फीट का तिरंगा लेकर नगर भ्रमण किया।

पंजाब के होशियारपुर में जिला भाजपा की ओर से बाइक रैली निकाली गई। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सदस्य श्वेत मलिक ने कहा कि सीएए पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। असलियत यह है कि इटली से ताल्लुक रखने वालीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसी कानून के तहत भारत में नागरिकता ली थी। जम्मू-कश्मीर में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से अंबेडकर चौक से लेकर बाहूफ्लाजा तक रैली निकाली गई। पूरे उत्तराखंड में सीएए के समर्थन में भाजपा ने रैलियां निकालीं। कालाढूंगी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएए के समर्थन में जनसभा की। हरियाणा के विभिन्न जिलों में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सभी समाज और वर्गों ने भागीदारी की।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शुक्रवार को जम्मू में भाजपा नेताओं ने जागरूकता रैली निकाली। जागरण

चलाया अभियान

- विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने को आम लोग भी सक्रिय
- तिरंगा यात्रा, पदयात्रा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली

उमा भारती ने राहुल और प्रियंका की तुलना जिन्ना से की

नईदुनिया, भोपाल: सीएए के समर्थन में मध्य प्रदेश के पन्ना में रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस के नेता नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में षड्यंत्रपूर्वक भय और भ्रम फैलाकर देश में भावनात्मक विभाजन का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उमा ने कहा कि जिन्ना तो अब रहे नहीं, लेकिन यहां राहुल जिन्ना और प्रियंका जिन्ना हैं, जो माहौल को खराब कर रहे हैं और मुस्लिमों में सीएए को लेकर डर फैला रहे हैं।

उमा भारती ने शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या हममें से किसी ने कभी कहा कि सोनिया गांधी के पिता मुसोलिनी की सेना में सैनिक थे। सोनिया की शादी हमारे देश में हुई है और वह हमारी बहू हैं। हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। भारती ने कहा कि दुनिया के मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि भारत अखंड रहेगा, क्योंकि जो खंड-खंड हुआ है, उसे भी लाने की हमारी तैयारी है। भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। यहां की सांस्कृतिक विरासत को खत्म नहीं किया जा सकता।

सीएए पर फेल हुआ विपक्ष का 'हॉरर हंगामा'

नकवी की दो टूक ▶ भारतीय नागरिक के अधिकारों पर न कोई खतरा था, न है और न होगा

बोले, नौजवानों को कंधों पर रखकर बंदूक चला रहा विपक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर फैलाए जा रहे भ्रम को विपक्ष का फ्लॉप 'हॉरर हंगामा' बताते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि नौजवानों को गुमराह कर राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नकवी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वह राजनीतिक पाखंड है। नौजवानों के कंधों पर बंदूक रखकर यह लोग अशांति फैला रहे हैं, एक वर्ग विशेष को भ्रमित करके राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भय-भ्रम का भूत अब बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस व उसके साथियों द्वारा झूठ व अफवाह के जरिए अमन को अगवा करने की साजिश हो रही है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों पर न कोई खतरा था, न है और न होगा। मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से ज्यादा महफूज जगह कहीं नहीं है।

सेलेक्ट कमेटी की मंजूरी के बाद पारित हुआ कानून: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई संशोधन करने के बाद यह बिल लाया गया है। हम चाहते तो जनवरी 2019 में ही इसे पास करा लेते, लेकिन विपक्ष की मांग पर इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। कमेटी की मंजूरी के बाद ही बिल पारित हुआ। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो एक वर्ग विशेष को अलग थलग करने की साजिश कर रहे हैं।

हम भी देखना चाहेंगे फिल्म छपाक: जेएनयू प्रकरण के बाद चर्चा में आयी फिल्म 'छपाक' का भाजपा समर्थकों द्वारा बहिष्कार करने के सवाल पर नकवी ने कहा, 'समय मिलेगा तो वह भी छपाक फिल्म को देखना चाहेंगे।' कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ने पर नकवी का कहना था, 'बेहतर यह होता कि राजस्थान या मध्य प्रदेश में जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों को बेहाल जनता की सुध लेने की सलाह देतीं।'

कांग्रेस सत्ता में आई तो हटा देंगे सीएए : प्रियंका

जागरण संवाददाता, वाराणसी

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) हटा देंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां लागू भी नहीं हो रहा है। प्रियंका ने कहा, संविधान ने अधिकार दिया है कि किसी मसले में असहमति होने पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा सकता है, लेकिन सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया गया। उन्हें दंगाई तक कहा गया है।

प्रियंका शुक्रवार सुबह वाराणसी पहुंची। इसके बाद सीधे राजघाट स्थित रविदास मंदिर जाकर उन्होंने दर्शन किया। वहां से मोटर बोट पर पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ गईं जहां बीएचयू के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। छात्रों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता को साझा किया। एक साल की मासूम चंपक को घर छोड़कर जेल जाने वाली मां एकता शेखर सिंह व पिता रवि शेखर सिंह ने अपने दर्द को बयां किया। सीएए को लेकर प्रदर्शन के दौरान बजरडीहा के भगदड़ में मृत बालक के पिता व दादी से भी प्रियंका ने मुलाकात की और सांत्वना दी। कहा कि बीएचयू के बच्चों से मिलने आई हूं। बीएचयू के छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जिनको जेल भेज दिया गया। इस दौरान एक मासूम के मां-बांप पर भी तरस नहीं किया गया। प्रियंका ने संवाद के दौरान विधिक सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि सीएए के प्रदर्शन को लेकर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसकी वापसी के लिए प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर वार्ता की गई है। संवाद के बाद प्रियंका ने श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद बाबा के दरबार पहुंचकर दर्शन-पूजन भी किया।

डरा रही, दबा रही भाजपा सरकार: प्रियंका ने वाराणसी में छात्रों के साथ संवाद की एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा है कि यह एक साल की छोटी बच्ची चंपक की मां है। पुलिस को मां-बाप को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी जेल में डाल दिया। एक साल की बच्ची को मां-बाप से जुदा कर दिया। आज तमाम लोगों की बात सुनकर ऐसा लगा कि भाजपा ने पुलिस को ऑर्डर दे रखा है कि कोई आवाज उठाए तो दबा दो और डरा दो। अच्छी बात है कि वाराणसी के छात्र-छात्राएं व सामाजिक कार्यकर्ता डरे नहीं।

केंद्र ने देश में सीएए किया लागू

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को दस जनवरी, 2020 से प्रभावी करने की घोषणा की है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

नागरिकता (संशोधन) कानून की धारा एक की उप धारा(2) के तहत केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 से इस कानून को लागू करने का निश्चय किया है। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा। इससे देश के संविधान मूलभूत अवधारणा को ठेस पहुंचती है।

हालांकि केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा इस कानून का जमकर बचाव करते रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीन पड़ोसी देशों से आए लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा है। इन लोगों के पास अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भारत आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय को इस कानून के संबंध में अभी नियम आदि तय करने बाकी हैं।

नया कानून नागरिकता छीनता नहीं, बल्कि दे रहा है

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कई सितारे आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं फिल्मी बिरादरी से जुड़े कुछ लोग अब खुलकर सीएए के समर्थन में आ गए हैं। गुरुवार को मुंबई में जूही चावला ने दो टूक कहा था कि लोगों को समझने तो दो कि आखिर सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) क्या है, किस बारे में है? हर कोई जल्दबाजी में विभाजन को लेकर बातें कर रहा है। हम एकता पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके सुर में सुर कई और फिल्मी हस्तियों ने मिलाए हैं।

धर्म से कोई लेना-देना नहीं है

फिल्म मेकर अशोक पंडित ने शुक्रवार को कहा, 'सीएए कई देशों में लागू है। इनमें से एक पाकिस्तान भी है। यह देश की अंदरूनी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपने देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं। विरोध कर रहे लोगों को दिक्कत मौजूदा सरकार से है। दिल्ली में चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है।' उन्होंने कहा कि हर देश में नागरिकता को साबित करना होता है। अगर कागजात नहीं हैं, तो उसका कोई और उपाय तो होगा ही। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा घर जल गया था, इसलिए कागजात नहीं हैं। घर तो मेरा भी जला था कश्मीर में। कश्मीरी हिंदुओं को तो निकाल दिया गया था। हमारे पास भी कागजात नहीं थे, लेकिन नागरिकता हम साबित कर सकते हैं। हम देशहित में खड़े हुए हैं। कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहां आकर बसे हैं। आतंकवाद पूरी दुनिया का मुद्दा बना हुआ है। इस तरह के विरोध से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान, अमेरिका में इस तरह का विरोध करके दिखाए, तब पता चलेगा। इस देश में ही ऐसे नखरे चलते हैं।

अशोक पंडित

विरोध करने वाले बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं करते : राकेश

राकेश ओमप्रकाश मेहरा।

राकेश ओमप्रकाश मेहरा कहते हैं कि लोगों के कहने पर आ गया। सेट पर तो ये लोग बिना स्क्रिप्ट पढ़े नहीं जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जो दस से पंद्रह लोग आकर विरोध कर रहे हैं, वह बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यह बॉलीवुड सपोर्ट नहीं है। यहां करीब दस लाख लोग काम करते हैं। जेएनयू जाकर दीपिका पादुकोण ने राजनीति का मुद्दा गर्माया है। उन्हें वहां जाने का हक है। लेकिन यह बोलने से न शर्माएं कि वह कन्हैया कुमार की राजनीति में यकीन करती हैं।

सीएए व एनआरसी को जोड़कर देखने पर भ्रम : रणवीर शौरी

विरोध को लेकर अभिनेता रणवीर शौरी का मानना है कि लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'सीएए और एनआरसी को एक साथ जोड़कर देखने पर लोगों में भ्रम है। लोगों को लगता है कि सीएए और एनआरसी को एक साथ लागू करने पर भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता जा सकती है। किसी भी देश में अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा करना बहुत आसान होता है। विपक्ष इसका लाभ उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के दौरान हमें सीएए के बारे में जानकारी दी।

रणवीर शौरी

अनिल शर्मा बोले-मैं कानून के समर्थन में हूं

गदर फेम निर्देशक अनिल शर्मा कहते हैं, मैं भारतवासी हूं। अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। मैं कानून का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि यह किसी से कुछ छीन नहीं रहा है बल्कि लोगों को नागरिकता प्रदान कर रहा है। विदेश में प्रताड़ित लोगों को अगर हम नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें समस्या किस बात की है। यह नागरिकता उन लोगों को दी जानी है जो वर्ष 2014 से पहले भारत आए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया है। इसके बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है।

अनिल शर्मा

गृह मंत्री के मुंह से बात निकली नहीं, हिंसा शुरू हो गई : दिलीप ताहिल

दिलीप ताहिल पहले ही कह चुके हैं कि हमारे गृह मंत्री के मुंह से यह बात निकली ही नहीं थी कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह पहले से ही तय था कि जैसे ही गृह मंत्री कुछ बोलेंगे हम जामिया मिलिया, जेएनयू और एएमयू जैसे विश्वविद्यालयों में छात्रों के बहाने हिंसा शुरू कर देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि हमारे देश के नागरिकों का सीएए से कुछ लेना-देना नहीं है। यह हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों के बारे में नहीं है। जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आते हैं उनकी गिनती करने के लिए कौन है।

दिलीप ताहिल

इंसानियत को ऊपर रखें : अध्ययन सुमन

कलाकारों के अपनी राय व्यक्त करने के संबंध में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन कहते हैं, 'देश में बहुत कुछ हो रहा है। कलाकार के लिए राय देना सही नहीं होगा। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि इससे आम लोगों को तकलीफ हो रही है। कई राजनीतिक दल हड़कंप मचाकर निकल जाते हैं। इंसानियत को ऊपर रखें। दुनिया में वैसे ही बहुत तनाव है। दिल टूटता है लोगों में इतना गुस्सा देखकर।

अध्ययन सुमन

चुनौती देने वाली याचिकाओं के स्थानांतरण पर नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ केंद्र सरकार ने कहा- अलग-अलग जगह सुनवाई होने से एक ही मुद्दे पर आ सकते हैं अलग-अलग फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई करने की केंद्र सरकार की मांग पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र की स्थानांतरण याचिका पर उच्च न्यायालयों में कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया और इस केस को भी इसी मसले पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की स्थानांतरण याचिका पर दलीलें सुनने के बाद जारी किया। इसके अलावा सीएए के मुद्दे पर लंबित अन्य याचिकाओं को भी कोर्ट ने पहले से लंबित मामलों के साथ सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दाखिल कर कहा है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सीएए को चुनौती दी गई है। ऐसे में अलग-अलग जगह सुनवाई होने से एक ही मुद्दे पर अलग-अलग फैसले आ सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी मामले अपने यहां स्थानांतरित करके एक साथ सुनवाई करे, ताकि एक ही मुद्दे पर भिन्न फैसले आने की संभावना न रहे।

सीएए मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 59 याचिकाएं लंबित हैं। इन पर गत 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने उस वक्त मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इन्कार करते हुए सभी याचिकाओं को 22 जनवरी को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया था। अब सभी मामलों पर उसी दिन सुनवाई होने की उम्मीद है। 59 याचिकाओं में ज्यादातर याचिकाएं विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दाखिल की गई हैं। कई याचिकाएं संगठनों की ओर से भी दाखिल हुई हैं। ज्यादातर याचिकाओं में सीएए को असंवैधानिक घोषित कर रद करने की मांग की गई है। याचिका दाखिल करने वाले विपक्षी दलों के नेताओं में कांग्रेस के जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राजद के मनोज झा, एआइएमआइएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य संगठनों ने भी याचिका दायर की है।

सरोकार

इलाके की युवतियों के लिए प्रेरणा बनीं कांगड़ा की 22 वर्षीय मोटर मैकेनिक स्नेहलता

नारी सशक्तीकरण

गाड़ी कितनी भी खराब हो, ठीक करना जानती है...

दिनेश कटोच, कांगड़ा

▶ बचपन में ही सिर से उठ गया था माता-पिता का साया

▶ तकनीशियन के साथ-साथ वाहनों की मरम्मत में है पारंगत

जिंदगी की गाड़ी कतई ठीक नहीं थी, सिर से मां-बाप का साया छिन जाने के बाद भाई ने सहारा दिया। ट्रैक्टर चलाना सीख जिंदगी की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी। और अब कोई भी गाड़ी कितनी ही खराब हो, स्नेहलता उसे ठीक करना सीख गई है। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर वह तकनीशियन के साथ-साथ वाहनों की मरम्मत में पारंगत हो चुकी है। महिंद्रा के मोटर वर्कशॉप में पुरुष सहयोगियों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर आजीविका जुटा रही है।

22 साल की स्नेहलता इलाके की युवतियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला स्थित शाहपुर हलके का मनेई गांव, जहां स्नेहलता ने गरीबी से जंग लड़कर जिंदगी की गाड़ी की मरम्मत करने का हौसला जुटाया, आज उस पर गर्व करता है। स्नेहलता ने स्कूली पढ़ाई के बाद शाहपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आइटीआइ) से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया। इस दौरान उसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोटर वर्कशॉप में काम करने का अवसर मिला। उसने चुनौती स्वीकारी। वर्कशॉप में युवाओं के बीच तकनीशियन ट्रेनी के रूप में वह अकेली युवती थी। अपने काम के साथ-साथ वह वाहनों की मरम्मत करने में भी पारंगत हो गई है। उसकी मदद और हौसला अफजाई को वर्कशॉप के अन्य सहयोगियों के अलावा वर्कशॉप मैनेजर और प्रबंधन के सदस्य भी तत्पर रहते हैं। सभी उसके काम और लगन की सराहना करते हैं।

स्नेहलता ने बताया कि छोटी उम्र में ही सिर से माता-पिता का साया उठ गया था। 2006 में पिता सुरेश कुमार और 2009 में मां वृशमा देवी का देहांत हुआ। घर की जिम्मेदारी बड़े भाई विनय कौंडल पर आई और उन्होंने इसे निभाया भी। ट्रैक्टर चलाकर विनय ने भाई-बहनों को पढ़ाया। स्नेहलता ने पढ़ाई के साथ-साथ भाई का हाथ बंटाने की ठानी और ट्रैक्टर चलाना सीखा। यहां से उसे मैकेनिक और फिर तकनीशियन बनने का रास्ता खुद मिल गया। अब स्नेहलता का छोटा भाई पवन भी शाहपुर आइटीआइ में टर्नर ट्रेड का कोर्स कर रहा है। कहती हैं, पुरुषों वाला यह काम आसान नहीं लगा था। शुरुआती दौर में मुश्किलें आईं, लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। काम कोई भी हो, उसे मेहनत से करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। वर्कशॉप में सभी का सहयोग मिलता है और ऐसा लगता है कि परिवार के बीच काम कर रही हूं...। वर्कशॉप मैनेजर राकेश ठाकुर ने बताया कि दरअसल कंपनी की एमडी भी महिला हैं। एमडी शिल्पा ग्रोवर ने इस काम में भी युवतियों को आगे लाने और उनके लिए रोजगार का अवसर जुटाने का जतन किया है। स्नेहलता को हमने मौका दिया। स्नेहलता यहां अन्य युवाओं के साथ काम कर रही है और वह इलाके की अन्य युवतियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इलाके के समाजसेवी संजय शर्मा कहते हैं, इस बच्ची को देख कर मुझे लगा कि वास्तव में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। यह हम सब के लिए प्रेरणा है। मैं अब इलाके की बेटियों से यही कहता हूं कि गरीबी और समस्याओं के आगे रोने से बेहतर है कि हौसला जुटाएं और सूझबूझ के साथ आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चौपहिया वाहनों की एक वर्कशॉप में वाहन की मरम्मत करती मनेई गांव की स्नेहलता। जागरण

नेहरू ने ठुकरा दिया था बाबा साहेब का प्रस्ताव : स्वामी

जासं, नई दिल्ली: भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश के विभाजन के समय डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुस्लिम आबादी का स्थानांतरण भी पूरी तरह होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का झगड़ा होने की संभावना न रहे, लेकिन यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया।

स्वामी राष्ट्र सेविका समिति के प्रबुद्ध वर्ग मेधाविनी सिंधु सृजन व शरण्या संस्था द्वारा दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आयोजित सीएए और महिला सुरक्षा-देश की प्राथमिकता विषय पर विचार मंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। स्वामी ने कहा कि सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित केवल 31313 हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को नागरिकता प्रदान करेगा। भारत ने इस संबंध में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है।

40 रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी प्रशिक्षण दे रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ। इसके लिए वह प्रतिबंधित संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की मदद ले रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सेनाओं और अर्धसैन्य बलों को इस आशय की चेतावनी जारी की है।

पाकिस्तान ने आतंक फैलाया, कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने भेदभाव

रखा पक्ष ▶ जम्मू के प्रतिनिधियों ने राजनयिकों से मुलाकात कर बयां की पीड़ा, राजनयिकों ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी की बैठक

बोले-पश्चिमी पाकिस्तान के निवासी अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए

जम्मू, राज्य ब्यूरो

पाकिस्तान ने घुसपैठ और गोलाबारी कर जम्मू में आतंक फैलाया तो कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने क्षेत्र को नजरअंदाज कर जम्मू वासियों का हक मारा। कश्मीर पंडित घर से बेघर हो गए और पश्चिमी पाकिस्तान के निवासी अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए। अब उम्मीद है अनुच्छेद 370 हटने के बाद सात दशकों से जारी भेदभाव खत्म होगा और रोजगार व विकास के रास्ते खुलेंगे। यह बात शुक्रवार को जम्मू में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर के हालात का जायजा लेने आए 15 देशों के राजनयिकों से मुलाकात में कही।

राजनयिकों के साथ बैठकों का सिलसिला सुबह जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के साथ हुआ। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद व्यवस्था में आए बदलाव, विकास को तेजी देने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों के आर्थिक, सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार केके शर्मा, गृह सचिव शालीन काबरा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह, योजना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा समेत प्रशासन के कई उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इसके बाद राजनयिकों का कश्मीरी पंडितों, सभ्य समाज, गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समाज, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, गोरखा समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। राजनयिकों ने अनुच्छेद 370 हटने में देरी, इसे हटाने के लिए अपनाए गए तरीके के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी राय ली। प्रतिनिधिमंडलों में शामिल जम्मू वासियों ने नई व्यवस्था से आए बदलाव के साथ अपनी उम्मीदों के बारे में भी राजनयिकों को बताया। इस दौरान कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता से वंचित रखे जाने का मुद्दा भी उठा। बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान एडवोकेट अभिनव शर्मा ने अनुच्छेद 370 हटने में देरी के लिए कांग्रेस व अब्दुल्ला परिवार को जिम्मेदार ठहराया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अभिनव ने कहा कि उन्होंने राजनयिकों को बताया कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए आतंकवाद को शह दे रहा है। वह खूनखराबा करने के लिए आतंवादियों की घुसपैठ को शह देने के साथ गोलाबारी कर रहा है।

जम्मू में शुक्रवार को जगटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के कैंप में भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर का परंपरागत तरीके से स्वागत करतीं कश्मीरी पंडित समुदाय की महिलाएं। जागरण

वियतनाम के राजनयिक बोले, सामान्य होते हालात शुभ संकेत

विदेशी राजनयिकों के दल में शामिल वियतनाम के राजनयिक फेम साहन चाऊ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होना एक शुभ संकेत है। जम्मू के एक होटल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से भेंट करने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में राजनयिक ने कहा कि यहां के लोग नई व्यवस्था और मौजूदा हालात से खुश हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बेहतर शासन, पारदर्शिता, भेदभाव को दूर करने की दिशा में हो रहे कार्यों के प्रति भी संतोष जताया।

कश्मीरी पंडितों ने राजनयिकों को सुनाया दर्द

नवीन नवाज, जम्मू

'यह रैन बसेरा है, घर नहीं। हमारा सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, हमारा वजूद मिटाया गया है। आप ही बताएं, जब किसी पेड़ को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो क्या होगा। इसलिए हम अपनी जड़ों (कश्मीर) में लौटना चाहते हैं। यह तभी होगा जब किसी के दिल में इस्लामिक आतंकवाद का खौफ न हो, रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड हो। हमें रिलीफ नहीं चाहिए। सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वादी में किसी एक ही जगह बसाया जाए, ताकि हम सुरक्षा-शांति और विश्वास की सांस ले सकें।'

यह बात जम्मू-कश्मीर के हालात का जायजा लेने आए 15 देशों के राजनयिकों के समक्ष एक विस्थापित कश्मीरी पंडित ने जरूर कही, लेकिन यह दर्द तीन दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रत्येक नागरिक का था। दो दिवसीय दौरे पर आए राजनयिक शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले जम्मू से करीब 17 किलोमीटर दूर जगटी माइग्रेंट कॉलोनी पहुंचे। इस कॉलोनी में लगभग 4200 विस्थापित कश्मीरी पंडित और कुछ विस्थापित सिख परिवार रहते हैं।

राजनयिक कड़ी सुरक्षा के बीच करीब तीन बजे कड़ी जगटी पहुंचे, लेकिन सुबह सवेरे ही बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जगटी स्कूल के पास बने एक सामुदायिक भवन में जमा होने लगे थे। इस बीच, दो आदमी हाथों में पोस्टर लिए सामुदायिक भवन के बाहर पहुंच गए। उन्हें अधिकारियों ने भीतर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बाहर अपने पोस्टरों संग खड़े रहेंगे और बताएंगे कि जेएनयू या मुंबई में फ्री कश्मीर का पोस्टर झूठा है, असली पोस्टर हमारा है। पोस्टर लिए ये दोनों व्यक्ति बाप-बेटा थे। रविंद्र कौल ने कहा कि हम उसी त्राल के रहने वाले हैं, जिसे आतंकियों की नर्सरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विस्थापन का कारण सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद है। जब तक यह खत्म नहीं होगा, कश्मीरी पंडित कश्मीर में बेखौफ नहीं बस सकते।

35 मिनट तक चली बैठक : जगटी में लगभग 35 मिनट तक विस्थापित कश्मीरियों और विदेशी मेहमानों के बीच बैठक चली। इस दौरान किसी ने मेमोरेंडम सौंपा तो किसी ने पूछा कि आखिर आज तक कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं सुना गया।

बोले, हमारा जातीय नरसंहार हुआ : पनुन कश्मीर के भूषण लाल ने राजनयिकों से कहा कि हमारा विस्थापन-पलायन नहीं हुआ है, हमारा जातीय नरसंहार, जिनोसाइड हुआ है। हमारी पूरी पहचान, संस्कृति को नष्ट किया गया है। हमारी हालत तभी सुधरेगी जब रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड हो। यहां कोई नहीं रहना चाहता, सभी वापस कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन एक ही जगह बसने की ख्वाहिश के साथ। इस्लामिक आतंकवाद को रोकना होगा।

पहली बार लगा दुनिया को कश्मीरी पंडितों की फिक्र है : बैठक स्थल से बाहर निकल रहे एल कौल ने कहा कि पहली बार अहसास हुआ है कि दुनिया को कश्मीरी पंडितों की कुछ फिक्र है। इससे लगता है कि अब कश्मीर मुद्दे पर होने वाली हर बातचीत में कश्मीरी पंडितों की आवाज भी शामिल होगी। पहले तो कश्मीर पर जब भी बात हुई, आजादी और जिहाद का नारा देने वालों की बात हुई, उन्हें ही कश्मीर का प्रतिनिधि समझा गया, जबकि हकीकत तो यह है कि असली कश्मीर तो कश्मीरी पंडितों से ही है।

न्यूज गैलरी

बरेली में दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को फांसी की सजा

बरेली : 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दो दोषियों मुरारी लाल व उमाकांत को कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सुनाई। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ हुई यह घटना दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी ज्यादा वीभत्स थी। दोनों दोषियों पर चार लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बरेली के एक गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की बच्ची 29 जनवरी, 2016 को दोपहर में मां के साथ खेत पर गई थी। कुछ देर बाद वहां से घर जाने के लिए निकली, मगर पहुंची नहीं। बाद में घर पहुंची मां को वह नहीं मिली तो तलाश शुरू की। उसी शाम को 4 बजे कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची की लाश खेत में पड़ी है। घटनास्थल पर पुलिस को बच्ची का क्षत-विक्षत शव मिला था। (जासं)

पाक सेना की फायरिंग में दो पोर्टरों की मौत, तीन घायल

पुंछ : जम्मू-कश्मीर के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलाबारी में दो पोर्टरों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शुक्रवार सुबह सेना के साथ काम कर रहे पोर्टर अग्रिम चौकी पर तैनात जवानों के लिए सामान लेकर जा रहे थे। इसी बीच जोरदार धमाका हुआ और पोर्टर मुहम्मद असलम, मुहम्मद अलताफ की मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य मुहम्मद शौकत, मुहम्मद सलीम व नवाज अहमद घायल हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ भेज दिया गया। वहीं, सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्यों ने भारतीय क्षेत्र में आइईडी लगाई थी। पोर्टर इसकी ही चपेट में आ गए। हालांकि सेना पाक सेना की फायरिंग के कारण ही दो पोर्टरों की मौत बता रही है। वहीं, एसएसपी पुंछ रमेश कुमार अंगराल का कहना है कि मारे गए पोर्टर में से एक का शव क्षतविक्षत है। (जासं)

मप्र में चाइनीज मांझे से बच्चे के गले की नस कटी, मौत

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानुपर में चाइनीज मांझे से गले की नस कटने के कारण एक बालक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर टाकली निवासी निखिल (9) अपने पिता जितेंद्र चौहान के साथ बाइक से फोपनार के समीप ग्राम खारी में लगे मेले में जा रहा था। वह बाइक पर आगे बैठा था। फोपनार रोड पर पेड़ से अटके चाइनीज मांझे के कारण उसके गले की नस कट गई। (नईदुनिया)

सिब्बल ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सूचनाओं का प्रवाह बहाल होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में सूचनाओं का प्रवाह बहाल हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने शीर्ष कोर्ट की इस व्यवस्था को मार्गदर्शक बताया जिसमें कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही वैचारिक मतभेद दबाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आजादी मिलेगी।

सुरजेवाला ने कहा-मोदी सरकार की गैरकानूनी गतिविधि को दोहरा झटका कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री यह याद रखें कि देश संविधान के आगे नतमस्तक है न कि उनके आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की गैरकानूनी गतिविधि को बड़ा झटका दिया है।

चिदंबरम बोले-लोकतंत्र में धारा 144 का अनियंत्रित इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं : पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनिश्चितकाल तक इंटरनेट प्रतिबंध और धारा 144 का अनियंत्रित इस्तेमाल लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है।' इससे सरकार को सीख लेनी चाहिए।

कश्मीर को लेकर लोगों के मन में था संदेह : जयराम रमेश : पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कश्मीर की हालत को लेकर लोगों के मन में संदेह था। पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू थी, इंटरनेट, संचार बंद था, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

फैसले को लेकर ट्विटर पर आई संदेशों की बाढ़

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर बाढ़ आ गई। एक यूजर ने ट्वीट किया, 'कोर्ट द्वारा कश्मीर में इंटरनेट का अधिकार बताने को आप सांस लेने के अधिकार की तरह देख सकते हैं। आप पांच महीने से आक्सीजन से वंचित हैं, इसलिए एक सप्ताह और रुकिए। यह देखेंगे कि रोगियों को आक्सीजन की जरूरत है, फिर हम फैसला लेंगे।'

आहिस्ता-आहिस्ता आसान होती गई जिंदगी

विवेक सिंह, जम्मू

▶ ज्यों-ज्यों हालात सुधरते गए पाबंदियां लगातार कम होती गईं

▶ आशंका थी कि देश विरोधी तत्व इंटरनेट को बना सकते हैं हथियार

केंद्र सरकार ने देश में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले तत्वों पर शिकंजा क्या कसा, कश्मीर के सुधरते हालात के साथ जिंदगी आसान होती गई। दुष्प्रचार से हालात बिगाड़ने की साजिशें रचने वालों के मंसूबे सिरे नहीं चढ़ पाए। यही वजह है कि अब वहां अमन की मीठी धुन बज रही है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से 12 घंटे पहले पूरे मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। घाटी में फोन सेवाएं भी ठप कर दी गईं। एहतियात के तौर पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं और पत्थरबाजों को हिरासत में ले लिया गया। पाक परस्त एजेंडा चलाने वालों ने खूब हो-हल्ला मचाया पर इन फैसलों और सुरक्षाबलों की तैनाती का असर घाटी में साफ दिखा।

फोन पर इंटरनेट बंद रहा तो भड़काऊ बयान देने वालों की बोलती बंद हो गई। इसके बाद जैसे-जैसे हालात बेहतर होते गए, वैसे-वैसे कश्मीर में पाबंदियां भी कम होती गई। पहले दो सप्ताह में ही पाबंदियों में ढील देनी शुरू हो गई।

पोस्टपेड और एसएमएस सेवा हो चुकी है शुरू : 72 दिनों बाद प्रशासन ने गत वर्ष 14 अक्टूबर को कश्मीर में बीएसएनएल ने पोस्ट पेड मोबाइल सेवा शुरू कर दी। नए साल का तोहफा देते हुए प्रशासन ने 1 जनवरी 2020 को पोस्ट पेड मोबाइल पर एसएमएस सेवा शुरू हो गई। इसके साथ 80 सरकारी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में ब्रांडबैंड सेवा भी शुरू कर दी गई।

शांत रहा लद्दाख : ऐसे में लेह व कारगिल में मोबाइल व ब्राडबैंड सेवाएं जारी रही। लेह में मोबाइल पर इंटरनेट सेवा भी लगातार जारी रही। ऐसे में हालात सामान्य बनाने के लिए प्रशासन ने जल्दबाजी से बचते हुए फूंक-फूंक कर कदम रखे।

आतंकी गतिविधियों में 30 फीसद कमी

इंटरनेट पर प्रतिबंध से शरारती तत्वों को दिशा देने वाले खुद दिशाहीन हो गए। राष्ट्र विरोधी इंटरनेट के जरिए सुरक्षाबलों के ऑपरेशन पर बाधा पहुंचाते थे ओर भीड़ को हिंसक कर आतंकियों को भागने में मदद करते थे। इंटरनेट बंद होने से इस सब के साथ ही पथराव भी लगभग रुक गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि बेहतर हो रहे हालात में आतंकवादी गतिविधियों में 30 फीसद कमी आई है। वहीं, आतंकी बनने के मामलों में भी कमी आई है।

युवाओं को दी गई थी सुविधा

इंटरनेट पर रोक से युवाओं, आम लोगों का भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए भी प्रबंध किए गए। कश्मीर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर 100 से ज्यादा इंटरनेट टच प्वाइंट स्थापित किए गए। कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर बसीर अहमद खान ने बताया कि सुविधा केंद्रों में डेढ़ लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है।

सुरक्षाबलों में भी कटौती

हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को हटाना आरंभ कर दिया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश से पूर्व प्रदेश में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षाबलों की 72 कंपनियां वापस लौट चुकी हैं।

राम माधव ने कहा, जम्मू-कश्मीर में अधिकांश राजनेता रिहा किए गए

हैदराबाद, प्रेट्र : अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर के नेताओं में से अधिकांश रिहा किए जा चुके हैं। भाजपा महासचिव राम माधव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

भाजपा महासचिव ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम से इतर बातचीत में कहा, 'अधिकांश नेता अब रिहा हो गए हैं। उनमें से करीब 20-25 अभी भी हिरासत में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी इस महीने के आखिर तक या अगले कुछ सप्ताह में रिहा हो जाएंगे।' उनसे पूछा गया था कि हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को सामान्य गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति कब तक दी जाएगी। राम माधव ने कहा, 'इंटरनेट पर रोक धीरे-धीरे खत्म की जा रही है और जल्दी ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सेवा पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। एसएमएस समेत मोबाइल सेवा अब पूरी तरह संचालन में है और मुझे भरोसा है कि जल्दी ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट सेवा भी बहाल हो जाएगी।'

विदेशी राजदूतों के दौरे के बारे में भाजपा महासचिव ने कहा कि दुनिया को घाटी की वास्तविक स्थिति के बारे में संदेश देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था।

ठंड से जमे पानी, कोल्ड ड्रिंक और अंडे, दिल्ली भी कांपी

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ठंड का कहर एकबार फिर बढ़ने लगा है। इसके चलते लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हिमाचल प्रदेश में हो रही है। यहां केलंग में ठंड से तापमान इतना गिर गया कि बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स और अंडे तक जम गए। वहीं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के चलते परेशानी बनी हुई। पहाड़ों बर्फबारी होने से दिल्ली में भी ठंड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को धूप खिलने के बावजूद शीत लहर ने ठिठुरन का एहसास कराया। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं, जबकि रविवार को हल्की बारिश हो सकती है।

हिमाचल में दो दिन से धूप चमकने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात से 198 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। पाइपें जाम होने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर पानी जमने से पाइप फट गए हैं। वहीं, पांच राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 835 सड़कें बंद हैं। ऊपरी क्षेत्रों में 3342 विद्युत ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, 13 जनवरी और 16 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है।

केलंग में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड : लाहुल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में शुक्रवार को सीजन का सबसे कम -17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जिले के अधिकतर हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। आलम यह है कि पेय पदार्थ, तेल और यहां तक कि अंडे तक बर्फ बन गए हैं। ऐसे में जिले के लोगों को खाने-पीने की चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। लाहुल स्पीति में इस बार ठंड का 12 साल पहले का रिकॉर्ड टूटा है।

जम्मू-कश्मीर में कल से फिर बर्फबारी व बारिश के आसार : राज्य में दो दिनों से खिली धूप के बावजूद तापमान सामान्य से नीचे ही चल रहा है। रविवार देर शाम से उच्चपहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस बीच शुक्रवार को लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 20.2 डिग्री सेल्सियस जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ में थमे वाहनों के पहिए। समर नेगी

उत्तराखंड में हिमपात से पर्यटन को मिलेगी सौगात

इस बार भी पहाड़ों में हुए माकूल हिमपात ने पर्यटन व्यवसायियों की मुराद पूरी कर दी है। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी समेत निकटवर्ती पर्यटक स्थलों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। जानकारों के अनुसार पर्यटन व्यवसाय पर इस बर्फबारी का असर लंबे समय दिखेगा। बर्फ में ट्रैकिंग करने वालों के साथ ही स्नो बाइकिंग और स्कीइंग के लिए भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा।

पुलिस ने शुरू की जांच, दर्ज होंगे डॉ. सैजल के बयान

जागरण संवाददाता, मंडी

▶ सैजल को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना निंदनीय, आरोपितों पर हो कार्रवाई

▶ जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस अधिकारी ने विधायक विनोद कुमार से फोन पर की बातचीत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल और नाचन के विधायक विनोद कुमार को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा की शिकायत पर मंडी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉ. राजीव सैजल व विधायक विनोद कुमार के बयान कलमबद्ध करने का निर्णय लिया है। मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विधायक विनोद कुमार से फोन पर बात की है।

अपने शिकायत पत्र में दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के संयोजक चमन राही और वाल्मीकि समाज सुधार समिति के संस्थापक चंद्रवीर कागरा ने इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपितों के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। बकौल चमन राही, मंदिर में प्रवेश से रोकने पर डॉ. राजीव सैजल नहीं पूरे दलित समाज का अपमान हुआ है। छुआछूत और भेदभाव की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो प्रशासन इसके लिए आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे।

मामला छुपाने पर उठे सवाल : मंदिर में प्रवेश न करने देने की बात विधानसभा के विशेष सत्र में उठाने पर चर्चा में आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल व नाचन हलके के विधायक विनोद कुमार मंदिर का नाम बताने से क्यों कतरा रहे हैं। डेढ़ साल तक इस दर्द को क्यों दबा कर रखा, लोगों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

> शिकायत मिली है। इसकी जांच होगी। मामले की तह तक जाने के लिए डॉ. राजीव सैजल व विधायक विनोद कुमार के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे।
> -गुरदेव शर्मा, पुलिस अधीक्षक मंडी

जागरण विशेष

नदी किनारे बसे गांव ने तालाबों से दी सूखे को मात

गांव में तालाबनुमा गड्ढे किए तैयार और नदी के पानी से किया लबालब, अब नहीं सूखती फसलें, नदी के किनारे बसे होने के बावजूद पानी को तरसते थे किसान, गांव के युवाओं ने मिलजुलकर निकाला समाधान

संदीप तिवारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का बगदई गांव। यह गांव बगदई नामक नदी के किनारे बसा है, इसीलिए नाम भी बगदई है। लेकिन यहां के किसान पानी को तरसते थे। नहर आदि न होने के कारण नदी का पानी खेतों के काम नहीं आ पाता था। गांव के युवाओं ने मिलजुलकर समाधान खोजा। खेतों के किनारे तालाबनुमा कुछ गड्ढे तैयार कर नदी के पानी से इन्हें लबालब कर दिया। अब यहां के खेत सूखे से मुक्त हो गए हैं। गांव वाले खरीफ और रबी की फसलें ले रहे हैं, पलायन थम गया है।

पानी की का रोना रोने के बजाय इन ग्रामीण युवकों ने उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करने की जो जुगत भिड़ाई, वह प्रेरक है। राजधानी रायपुर से 95 किमी दूर स्थित बगदई नदी के किनारे बसे इस गांव के किसान सूखे की मार हर साल झेलते थे। इनके खेत तो बीमार हो ही रहे थे, लोग भी पलायन को बाध्य हो रहे थे। ऐसे में गांव के युवाओं ने सोचा कि क्यों न सभी मिलकर खेतों को हरा-भरा करने के लिए बगदई नदी के पानी को खेतों के लिए सहेजें।

इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से युवाओं ने खेतों के किनारे छोटे-बड़े गड्ढे खोदे, ठीक तालाब की तरह के, और इन्हें भरने के लिए नदी से गड्ढों तक नालियां भी बनाईं। अब गर्मियों में नदी भले ही सूख जाती है पर यहां बने तालाबनुमा ये गड्ढे सालभर भरे रहते हैं। इससे न सिर्फ खरीफ बल्कि रबी की फसल भी किसान आसानी से लेने लगे हैं। कुलमिलाकर यह कि हालात अब पूरी तरह बदल गए हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति में हो के सुधार को सहज देखा जा सकता है।

700 की आबादी वाले गांव की किस्मत पलटने में बस एक महीने का समय और श्रमदान लगा। करीब दो साल पहले युवाओं की टोली ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक महीने के भीतर बिना किसी सरकारी मदद के इस युक्ति को अंजाम दिया। ग्रामवासी चेतन पटेल, महादेव निषाद, सुखलाल यादव, खेलन निर्मलकर, रिंकू पटेल, महावीर निषाद और बाला बताते हैं कि पंचायत और ग्रामवासियों की मदद से गड्ढे तैयार किए गए। सभी ने मिलकर श्रमदान किया। इन गड्ढों में भरे जल का इस्तेमाल मछली पालन के लिए भी हो रहा है। गांव का महिला स्व सहायता समूह मछली पालन के लिए काम कर रहा है। अच्छी बात यह कि गांव के इर्दगिर्द भूजल स्तर भी बढ़ा है। सिंचाई के साथ-साथ गांव के ट्यूबवेल, कुएं आदि भी अब गर्मियों में सूखते नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ में बगदई नदी के किनारे बसे गांव में बनाए गए तालाब पर मौजूद गांव के युवक। नईदुनिया

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

सॉल्वर गैंग का सरगना अरविंद राणा मेरठ से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ

▶ दिल्ली में चल रही फायर सर्विस भर्ती में कर रहा था सेंधमारी

▶ एसएससी, रेलवे भर्ती का पेपर भी लीक करा चुका अरविंद राणा

उप्र एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के सरगना नकल माफिया अरविंद राणा उर्फ गुरुजी को गुरुवार रात मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। 25 हजार के इनामी अरविंद को दिल्ली में चल रही फायर सर्विस भर्ती में सेंधमारी के लिए जाते समय दबोच लिया। फायर सर्विस का पेपर लीक करा भर्ती कराने के एवज में वह 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों से चार-चार लाख रुपये वसूल चुका है। बता दें अरविंद राणा ने सात साल पहले मुजफ्फरनगर में सरेंडर किया था। जमानत के बाद उसने बिहार के युवकों को साथ जोड़कर सॉल्वर गैंग बनाया था। यह गैंग प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती कराने के एवज में मोटी रकम वसूलता था।

एसटीएफ के डिप्टी एसपी बृजेश सिंह ने मेरठ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली जाते समय अरविंद राणा को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। शामली जिले के बझेड़ी गांव का मूल निवासी आरोपित इन दिनों मेरठ में रह रहा था। उसके कब्जे से दिल्ली क्राइम ब्रांच के दो नोटिस, मोबाइल व आइ-20 कार बरामद की है। अरविंद पिछले 15 साल से पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों को भर्ती करा रहा था।

2018 की पुलिस आरक्षी भर्ती के बाद वह वांछित था। 2013 में भी अरविंद लखनऊ में एसएससी परीक्षा का पेपर लीक कराकर 50 युवकों को भर्ती करा चुका है। उसके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी वर्ष दिल्ली एसएससी परीक्षा का पेपर लीक कराने का मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ था। 2013 में ही रेलवे भर्ती का पेपर भी लीक कराया था।

दैनिक जागरण
शिखर पर हमेशा जगह होती है

उच्च शिक्षा के अराजक केंद्र

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए प्रारंभिक तथ्यों से यदि कुछ रेखांकित हो रहा है तो यही कि दोनों पक्षों के छात्र किसी ने किसी रूप में हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। चूंकि अभी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई और उसकी ओर से नकाबधारी तत्वों को बेनकाब किया जाना भी शेष है इसलिए किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। दिल्ली पुलिस को न केवल जल्द से जल्द अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, बल्कि हिंसा में लिप्त तत्वों के खिलाफ ऐसे पुख्ता सुबूत भी जुटाने होंगे जिससे अराजक तत्वों को दंड का भागीदार बनाया जा सके। उसे यह काम प्राथमिकता के आधार पर इसलिए करना होगा, क्योंकि यदि उसने जेएनयू परिसर की हिंसक गतिविधियों पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की होती तो शायद जो स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था। यह अच्छा नहीं हुआ कि पुलिस न तो तब हरकत में आई जब जेएनयू में रजिस्ट्रेशन कराने गए छात्रों को पीटने के साथ वहां इंटरनेट बाधित किया जा रहा था और न ही तब जब वहां नकाबधारी तत्व घुसकर उत्पात मचा रहे थे। दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में तत्परता का परिचय देना चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दल पुलिस की अधूरी जांच के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने से बाज आएं।

यह ठीक है कि जेएनयू एक नामचीन विश्वविद्यालय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि परस्पर विरोधी दल उसे अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लें। जेएनयू के अशांत और उपद्रव ग्रस्त रहने की एक बड़ी वजह राजनीतिक दलों की दखलंदाजी है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मानव संसाधन विकास मंत्री यह कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वे तो राजनीति के अड्डे बन चुके हैं। यदि विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे बने रहे तो फिर वहां वैसा कुछ होता ही रहेगा जैसा जेएनयू में हुआ। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र हैं न कि राजनीति की नई खेप तैयार करने के कारखाने। समझना कठिन है कि छात्र संगठनों को विश्वविद्यालयों में बेलगाम होने की इजाजत क्यों मिली हुई है? जेएनयू सरीखे विश्वविद्यालयों में कई छात्र पढ़ने के नाम पर न केवल नेतागीरी करते हैं, बल्कि शिक्षा से इतर मसलों पर हंगामा भी करते हैं? इससे भी खराब बात यह है कि वे विश्वविद्यालय को अपनी निजी जागीर समझने लगते हैं। इसी मुगालते के कारण जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं बाधित करने की हिमाकत की। यह खुली गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी गुंडागर्दी को केवल पुलिस के भरोसे नहीं रोका जा सकता।

नकेल जरूरी

झारखंड मानव तस्करी के लिए पूरे देश में बदनाम रहा है। गांव की गरीब बेटियों को मानव तस्कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर या बेहतर जीवन का सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर वे शहर पहुंचकर इनके मकड़जाल में फंसती चली जाती हैं। पिछले दिनों रांची की बेटी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले जाकर शादी के लिए बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया। गरीब घर की बेटी को शादी का झांसा देकर बुलंदशहर ले जाया गया और वहां उसे 80 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। इस दौरान युवती को साड़ी पहनने एवं मुस्कुराते रहने के लिए मजबूर किया गया। जब इस मामले को लेकर हंगामा हुआ तो बात पुलिस तक पहुंची और दो महिला समेत सात लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसा ही गुमला की दो नाबालिग किशोरियों के साथ हुआ। उन्हें काम दिलाने का झांसा देकर पंजाब ले जाकर देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया गया। किसी तरह जब किशोरी इन दलालों के चंगुल से भागी तो मामले का खुलासा हुआ। झारखंड में ऐसे सैकड़ों मामले हैं, जहां गरीब परिवार के बच्चे इन मानव तस्करों के निशाने पर रहते हैं। गरीब अपने परिवार के भरण पोषण और अंधकार में डूबे भविष्य से निकलने की जद्दोजहद में इन मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था भी जिम्मेदार है। पुलिस के ढीले रवैये के कारण इन मानव तस्करों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है या इतने विलंब से होती है कि न्याय नहीं मिल पाता है। जरूरत है पुलिसिंग को मजबूत करने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई करने की, जिससे ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो और लोगों का न्याय पर विश्वास जगे। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी और अधिक संसाधन एवं शक्ति दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे वह बेहतर तरीके से बच्चों के पुनर्वास के लिए काम कर सके।

झारखंड जैसे राज्य में मानव तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत है पुलिसिंग को मजबूत करने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई करने की, जिससे ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो और लोगों का न्याय पर विश्वास जगे

दोराहे पर मुस्लिम समाज

कैप्टन आर विक्रम सिंह

आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से भारतीय मुस्लिमों के हित कैसे प्रभावित होते हैं?

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों और खासकर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया चकित करने वाली है। यह अचानक नहीं हुआ। इसे समझने के लिए वापस 1946-47 में जाना होगा। 1946 में 14 अगस्त को जिन्ना द्वारा घोषित 'डायरेक्ट एक्शन' भारत विभाजन की पूर्वपीठिका था। कांग्रेस के पास इस पूर्व नियोजित नरसंहार का मुकाबला कर पाने का कोई हथियार नहीं था। गांधी जी का एक लाइन का अहिंसक फॉर्मूला यह था कि वध होने के लिए स्वयं को हत्यारों के सम्मुख प्रस्तुत कर दो। असहायता की यह विरासत आजाद भारत की नीति बनी और हमने इसके परिणाम भी देखे। विभाजन के दंगों में सदियों से प्यार- मुहब्बत से साथ रहने वालों ने तलवारें निकालीं, एक दूसरे की गर्दनें काटीं, औरतें लूटीं। सैकड़ों साल साथ रहने के बाद भी जो घृणा थी वह एक ही झटके में सतह पर आ गई।

कांग्रेस के नेताओं, खासकर पंडित नेहरू, मौलाना आजाद आदि ने पाकिस्तान जाने वाले बहुत से लोगों के शिविरों में भ्रमण कर उन्हें भारत में रुकने को प्रेरित किया कि हम सेक्युलर देश हैं। यह हिंदुओं का देश नहीं है। वे जानते थे कि अगर यह हिंदुओं का देश बन गया तो नेतृत्व वीर सावरकर जैसों के हाथ चला जाएगा और उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। उधर पाकिस्तान में हिंदुओं को रोक लेने वाला कोई नहीं था। आज हिंदू आबादी वहां 23 प्रतिशत से घटकर 1.5-2 प्रतिशत रह गई है, जबकि भारत में मुस्लिम आबादी जो आजादी के वक्त की 9.8 प्रतिशत थी अब 14-15 प्रतिशत हो चुकी है। पाकिस्तान के रास्ते से वापस लौट आने के बाद यहां के सुरक्षित माहौल में मुसलमानों से भारतीय अस्मिता से एकाकार हो जाने की हमारी अपेक्षा स्वाभाविक थी, लेकिन यदि मुसलमान सेक्युलर हो जाते तो उन्हें एक वोट बैंक बनाए रखने की योजना बेकार हो जाती। इसलिए जरूरी था कि उनकी अलग बस्तियां हों, अलग पहचान और अलग संस्थान हों। हिंदुओं के समान मुसलमानों की समस्याएं शिक्षा, रोजगार की ही तो हैं। भारतीय मुसलमान भी तो मलेशिया, इंडोनेशिया के मुसलमानों की मलय या इंडोनेशियाई संस्कृति के समान अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व कर सकते थे। वे भी इंडोनेशिया की तरह राम को अपना पूर्वज या महापुरुष मान सकते थे, पर उन्हें अरबों, तुर्कों से जोड़ा गया। उन्हें राम मंदिर के विरुद्ध मुकदमे में भी खड़ा कर दिया गया।

दरअसल मुस्लिम समाज को भारत की संस्कृति-सभ्यता से जोड़े रखने के प्रयास ही नहीं हुए। राजनीतिक आवश्यकताओं ने साझा संस्कृति ही नहीं विकसित होने दी। आजादी से पहले इस अलगाव के लिए हम अंग्रेज सरकार की नीतियों, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद, अल्लामा इकबाल, मुहम्मद अली जिन्ना को दोषी मान सकते थे, लेकिन आजादी के बाद तो नेहरू भारत के नए भाग्य विधाता थे। अंग्रेजों की जेल में भारत और विश्व इतिहास पर पुस्तकें लिखते नेहरू को उन वतनपरस्त मुसलमानों जैसे हाकिम खां सूर, इब्राहिम गार्दी जो महाराणा और मराठों के सेनाओं में लड़ते हुए शहीद हुए थे, की याद नहीं थी। दारा शिकोह को उन्होंने शायद पढ़ा नहीं था। हमारी संस्कृति-साहित्य का हिस्सा बन चुके कबीर, रसखान, बाबा फरीद, दादू को उन्होंने कितना जाना, वे ही बता सकते थे।

पता नहीं उन्होंने अब्दुर्रहीम खानखाना का यह दोहा 'जेहि रज मुनि पतनी तरी, सो ढूंढत गजराज' कभी सुना था या नहीं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज में भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने के लिए कुछ नहीं किया। वे चाहते तो भारतीय मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय एकता की सबसे मजबूत कड़ी बना सकते थे। वे कह सकते थे कि अगर भारत टूटा तो सोचो, तुम कितने टुकड़ों में होगे। हर खंडित टुकड़े में भारत की विरासत तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं होगी, लेकिन नहीं, मुसलमान भारतीयता से दूर सिर्फ वोट बैंक बनता गया। बड़ी-बड़ी समस्याओं को विरासत में हमारे हवाले कर नेहरू जी इतिहास पटल से विदा हुए। उनके आगे पीछे वह पीढ़ी भी विदा हो गई जिसे भारत की फिक्र थी। अब शुद्ध रूप से सत्ता आकांक्षियों का राज आ गया था।

भारतीय मुस्लिम समाज राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में अपनी मूल समस्या पाकिस्तान को लेकर एक स्पष्ट अवधारणा विकसित ही नहीं कर सका, दुविधाग्रस्त ही रहा। रफी अहमद किदवई जैसे नेता दोबारा नहीं आए। आरिफ मुहम्मद खान एक बड़ी संभावना थे, लेकिन परिस्थितियां ही नहीं बनीं। वे सवाल जिन्हें और उलझाकर नेहरू जी रुखसत हो गए थे, उनके समाधान का सिलसिला अब जाकर शुरू हुआ।

अनुच्छेद 370 व्यतीत इतिहास का भाग हो चुका है। तीन तलाक का हटना असंभव लगता था, पर वह संभव हुआ। आतंकवाद से रक्तरंजित मजबूर भारत आज सशक्त भारत है। आशा थी कि अनुच्छेद 370 के हटने का भारतीय मुस्लिम समाज स्वागत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का हित और भारतीय मुस्लिम समाज का हित अलग-अलग कैसे हो सकता है? हम अपनी अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर गलत रास्तों पर चले हैं। भारत का मुसलमान आज भी दोराहे पर खड़ा है। आज जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शनों का दौर चल रहा है तो संदेह होता है कि कहीं कोई दूसरा एजेंडा इन्हें प्रभावित तो नहीं कर रहा है। आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से भारतीय मुस्लिमों के हित कैसे प्रभावित होते हैं? संविधान की रक्षा का दम भरते प्रदर्शनकारियों से सीधा सवाल है कि क्या संविधान ने देश को धर्मशाला बनाया है? यदि वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या भारत के नागरिक बन जाएं तो 1946 में यूपी, बिहार, बंगाल के मुसलमानों को जिन्ना के साथ खड़े होकर पाकिस्तान मांगने की जरूरत क्या थी?

हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या वह धार्मिक एजेंडा है जिसके तहत हजारों रोहिंग्या म्यांमार से लाकर जम्मू में बसा दिए गए। करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश के नागरिक बनने की फिराक में हैं। बहुत से पाकिस्तानी यहां आकर गुम हो गए हैं। समस्या भारतीय मुसलमान नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो उन्हें भारतीयता से अलगाव की प्रेरणा देती है। समस्या आज भी शिलादित्य जैसे वे लोग हैं जो खानवा के युद्ध के दौरान अपने हजारों सैनिकों के साथ राणा सांगा को छोड़कर बाबर से जा मिलते हैं। रात में किले के फाटक खोल देने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। अफसोस होगा अगर कल के इतिहासकार यह कहेंगे कि सदियों से भारत का अटूट हिस्सा रहे एक तबके ने अपनी क्षुद्र सोच के चलते सशक्त होते भारत में अपनी हिस्सेदारी गंवा दी।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

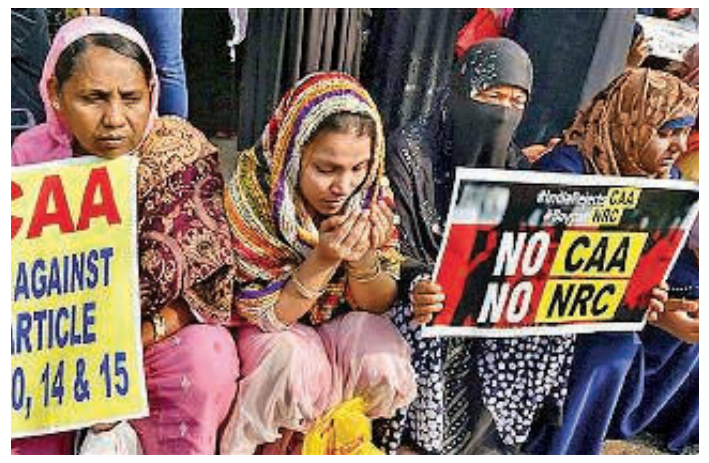

संकट की ओर ले जाता अतिवादी आग्रह

गिरीश्वर मिश्र

अन्य विश्वविद्यालयों से अलग जेएनयू के भीतर एक निहायत निजी किस्म की संस्कृति विकसित हुई है

यह अत्यंत खेदजनक है कि भारत के कई प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में शिक्षारत भारत की युवा प्रतिभाओं का बहुमूल्य समय ऐसे प्रदर्शनों और गतिविधियों में बीत रहा है जो अनुत्पादक तो हैं ही, विध्वंसक भी साबित हो रही हैं। दिल्ली के विख्यात शिक्षा संस्थान जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब तीन महीने तक पढ़ाई-लिखाई का काम लगभग ठप रहने के बाद अब हालात कुछ सामान्य होते दिख रहे हैं। इन महीनों में जेएनयू के कई भवनों में विरोध के लिए लामबंद हुए छात्रों द्वारा ताला बंद कर शिक्षक और विद्यार्थियों का प्रवेश जबरन रोक दिया गया। नामांकन करने गए छात्रों के साथ मारपीट भी की गई और नामांकन बाधित करने के लिए सर्वर कक्ष में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद छात्रों के साथ मारपीट की गई। यह मारपीट नकाबधारियों के एक गुट की ओर से की गई जिसमें कई छात्र घायल हुए। चूंकि घायल छात्र दोनों पक्षों के हैं इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि किसने किसे निशाना बनाया? इस उपद्रव के लिए जो भी जिम्मेदार हो, इस तरह की हिंसक घटनाएं किसी भी शिक्षा प्रेमी के लिए दुखदायी हैं। इससे अधिक दुखदायी यह है कि राजनीतिक दखल शिक्षाजगत की चुनौतियों को और जटिल बनाता जा रहा है। यह स्थिति उच्च शिक्षा की प्रणाली पर पुनर्विचार की अपेक्षा करती है। शिक्षा केंद्रों को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है।

जेएनयू के मामले में यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भौतिक, व्यावहारिक और बौद्धिक दृष्टि से इसका एक खास तरह का चरित्र निर्मित हुआ है। यह उच्च शिक्षा के इतिहास में सरकार द्वारा एक विशेष तरह के सेक्युलर शिक्षा केंद्र के निर्माण, पोषण और विकास का एक अद्भुत नमूना है। अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों से अलग जेएनयू में चहारदीवारी के भीतर एक निहायत निजी किस्म की संस्कृति विकसित होती रही, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसी संप्रदाय से कम नहीं आंकी जा सकती। इसकी छाया सब ओर फैल रही थी, भले ही वह अनोखे और एकांगी वैचारिक लेंस से लैस हो। इसका वैचारिक रुझान जग जाहिर है। इसके आख्यानों और मिथकों की शृंखला प्रचारित होती रही। यह सब करने के लिए परिसर में प्रोत्साहन और सुविधाएं भी उदारभाव से उपलब्ध होती रहीं। ये सुविधाएं इस तरह उपलब्ध होती रहीं कि आंतरिक व्यवस्था और अव्यवस्था की रूढ़ियां अनदेखी ही चलती रहीं और उनके चलते रहने के कारण वे प्रामाणिक और उपयुक्त भी ठहराई जाती रहीं। यहां अनेक बौद्धिक विमर्शों का उदय हुआ। भारत के इतिहास, संस्कृति, प्रजातंत्र और अर्थव्यवस्था सबकी एक विशेष तरह की व्याख्याएं दी गईं, जो सीमित तथ्यों को लेकर चल रही थीं। बौद्धिक जगत में वैचारिक स्थापनाओं में विविधता होना लाजमी होती है। उनका आकलन, विश्लेषण और आलोचना सब कुछ होता है। अकादमिक जगत में यह सब जायज ठहरता है, परंतु समाज और देश भौतिक सत्ता मात्र नहीं होते और न उनका ज्ञान ही शाश्वत होता है। चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ दें तो शेष ज्ञान देश और काल के सापेक्ष ही होता है इसलिए ज्ञान के सामान्य क्षेत्र में समग्र को देखने की चेष्टा होनी चाहिए। ज्ञान पाने में उदारता और सहिष्णुता, दोनों ही आवश्यक हैं। संविधान में स्वीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी यही कहती है कि संवाद द्वारा पारस्परिक समझ विकसित की जाए। किसी भी तरह का अतिवादी आग्रह संकट की ओर ले जाता है। अधूरे ज्ञान के चलते विचार और ज्ञान की देशज परंपराएं खारिज करने और उनकी अवांछित व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी जी का विचार था कि हम अपनी ही जमीन पर खड़े रहें और खिड़कियां खुली रखें ताकि बाहरी हवाएं इस तरह आती-जाती रहें कि हमें उखाड़ न फेंके।

राजनीतिक दलों के वर्चस्व की लड़ाई में जेएनयू की व्यवस्था को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के कई बडे नेता मुखर उपस्थिति दर्ज कराकर स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय प्रश्न बनाकर पेश कर रहे हैं। सामान्यतः शिक्षा केंद्रों का राजनीतिक उपयोग अल्पकालिक फायदे पहुंचाता लग सकता है, लेकिन यह ज्ञान अर्जित करने की परंपरा को खंडित करने के लिए पर्याप्त होता है।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अमंगल से मंगल

अमंगल अर्थात मनुष्य के जीवन की वह स्थिति जिसमें मनुष्य अपने जीवन के किसी एक काल खंड में किसी विशेष संकट में पड़कर अपना अपकर्ष देख रहा होता है। जैसे कि वह किसी विशेष दुर्घटना का शिकार हुआ हो अथवा किसी ऐसी स्थिति में फंस गया हो, जिसके कारण उसे अपयश का भागीदार बनना पड़ा हो। इसके विपरीत मनुष्य-जीवन की मांगलिक स्थिति वह होती है, जब वह स्वस्थ, संपन्न और यशस्वी होकर जीवन जीता है तथा किसी भी विशेष अघटित घटना का शिकार नहीं बनता।

इस तरह उसके जीवन की ये दोनों स्थितियां दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी होती हैं और प्रायः कभी भी एक-दूसरे को उत्पन्न करने की वजह नहीं बनतीं। हमारी परंपरा में अनेक उदाहरण हैं जिनसे यह देखने को मिल जाता है कि यद्यपि व्यक्ति के जीवन में घटित तो हुआ था अमंगल, किंतु उसका जो परिणाम मिला, वह मंगलदायक हुआ। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वे शिकार करने के लिए वन की ओर गए। बहुत समय तक जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तब वे वहीं जंगल में ही कुछ क्षण विश्राम करने के लिए एक सरोवर के पास बैठ गए। कुछ ही देर में उन्हें लगा कि उस सरोवर के किनारे पेड़ की आड़ में जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो तो उन्होंने बिना देखे ही उस पर अपना बाण चला दिया। शिकार घायल हुआ और उसने अपना दम तोड़ दिया, पर यह क्या, शिकार कोई जानवर न होकर शांतनु और ज्ञानवानी का पुत्र श्रवणकुमार था।

श्रवण के माता-पिता अंधे थे। उन्होंने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो व्यथित होकर राजा दशरथ को श्राप दिया कि राजन! जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। तब तक राजा पुत्रहीन थे, किंतु बाद में श्रीराम उन्हें पुत्र रूप में मिले और उनका जीवन मांगलिक हो गया।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

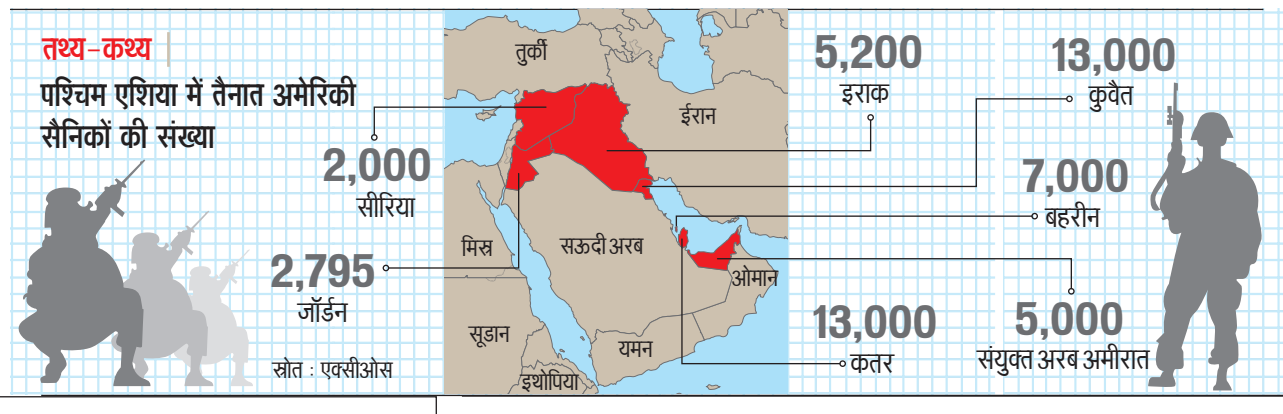

जीवन से हारने के बढ़ते मामले

अनीश कुमार

मौजूदा दौर में जिंदगी की आपाधापी और अकेलापन जीना मुश्किल ही नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी भी छीन रहे हैं

जाने-माने चेहरे कुशल पंजाबी की आत्महत्या ने फिर यह सवाल उठाया है कि युवाओं का सफल, सेहतमंद और खुशहाल दिखती जिंदगी से आखिर मोहभंग क्यों हो रहा है? चिंतनीय है कि जाने-माने चेहरे ही आम युवा भी छोटी-छोटी परेशानियों से होकर जिंदगी से मुंह मोड़ रहे हैं। हौसले और सकारात्मकता की उम्र में उनका मन थका-हारा सा है। ऐसी घटनाओं पर गौर करें तो सामने आता है कि खुदकुशी करने वाले अधिकतर युवाओं का जीवन कोई दयनीय स्थिति में नहीं था। कहना गलत नहीं होगा कि आज के युवाओं में भावनात्मक टूटन और पलायन की प्रवृत्ति तेजी बढ़ रही है। जीवन से जूझने की क्षमता कम हो रही है।

करियर, तरक्की, सब कुछ जुटा लेने की भागमभाग और बिखरते रिश्तों से जुड़ी बातें ही उन्हें कमजोर कर रही हैं, जबकि इन सभी समस्याओं का हल मेहनत या संवाद से निकाला जा सकता है। सोच में ठहराव लाकर इस आपाधापी से बाहर आने की राह तलाशी जा सकती है। अफसोस कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसकी बड़ी वजह इस पीढ़ी का पारिवारिक-सामाजिक माहौल से कट जाना भी है। आभासी दुनिया की बनावटी सक्रियता-लोकप्रियता और बाहरी दुनिया को दिखने वाले दंभ को छोड़ दें तो अधिकतर युवा आत्मकेंद्रित और अकेलेपन की जिंदगी ही जी रहे हैं। बीते एक दशक में युवाओं के वैवाहिक रिश्तों में भी बिखराव की स्थितियां बन गई हैं। सामंजस्य और समझ की कमी पति और पत्नी दोनों में देखने को मिल रही है। कारण चाहे जो भी हो देश में बढ़ते खुदकुशी के आंकड़ों को देखते हुए परामर्श केंद्र, अपनों का साथ-सहयोग और हालातों से लड़ने का मनोबल ही काम आ सकता है। वर्ष 2016 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आत्महत्या दर वैश्विक दर से अधिक है। हमारे यहां आत्महत्या की दर प्रति एक लाख व्यक्ति पर 16.5 लोग हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रति एक लाख में 10.5 लोग खुदकुशी करते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी-2016 के मुताबिक साल 2016 में सर्वाधिक आत्महत्याएं हमारे देश में ही हुई थीं। दुनियाभर में 8,17,000 लोगों ने खुदकुशी की थी, जबकि अकेले भारत में यह संख्या 2,30,314 थी। ऐसे में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जीवन से हारने के बढ़ते आंकड़ों की इस आपातकालीन स्थिति से निकलने के लिए प्रयास किए जाने जरूरी हैं। मौजूदा दौर में जिंदगी की आपाधापी, अकेलापन और अवसाद जीना मुश्किल ही नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी भी छीन रहे हैं।

हर परिवार और समग्र समाज के लिए इन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। अवसाद और अकेलेपन जैसी समस्याओं पर खुलकर विमर्श किए जाने की दरकार है। बिगड़ते-बिखरते रिश्तों को लेकर सार्थक संवाद किए जाने की जरूरत है, ताकि देश के आम युवा हों या चर्चित चेहरे, जीवन के खात्मे की नहीं, बल्कि खुशहाल और हौसले से भरी राह चुनें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

फिल्मी कलाकारों का राष्ट्रवाद

रशीद किदवई ने अपने लेख 'फिल्म कलाकार भी नागरिक हैं' में राजनीति से जुड़े फिल्मी इतिहास को प्रस्तुत करते हुए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनकी आने वाली विवादित फिल्म 'छपाक' का बचाव करने की एक लचर कोशिश की है। माना कि सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को अपनी दोहरी जिंदगी जीते हुए रील लाइफ से इतर रियल लाइफ में आम आदमी की तरह समाज के साथ जीना पड़ता है। बेशक यह बात दीपिका पादुकोण पर भी लागू होती है जो अपनी रियल लाइफ में बिना सोचे समझे जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनकर भारतीय समाज में तिरस्कृत हो रही हैं। विगत में भी फिल्मी कलाकारों का राजनीति से जुड़ाव रहा है, लेकिन अपवाद को छोड़कर सभी फिल्मी कलाकार भारतीयता के भाव से देश की एकता और अखंडता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनकी फिल्मों के संदर्भ भी समाज सापेक्ष और देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के इस आचरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

pandeyvp1960@gmail.com

ऐसा हो लेखक

पिछले दिनों विश्व (दिल्ली) पुस्तक मेला गई थी। पुस्तकों की भीड़ में जहां अधिकतर लेखक अपनी-अपनी किताबों के प्रचार में व्यस्त दिख रहे थे, वहीं एक लेखक जो बच्चों के ट्रस्ट के पास खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे और मेरे ही सामने उन्होंने 2000 रुपये उस ट्रस्ट को दान कर दिया। जहां अधिकतर लेखक उस ओर जा नहीं रहे थे, वहीं जब मैं उस लेखक से मिली, तो जान पाई कि वह उपन्यास, वेंटिलेटर इश्क, के लेखक हैं और उनके उपन्यास से उन्हें जो भी रॉयल्टी प्राप्त होती है, वह गरीब बच्चों की शिक्षा, शहीद परिवारों को दान देकर देश के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। देश को ऐसे लेखकों की सख्त जरूरत है, जो सोशल मीडिया से निकलकर देश के बच्चों व शहीद परिवारों के लिए थोड़ी-सी सही, परंतु मदद कर रहे हैं।

biharinumber1@yahoo.com

शिक्षक बड़ा परामर्शदाता

अगले माह से बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ हो रहा है। प्रतियोगिता के इस दौर में बालकों व उनके अभिभावकों का तनावयुक्त होना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए सरकारें भी अपने स्तर पर परामर्श केंद्रों की व्यवस्था करती हैं, ताकि परीक्षार्थी तनावमुक्त रहकर परीक्षा दे सकें। लेकिन माता- पिता अथवा अभिभावकों के अलावा उनके अध्यापक उनके बहुत करीब होते हैं, जो कार्य परामर्श केंद्रों में बैठे परामर्शदाता नहीं कर सकते वह कार्य एक अध्यापक आसानी से कर लेता है। क्योंकि अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बालक की केस स्टडी से वाकिफ होता है। देखा जाए तो वह उनके लिए सबसे बड़ा परामर्शदाता होता है।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर गुरुग्राम

सीएए का विरोध

विरोध के नाम पर सड़कों पर हिंसा करने का चलन बन गया है। यह चिंता की बात है। तोड़फोड़ से देश की संपत्ति व जानमाल को नुकसान होता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का मकसद अवैध घुसपैठियों को रोकना है, क्योंकि दुनिया का कोई देश घुसपैठियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर इसका विरोध क्यों? वैसे भी आम जनता इसके विरोध में नहीं है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इनके पीछे भी कुछ राजनीतिक दल हैं, जो उनको उकसा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि विरोध करने वालों से सीधे बात करे और उनकी शंकाओं का समाधान करे।

murarimishra580@gmail.com

विपक्ष का विरोध

दैनिक जागरण के 9 जनवरी के अंक में प्रकाशित प्रदीप सिंह का लेख, नफरत की राजनीति में झुलसता विपक्ष, पढ़ा। लेखक की बात सही है कि विपक्ष के नेता झुंझलाहट में हैं और नागरिकता संशोधन कानून केवल बहाना है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं। भाजपा पिछले करीब छह साल से सत्ता में है और बहुत से फैसले गलत भी लिए हैं, लेकिन उनपर विपक्ष का ध्यान ही नहीं है।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1.27 लाख दुष्कर्म संबंधी मामले देश की विभिन्न अदालतों में अनेक चरणों में लंबित हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार।

आजकल

हांगकांग में 'रिवोल्यूशन नाउ' की उठती आवाज

'लिबरेट हांगकांग, रिवोल्यूशन नाउ', हांगकांग में हजारों प्रदर्शनकारियों ने विक्टोरिया हार्बर, लॉन क्वाइ फोंग और मोंग कोक सहित कई स्थानों पर इसी नारे के साथ वर्ष 2020 का स्वागत किया, कुछ तोड़-फोड़ की और बैरीकेड में आग लगाई। क्या इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीते छह माह से अशांत रहा हांगकांग न केवल आंदोलन को जारी रखना चाहता है, बल्कि क्रांति की मनोदशा तक पहुंच चुका है? ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि हांगकांग में लोकतंत्र जीतेगा या चीन? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज

प्रतीकात्मक फोटो

डॉ. रहीस सिंह
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

इसमें कोई संशय नहीं कि हांगकांग की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के विषय में स्पष्ट रूप से यह सोच रही है कि यदि वह अपने अधिकारों के लिए आज नहीं खड़ी हुई तो फिर वह सदैव के लिए अपने अधिकारों को खो देगी। लेकिन इसके विपरीत 'सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टिरिस्टक्स' के प्रणेता, संरक्षक और चीन के शासक यह मानकर चल रहे होंगे कि यदि हांगकांग के लोग अपने उद्देश्यों में सफल हो गए तो फिर यह स्थिति तिब्बत और शिनझियांग में भी देखने को मिल सकती है। यानी दोनों ही अस्तित्व के संकट से गुजरते दिख रहे हैं। तो क्या यह संघर्ष अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगा या फिर चीन इतिहास को दोहराने जैसा कदम उठाएगा?

हांगकांग अपने मूल्यों पर आगे बढ़ना चाहता है जिसमें स्वतंत्रता है, शासन की एक अलग व्यवस्था है, मूल्य हैं और लोकतंत्र है, जबकि दूसरी तरफ चीन है जहां एकदलीय व्यवस्था है और आजीवन राष्ट्रपति पद पर रह सकने वाला एक व्यक्ति। इसी व्यक्ति के इर्दगिर्द देश की व्यवस्था का तानाबाना व सभी प्रकार की ताकतें निहित हैं। खास बात यह है कि यह व्यक्ति इतना ताकतवर होने के बावजूद स्वतंत्रता, लोकतंत्र एवं बहुलतावाद से डरता है। यही वजह है कि छह माह पहले जून महीने में एक विधेयक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन आज हांगकांग की स्वतंत्रता का आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन की मूल वैचारिकी और प्रयास अब चीन को हांगकांग से बाहर निकालने का है। इसके अंश आप क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर की रात तक के आंदोलन में देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि क्रिसमस के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने चीन की सीमा से लगे शहर श्योंग सुईं में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर चीनी व्यवसायियों के वहां से चले जाने की मांग की और शक्ति प्रदर्शन किया। यही स्थिति 31 दिसंबर की रात को हांगकांग के कई शहरों में दिखी जहां 'लिबरेट हांगकांग, लिबरेशन नाउ' के नारे लगा रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले छह माह के दौरान पुलिस ने करीब सात हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यह संख्या वास्तविक होगी, ऐसी संभावना कम है।

हांगकांग के प्रदर्शन को शेष दुनिया ने किस तरह से देखा है, इस पर टिप्पणी करना फिलहाल समझ से परे है। कारण यह है कि आंदोलनकारियों के समर्थन में ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से बयान तो दिए गए हैं, लेकिन वे खुलकर उनके समर्थन में नहीं आए हैं। हालांकि इस सीमित समर्थन के बाद भी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। शी चिनफिंग का कहना था कि तिब्बत, ताइवान, हांगकांग और शिनजियांग को लेकर अमेरिकी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को खराब कर रही हैं। हालांकि यह प्रतीकात्मक समर्थन ही माना जाएगा, जिस पर शी चिनफिंग ने प्रतिक्रिया जाहिर की। सही अर्थों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु लड़ाई हांगकांग अकेले लड़ रहा है। हां, हांगकांग में कुछ के हाथों में अमेरिकी झंडे अवश्य दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया गया है। अब इनके मायने क्या हैं, इसे अर्थमेटिकल तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

करीब से देखें तो दुनिया के सर्वाधिक सक्रिय आर्थिक केंद्रों में से एक हांगकांग पिछले काफी समय से न थमा हुआ है और न ही चल रहा है। हांगकांग की सड़कों पर रोजाना हजारों लोगों की ऐसी भीड़ रहती है जो विभिन्न प्रकार के नारों के साथ सुबह से शाम तक सक्रिय रहते हैं। यह आंदोलन शुरू तो उस बिल के खिलाफ हुआ जो हांगकांग की हैसियत और हांगकांग के निवासियों की आजादी को खतरे में डाल सकता था। लेकिन धीरे-धीरे यह चीन विरोधी आंदोलन में बदल गया। दरअसल यह विवाद प्रत्यर्पण कानून में लाए गए बदलाव को लेकर उत्पन्न हुआ। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि व्यक्ति अपराध करके हांगकांग भाग जाता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेज दिया जाएगा। यह कानून चीन को उन देशों के संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने और उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देगा, जिनके साथ हांगकांग के समझौते नहीं हैं। जबकि अभी तक हांगकांग ब्रिटिशकालीन कॉमन लॉ सिस्टम से काम कर रहा था और उसकी 1997 से पहले जिन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि थी उन्हीं को ही वह वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करता था जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। इस बिल के कानून में बदल जाने से ऐसे अपराधियों को चीन को प्रत्यर्पित करना पड़ता। इससे हांगकांग के लोगों में यह भय पनपा कि चीन इस कानून के जरिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा है, हांगकांग से प्राप्त कर लेगा और इस तरह से हांगकांग के लोगों के सभी राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उनका यह डर वाजिब भी था, क्योंकि नया कानून स्वतंत्र, लोकतांत्रिक दौर का अंत कर देता और हांगकांग के नियंत्रण में न होकर चीन के नियंत्रण में चला जाता। हालांकि अब बिल वापस हो चुका है, लेकिन इसने हांगकांग को इस तरह से उद्वेलित और आक्रोशित किया है कि हांगकांग अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर उतर आया।

अब चीन की कोशिश होगी कि 'एक देश-दो व्यवस्था' (वन कंट्री-टू सिस्टम) को समाप्त कर 'वन कंट्री, वन सिस्टम' में तब्दील कर दिया जाए। जबकि 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को हस्तांतरित करते समय यह गारंटी हासिल की थी कि चीन 'वन कंट्री-टू सिस्टम' के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी अवस्था को बनाए रखेगा। अब सवाल यह उठता है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे 20 वर्ष भी क्यों नहीं निभा पाई। आखिर वजह क्या है कि 2014 में हांगकांग में लोकतंत्रवादियों ने 'अंब्रेला मूवमेंट' क्यों चलाया? यह आंदोलन 79 दिनों तक क्यों चला? 2019 में लोग पुनः क्यों सड़कों पर उतर आए? चीन ने 1997 के समझौते का उल्लंघन क्यों किया? आखिर बीजिंग हांगकांग से क्यों डर गया?

सवाल यह उठता है कि हांगकांग और बीजिंग के बीच टकराव केवल एक बिल को लेकर ही था या फिर उसके कोई अन्य और व्यापक आयाम थे? दरअसल यह बात केवल हांगकांग की नहीं है, बल्कि ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग जैसे उन राज्यों की भी है जिन पर बीजिंग ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है या फिर वह उस पर अपना दावा करता है। ताइवान कहता है कि उसका चीन के साथ सहयोग करते हुए अपना विशिष्ट चरित्र और पहचान बनाए रखना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है और अपना संसदीय लोकतंत्र बनाए रखना चाहता है। इसे लेकर ताइवान में सनफ्लावर मूवमेंट भी हुआ था और वह सफल भी रहा था। लेकिन शी चिनफिंग ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। जो ताइवान की हैसियत है, शायद वही हांगकांग के लोग चाहते हैं।

बहरहाल अब दुनिया के अग्रणी लोकतंत्रों को एक बार यह यकीन दिलाना होगा कि वे स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं और अब खड़े होंगे, क्योंकि हांगकांग की स्वतंत्रता खतरे में है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हांगकांग के लोग ही पराजित नहीं होंगे, बल्कि लोकतंत्र भी हार जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो चीन को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। कुछ अध्ययनों की मानें तो इस समय चीन तमाम क्षेत्रीय एवं सामाजिक अंतर-विभाजनों और द्वंद्वों से गुजर रहा है। यही चीन को हांगकांग में निर्णायक कार्रवाई करने से रोक रहे हैं और हांगकांग के लोगों को रिवोल्यूशन नाउ की मनःस्थिति तक ले जा रहे हैं।

वैधानिक हैसियत मांग रहे हांगकांग के निवासी

हालांकि अभी हांगकांग के लोग सिर्फ उस वैधानिक हैसियत की मांग कर रहे हैं जिसका वादा कभी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किया था। यानी वे अपने उन लोकतांत्रिक अधिकारों को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं जो उन्हें 'वन कंट्री-टू नेशन' व्यवस्था के तहत मिले थे। लेकिन इससे आगे बढ़कर हांगकांग के लोग लोकतंत्र का वह मॉडल चाहते हैं जो पश्चिम में है यानी जो ताइवान में है, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका में है। उन्हें चीन के मॉडल में कोई रुचि नहीं है और ना ही वे ताउम्र बने राष्ट्रपति में कोई रुचि रखते हैं। यह बात राष्ट्रपति शी चिनफिंग को भलीभांति मालूम है। लेकिन बीजिंग सख्त रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। वह हांगकांग को ऐसा अवसर प्रदान करना नहीं चाहता जिससे उसे स्वतंत्र होने का एहसास हो सके। लेकिन क्या बीजिंग उन्हें ऐसा करने देगा? नहीं, क्योंकि बीजिंग कभी नहीं चाहेगा कि हांगकांग एक ऐसी हैसियत प्राप्त कर जाए जो आने वाले समय में चीन के एक दलीय शासन के लिए मजबूत चुनौती बने।

बीजिंग की कोशिश रहेगी कि वह हांगकांग के आंदोलन का चीन के खिलाफ सुनियोजित विद्रोह बनाकर पेश करने में सफल हो जाए। बीजिंग के अधिकारी शुरू से ही आंदोलनकारियों के कार्यों को आतंकी गतिविधियों के रूप में पेश करने की कोशिश करते रहे हैं, हालांकि वे सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजिंग किस निष्कर्ष तक पहुंचा है। क्या वह यह मानकर चल रहा है कि हांगकांग के संघर्ष पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लेगा? या यह मान कर चल रहा है कि बाहरी विश्व का समर्थन ना हासिल कर पाने से एक दिन हांगकांग का आंदोलन शक्तिहीन होकर स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा न हुआ तो? तो शायद बीजिंग हांगकांग पर सैन्य कार्रवाई कर दे।

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि बीजिंग अपनी प्रकृति के विपरीत हांगकांग आंदोलन को जारी रखने दे रहा है, तो इसके पीछे कोई दबाव अवश्य होगा। फिर चाहे वह अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के कारण अमेरिका और चीन की चौड़ी होती खाई हो या फिर चीनी अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती से उपजे कुछ संकोच। शायद यही वजह है कि चीन अभी तक हांगकांग में नियुक्त अपने अधिकारियों और अदालतों के जरिये ही आंदोलन को दबाने की युक्ति अपना रहा है। लेकिन वह आगे भी इसी राह पर चलेगा, यह जरूरी नहीं है। इसलिए हांगकांग के लोगों को अपने लोकतांत्रिक आंदोलन को वैश्विक लोकतांत्रिक वैचारिकी तथा विश्व में चलने वाले तमाम लोकतांत्रिक आंदोलनों और स्थापित राजनीतिक दलों से जोड़ लेना चाहिए। अन्यथा बीजिंग किसी भी समय, किसी भी हद तक जाने का निर्णय ले सकता है।

खरी-खरी

विमोचन के धंधे में स्कोप

अंशुमाली रस्तोगी

वे वरिष्ठ कवि ही नहीं, वरिष्ठ विमोचक भी हैं। अब तक अनेक पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं। इन दिनों वे दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला में व्यस्त हैं। शायद ही वहां ऐसा कोई बुक स्टॉल हो, जहां वे विमोचक न बने हों। पुस्तक चाहे कैसी भी हो, किसी की हो, कहीं से भी छपी हो, ये सब वे नहीं देखते। उनका काम विमोचन करना है, सो कर देते हैं। पर यह सब मुफ्त में नहीं करते। पैसे लेते हैं। इसमें गलत भी क्या है, आखिर 'प्रोफेशनल विमोचक' हैं, कोई नत्थू-खैरे विमोचक नहीं!

सुना है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी विमोचिका बना डाला है। लेकिन वे सिर्फ लेखिकाओं की पुस्तकों का ही विमोचन करती हैं। वैसे, पुस्तक विमोचन का काम बुरा नहीं। अगर अच्छे लेखक न भी बन पाओ, तो कामयाब विमोचक तो बन ही सकते हो। विमोचन की लाइन में बहुत स्कोप है। न तो यहां किसी प्रकाशक की चिरौरी करने की जरूरत है, न लेखक के आगे गिड़गिड़ाने की। पुस्तक छपी है तो अगला झक मारकर विमोचन करवाएगा ही। यह ठीक वैसा ही है, जैसे किसी के घर बच्चा हो तो वह मुंडन करवाने नाई के पास आएगा ही।

पुस्तक मेला में तो विमोचनों की बाढ़-सी आई हुई है। एक ही विमोचक एक दिन में कई पुस्तकों को विमोचित कर रहा है। लोग जितना लेखक को न पूछ रहे, उससे कहीं ज्यादा विमोचक की आवभगत में लगे हैं। विमोचक के आगे क्या आलोचक और क्या समीक्षक, सब फेल हैं। वे जितना साल भर में कविताएं लिखकर न कमा पाते, उससे कहीं ज्यादा दस दिनों के पुस्तक मेले से कमा लेते हैं।

कभी-कभी सोचता हूं, और कभी-कभी क्या उनके धंधे की बरकत देख तो अब रोज ही सोच रहा हूं कि...

चाह बड़ी है दिल में,
पुस्तकों का मैं विमोचक बन जाऊं।
मेला जाकर पुस्तक का मोचन,
जेब का लोचन कर आऊं।
मुझे बैठा देना हे प्रकाशक,
उस मेले में कुर्सी टेक,
जिस मेले में विमोचित होने,
आएं पैसे वाले लेखक अनेक।

कल से घर में ही मैं भी पुस्तक विमोचन की प्रैक्टिस शुरू करूंगा। पुस्तक का रैपर कैसे फाड़ना है, भीड़ में कैमरे वाले को कैसे ढूंढना है, कैसे उसकी ओर मुस्कुराना है।

ट्वीट-ट्वीट

जो चोर-चोर चिल्ला रही थी वही चोर निकली। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा में नौ आरोपियों की पहचान की। दो एबीवीपी के और सात लेफ्ट के। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष भी थी हिंसा में शामिल।
जितेंदर शर्मा@capt_ivane

जेएनयू में बवाल पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस से साफ है कि चाहे लेफ्ट हो या राइट... सबने मिलकर शिक्षा के संस्थान को जंग का मैदान बना डाला। अफसोस जेएनयू प्रशासन कई दिनों से चल रहे विवाद को इतने बड़े झगड़े में तब्दील होते नहीं देख पाया।
निशांत चतुर्वेदी@nishantchat

जब से तेरा मजा चखा हिंदी, इश्क तेरे में खो गया है 'थरूर'। अब तो इंग्लिश भी सोचती होगी, ये तो हिंदी का हो गया है 'थरूर'।।
शशि थरूर@ShashiTharoor

एनसीआरबी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करने वालों की संख्या किसानों की आत्महत्या की तादाद से भी ज्यादा है। वर्ष 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की, जबकि इसी साल खेती-किसानी से जुड़े 10,349 लोगों ने परेशान होकर मौत को गले लगा लिया।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असर दिखाएगा?

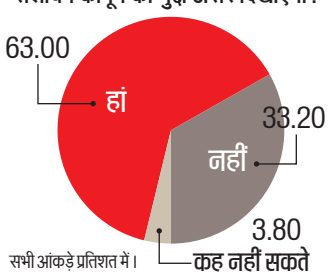

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या छात्रों के एक वर्ग द्वारा जेएनयू के कुलपति को हटाने की मांग उचित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आजादी किस चीज से चहिए तुमको यार,
बदला-बदला आजकल क्यों लगता व्यवहार?
क्यों लगता व्यवहार अगर आए हो पढ़ने,
तो क्यों लेकर लट्ठ लगे आपस में लड़ने!
चल करके इस राह मिलेगी बस बर्बादी,
पा जाओगे आप कैरियर से आजादी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

सियासत नहीं, हरियाली की बात कीजिए

मनोज झा
स्थानीय संपादक, बिहार

चुनाव और राजनीति से इतर प्रदेश के चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस शिद्दत से पूरे प्रदेश में जल, जीवन और हरियाली के मिशन पर निकले हैं, वह सियासी पंडितों को थोड़ा चौंका जरूर रहा है। चौंकने की वजहें भी हैं। पहले महाराष्ट्र और फिर झारखंड में विपक्षी एकता ने जिस तरह राजनीतिक गलियारे में चीजों को उलट-पलट दिया, उससे तमाम निगाहें दिल्ली और बिहार पर आ टिकी हैं। बिहार का चुनावी परिदृश्य न सिर्फ रोचक दिखाई दे रहा है, बल्कि अभी चुनाव की घोषणा तक कई सियासी समीकरण बन और बिगड़ भी सकते हैं। विपक्ष में खींचतान शुरू होता भी दिखाई देने लगा है। ऐसे माहौल में यदि प्रदेश का मुखिया दूर पानी, पेड़ और जीवन बचाने-संवारने की बात करे तो निश्चित रूप से यह थोड़ा लीक से हटकर तो है ही।

दरअसल, सियासत के नए तौर-तरीकों में आज वह सब कुछ शुमार नहीं है, जो नीतीश कुमार या उनकी तरह के अन्य नेता सोचते या करते हैं। राजनीति को समाज सुधार का माध्यम बनाने के मामले में बाकी राजनेताओं से नीतीश अलग दिखाई देते हैं। वह पिछले पंद्रह साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं आता कि उन्होंने इस दौरान कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अभियान चलाया हो। इसके उलट, उन्होंने ऐसे कई कदम जरूर उठाए हैं, जिनकी बदौलत सामाजिक क्षेत्र में बदलाव दिखाई देने लगा है।

शराबबंदी, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उनकी ठोस पहल ने प्रदेश में आधी आबादी की तस्वीर को एक हद तक संवारने का प्रयास किया है। इसी प्रकार दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर शासन के कड़े रुख ने कुछ नहीं तो कम से कम माहौल जरूर बदला है। अब ताजा उदाहरण जल, जीवन और हरियाली मिशन का है। इसमें कोई शक नहीं कि पानी और हरियाली पर आज संकट है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे देश में वोटबैंक सहेजने या चुनाव जीतने के लिए ये मुद्दे अनुत्पादक ही कहे जाएंगे। यही कारण है कि पर्यावरण पर लाख संकट के बावजूद शायद ही कोई राजनेता हो, जिनकी सभा में पानी और हरियाली जैसे विषयों की गूंज सुनाई पड़ती हो। नीतीश पिछले करीब तीन माह से पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर इस मिशन का प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत अब तक दर्जनों गांव गए, वहां जलाशयों की सेहत देखी और खुद के साथ-साथ लोगों को भी इनके संरक्षण का संकल्प दिलाया।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन करते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

सवाल है कि क्या नीतीश प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर बेफिक्र हैं। बेफिक्र न भी हों, लेकिन पर्यावरण जैसे गैर-सियासी सवालों से जूझकर वह साहस तो दिखा ही रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार जैसे सियासी परिदृश्य वाले प्रदेश में पानी और हरियाली चुनाव के नैरेटिव नहीं बन सकते, बावजूद उनके प्रति बारंबार आसक्ति दिखाना यह बताता है कि इतिहास में ऐसी ही जिद और जुनून की बदौलत चीजें सुधरी हैं।

जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो फिलहाल यह स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार में नीतीश की अगुआई में एनडीए का विपक्ष के महागठबंधन से सीधा मुकाबला होगा। एनडीए में तस्वीर एक हद साफ है। फिलहाल किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं दिखाई देता है। दूसरी ओर, विपक्ष का कुनबा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से खुद की हौसला अफजाई तो जरूर कर सकता है, लेकिन वहां चीजें तय करने में कब महाभारत छिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। वहां खटपट सुनाई भी पड़ने लगी है। विपक्षी खेमे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी जैसे किरदार कब किस ओर पलट जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी कहां हैं और उनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, कोई नहीं जानता। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव किसके पक्ष में कितना जोर लगाएंगे, कुछ पता नहीं। क्या इस बात की अभी कोई गारंटी दे सकता है कि मांझी, सहनी या पप्पू जैसे नेता महागठबंधन के अगुआ के तौर पर तेजस्वी यादव को हंसी-खुशी स्वीकार कर लेंगे। फिर इस बात की कौन गारंटी लेगा कि इस बार सीटों को लेकर कांग्रेस और राजद में टूट जाने की हद तक खींचतान नहीं होगी। मतलब कि एनडीए के सामने विपक्ष कितना एकजुट रह पाएगा, इसका अंदाजा कम से कम इस समय तो नहीं ही लगाया जा सकता।

फिलहाल चुनाव की तैयारियों और गहमागहमी से दूर मुख्यमंत्री प्रदेश में पानी और हरियाली की अलख जगाने में लगे हुए हैं। कायदे की बात तो यह है कि इस मिशन को एक बार गैर-सियासी चश्मे से देखा जाए और पानी और हरियाली की चिंता से पूरे समाज को जोड़ा जाए।

उम्मीद

देर से आया एक दुरुस्त फैसला

इस समय देश भर में विविध स्तरों पर अदालतों में करीब साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इसमें भी करीब साठ हजार मामले तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं

कैलाश विश्नोई
अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख देने वाले निर्भया दुष्कर्म मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। इस जघन्य घटना के सात साल बाद बहुप्रतीक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक 22 जनवरी को सुबह सात बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दुष्कर्मियों व हत्यारों को फांसी दी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता- 1973 के तहत फॉर्म नंबर- 42 को डेथ वारंट या ब्लैक वारंट कहा जाता है। ये जारी होने के बाद ही किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है। हालांकि डेथ वारंट के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है।

यह संतोष का विषय है कि देर से ही सही निर्भया के दोषियों को फांसी की तारीख तय हो गई है। लेकिन देश में क्रिमिनल मामलों में फैसले में विलंब एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां क्राइम का मामला दर्ज किए जाने से लेकर अंतिम रूप से दोषी ठहराए जाने तक पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 16 वर्ष लग जाते हैं। कई बार तो छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े को लेकर दशकों तक मुकदमे चलते हैं। फौजदारी के मामलों में तो स्थिति और भी गंभीर है। हम अक्सर समाचारों में सुनते और पढ़ते हैं कि अपराध में मिलने वाली सजा से ज्यादा तो लोग फैसला आने के पहले ही सजा काट लेते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। हालत इतनी खराब है कि आपराधिक मामलों में आरोपी अपनी संभावित सजा से अधिक की मियाद जेल में ही पूरी कर लेता है और तब जाकर कहीं उनके मामले की सुनवाई हो पाती है। पीड़ितों के मामले में कुछ ऐसे संदर्भ भी रहे हैं जब आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 30 वर्ष तक का समय लगा, हालांकि तब तक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। न्याय-व्यवस्था की यह गति परेशान करने वाली है।

हाल में लोकसभा में सरकार ने बताया कि देश की निचली और जिला अदालतों में तीन करोड़ चौदह लाख मामले लंबित हैं। इनमें लगभग 18 लाख मामले दस साल से ज्यादा व 40 लाख मामले पांच साल से ज्यादा पुराने हैं। यदि केवल दुष्कर्म संबंधी मामलों की बात करें तो एनसीआरबी के वर्ष 2017 के आंकड़े बताते हैं कि देश में दुष्कर्म के कुल 1.27 लाख मामले अदालतों में विभिन्न चरणों में लंबित हैं। इससे जाहिर होता है कि भारत में न्यायिक विलंब की समस्या उत्तरोतर गंभीर होती जा रही है। वाकई यह बहुत चिंता की बात है।

न्याय में विलंब के कारण लोगों का न्याय से विश्वास उठने लगा है। अदालती प्रक्रिया तेज कर ही आम आदमी को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि संविधान में उसे न्याय का जो अधिकार मिला है, उसकी हिफाजत हर कीमत पर की जाएगी। न्याय में विलंब से अपराध करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं कि न्याय प्रक्रिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती या जब तक फैसला आएगा, स्थितियां बहुत बदल चुकी होंगी। कोर्ट में मामलों के पेंडिंग रहने से समाज में असंतोष बढ़ता है और न्याय के प्रति लोगों में आस्था कम होती है। बढ़ते अपराध और सामाजिक तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है। अत्यधिक देरी की वजह से कई बार आम जनता से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक प्रचलित कहावत है कि देर से मिला न्याय असल में न्याय देने से इन्कार के समान है, जबकि समय पर न्याय पाना हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में न्याय मिलने में देरी और सुनवाई की मंथर गति के बारे में गहन सोच-विचार करने की आवश्यकता है। न्याय पर लोगों का भरोसा रखने के लिए समय पर न्याय देने के प्रयास तेज करने होंगे। इसके लिए लंबित तमाम न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाना होगा।

अदालतों में आधारभूत ढांचे की कमी है। विभिन्न श्रेणियों में फास्ट ट्रैक सुनवाई से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि अदालतों में कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी है। ऐसे में पर्याप्त बजट आवंटन के साथ न्याय तंत्र की गति बढ़ाने के लिए इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की जरूरत है। भारत में भी सिंगापुर की तरह अदालतों में केस का समयबद्ध तरीके से निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंगापुर में कोर्ट में लगने वाले दिनों के हिसाब से वादी या प्रतिवादी से 'टैक्स' लिया जाता है जिससे कम दिनों में ही मुकदमा निपट सके। आज भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 17 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 30 वर्ष पहले इस अनुपात को बढ़ाकर प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश करने की सिफारिश की थी। इस अंतराल को भरने के लिए मौजूदा खाली पदों को भरने के साथ साथ जरूरत के मुताबिक न्यायाधीशों के नए पद सृजित करने की भी है।

प्रतीकात्मक फोटो।

हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने में बुरी तरह विफल रही है। ऐसे में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना मददगार सिद्ध हो सकती है। दुनिया के कई देशों जैसे इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 68 से 75 वर्ष के बीच है, जबकि अमेरिका में इसके लिए कोई आयु सीमा तय नहीं है। भारत में ही उच्च न्यायालयों के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है। जजों की भारी कमी से जूझ रही भारत की न्यायपालिका में जजों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ानी चाहिए ताकि मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सके।

359 मीटर की ऊंचाई पर है जम्मू-कश्मीर के चिनाब दरिया पर बन रहे पुल के दोनों छोर। इस पुल को विश्व का सबसे ऊंचा पुल बताया जा रहा है। इसके कामों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 11 जनवरी 2020

पंजाब

जल्द न्याय की उम्मीद

दुष्कर्म और हत्या के संगीन अपराधों से देश भर में जो भय व आक्रोश है उससे पंजाब भी अछूता नहीं है। इसलिए पंजाब में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए सात फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का देर से लिया गया दुरुस्त फैसला है। यह समय की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और न्याय के लिए समय लग रहा है। इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सूबे में दुष्कर्म और बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं के मामलों की जल्द सुनवाई हो सकेगी। ऐसा करना अब राज्य सरकारों के लिए लाजिमी भी हो गया है।

केंद्र सरकार ने गत वर्ष जुलाई में यौन और पोक्सो अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मुहिम छेड़ी थी, जिसमें देशभर में एक हजार से ज्यादा अदालतें बनाई जानी थीं। पंद्रह राज्यों ने इन अदालतों को बनाने की सहमति जताई थी। पंजाब में नए साल में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि इस साल में यह अदालतें आरंभ हो जाएंगी। यह सही है कि इससे कम से कम जिला एवं सत्र न्यायालय के स्तर पर दुष्कर्म के मामलों में जल्द न्याय हो सकेगा।

ऐसे मामलों में अंतिम न्याय होते-होते देर लग जाती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक अदालतें जिन्हें दोषी करार दे देती हैं, उन्हें ऊपर की अदालतों में अपील करने का पूरा अधिकार रहता है।

हालांकि सच यह भी है कि ऐसे मामलों में अंतिम न्याय होते-होते देर लग जाती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक अदालतें जिन्हें दोषी करार दे देती हैं, उन्हें ऊपर की अदालतों में अपील करने का पूरा अधिकार रहता है। यह सही है कि न्यायिक व्यवस्था के जरिये ही न्याय होना चाहिए। आरोपितों को खुद को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त मौका भी मिलना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था यही है, लेकिन ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई जल्दी होने के बाद भी वे कई वर्षों तक अंतिम न्याय तक लटके रहते हैं। जिस निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक, कठोर कानून, समय पर न्याय जैसी बातें देश में उठीं उसी कांड की अंतिम सुनवाई होते-होते सात साल हो गए हैं। इसलिए एक सवाल यह भी उठता है कि क्या फास्ट ट्रैक अदालतों के ही गठन मात्र से इस तरह के मामलों में बड़ा बदलाव हो सकेगा? जरूरत है कि फास्ट ट्रैक के बाद ऊपर के स्तर पर भी ऐसे मामलों का शीघ्रातिशीघ्र एवं प्राथमिकता पर निपटारा हो।

स्वतंत्र और समर्थ न्याय-प्रणाली किसी भी सभ्य समाज का आधार है। इसके बिना लोकतंत्र की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। न्याय पाने का अधिकार महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में एक है। हमारे संविधान में भी इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, परंतु लचर और लापरवाह दशा और दिशा के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था में तमाम खामियां घर कर गई हैं। एक बहुत प्रचलित कहावत है कि देर से मिला न्याय असल में न्याय देने से इन्कार के समान है। जाहिर है न्याय मिलने में हो रही देरी के बारे में गहन सोच-विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय पर होनेवाले, सही और सधे हुए न्यायिक फैसले न्यायपालिका में आम जन के भरोसे की पहली शर्त है।

बंगाल

विपक्ष की बैठक से ममता की मनाही

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में विपक्षी एकता को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झटका दे दिया है। हालांकि बीते कुछ समय से देश भर में अधिकांश विपक्षी दलों द्वारा जिस प्रकार से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मामले पर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और इसके व्यापक विरोध का अभियान चलाया जा रहा है, उसे देखते हुए इस बात का सहज अनुमान लगाया गया था कि इन दोनों मामलों पर जब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात होगी तो ममता बनर्जी निश्चित तौर पर उसकी अगुआई कर सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में विपक्षी एकता बिखरती दिख रही है। वैसे ममता बनर्जी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट करने के लिए सबसे पहले पत्र लिखा था, लेकिन अब वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 13 जनवरी को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में जाने से इन्कार कर रही हैं।

ममता बनर्जी के इस इन्कार के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि एनआरसी के विरोध में सबसे पहले दहाड़ लगाने वाली दीदी ने रास्ता बदल लिया? कहने को तो वह एनआरसी और सीएए के विरोध में सबसे ज्यादा मुखर हैं और बंगाल की सड़कों पर खूब नारे भी लगा रही हैं, लेकिन जब विपक्षी दलों के साथ सुर में सुर मिलाने का मौका आया

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल फोटो

तो उनकी आवाज बदल गई। अब वह अपने दम पर लड़ाई लड़ने का एलान कर रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस और वामदल दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। एनआरसी के विरोध में आवाज उठा रहे अन्य विपक्षी दलों को ममता का रवैया रास नहीं आ रहा है। विगत आठ जनवरी को जब वामपंथी श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल की थी तो ममता सरकार बंगाल में इसे विफल करने में जुटी रही। सरकार के पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बंगाल में कमजोर हो चुके वामपंथी संगठनों और कांग्रेस ने सफल आंदोलन का इतिहास रच दिया। कहीं ममता वामो-कांग्रेस के सफल आंदोलन से तो विचलित नहीं हो गई हैं या फिर वह

सीएए और एनआरसी पर देशव्यापी विरोध के लिए अनेक विपक्षी दलों द्वारा आयोजित बैठक में शामिल होने से ममता बनर्जी ने इन्कार कर दिया है।

एनआरसी और सीएए के विरोध का श्रेय किसी और को लेने नहीं देना चाहती हैं। इस संबंध में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर मिली-जुली लड़ाई में ममता शामिल हुईं तो विरोध का श्रेय कांग्रेस और वामो को भी मिलेगा। ममता सीएए और एनआरसी के विरोध में सुर में सुर मिलाने वाले एक खास तबके के बीच किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहती हैं। फिर तो सवाल उठना लाजिमी है कि दोहरा मापदंड कौन अपना रहा है।

इस मामले में मजेदार यह कि सोनिया की बैठक में जाने से ममता के इन्कार पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी खुशी जाहिर की है। उधर वामो विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती और कांग्रेस विधायक दल के नेता अब्दुल मन्नान ने दो टूक कह दिया है कि ममता तो भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करती हैं। उनका विरोध सिर्फ दिखावा मात्र है। ममता बनर्जी इन आरोपों पर जो चाहे तर्क चाहे दें, लेकिन निकट भविष्य में इन आरोपों को बल मिलना तय है। लोगों को यह कहने का मौका मिलेगा कि ममता बनर्जी विपक्ष के आंदोलन को कमजोर कर रही हैं।

उत्तराखंड

सेहत पर सुस्त रवैया

उत्तराखंड में स्वास्थ सुविधाओं को लेकर सरकार के दावों पर अंगुली उठ रही है। स्वाभाविक भी है, सेहत के मामले में राज्य सरकारें अभी तक जितने दावे करती आई हैं, वह धरातल पर कम ही नजर आए। अगर यूं कहें कि राज्य में कागजों में सेहत ज्यादा सुधार रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजधानी स्थित दून मेडिकल कॉलेज इसका उदाहरण है। यहां पर 11 महीनों से सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, लेकिन महकमा इस 'मर्ज' को दूर करने के प्रति कतई गंभीर नहीं दिख रहा है। जैसा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है उसके स्तर से नई मशीन की खरीद का प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया गया है, पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसे क्या कहा जाए, सेहत के प्रति स्वास्थ्य महकमे की बेरुखी या असंवेदनशीलता।

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून मेडिकल कॉलेज में न केवल शहर के, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। राज्य के पर्वतीय इलाकों में आए दिन होने वाली

प्रतीकात्मक

दुर्घटनाओं में जख्मी लोगों को भी इलाज के लिए यहीं लाया जाता है। ऐसे में सहज ही समझा जा सकता है दून मेडिकल कॉलेज में समुचित सुविधाएं कितनी जरूरी हैं। विडंबना यह कि मेडिकल कॉलेज की कामचलाऊ व्यवस्था पर निर्भरता बनी हुई है। कहने में हिचक नहीं कि महकमे के अफसरों और नीति नियंताओं की समझ में यह बात ठीक से बैठ नहीं पा रही है। अगर राजधानी के मेडिकल कॉलेज का यह हाल है तो राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में संचालित होने वाले सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? यह बताने की जरूरत नहीं है। इनमें अधिसंख्य अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। डॉक्टरों की तैनाती और संसाधनों के विस्तार को लेकर सरकार की ढुलमुल नीति मरीजों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा कि क्या नीति नियंता वाकई में जन सेहत के लेकर फिक्रमंद हैं? यह स्थिति तब है, जबकि स्वास्थ्य से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं केंद्र सरकार की मदद से संचालित हो रही हैं। सरकार को केवल क्रियान्वयन के लिए तंत्र विकसित करना है, पर सरकार उसमें भी नाकाम रह रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार को समझना होगा कि केवल कागजों में चिंता करके लोगों की सेहत नहीं सुधरने वाली है। सरकार को अपनी सोच और कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा। समय गंवाए बगैर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। उम्मीद है सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

बिहार

सराहनीय पहल

बिहार में बड़े पैमाने पर मौजूद बंजर भूमि को उर्वर बनाने की कवायद एक सराहनीय पहल है। यह जरूरी भी था, क्योंकि प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि इस हिसाब से कृषि उपज बढ़ने की जगह घट रही है। यह चिंताजनक होने के साथ एक बड़ी चुनौती भी है। इससे पार पाने के लिए तमाम उपायों के साथ कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ाना आवश्यक है।

सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसआइ) ने पिछले साल पर्यावरण की स्थिति पर वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि पूरे देश में औसत खेतों का आकार सिकुड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण बंजर जमीन का तेज रफ्तार से बढ़ना है। बंजर जमीन को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सूख जाती है और क्षेत्र से नमी खत्म हो जाती है। यह क्षेत्र अपनी वॉटर बॉडीज को खो देता है। साथ ही वनस्पति और वन्यजीव भी नष्ट हो जाते हैं। बंजर जमीन कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रहती। जमीन आमतौर पर पानी की कमी के कारण बंजर होती है। वह रिपोर्ट बताती है कि भारत में 9.64 करोड़ हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.872 करोड़ हेक्टेयर है। देश कराब 26 राज्यों में 2007 से 2017 तक बंजर होने वाली जमीन में इजाफा हुआ है। भारत में कुल उपजाऊ जमीन का 32 प्रतिशत हिस्सा बंजर होने की कगार पर है। वहीं भारत में कुल 69 प्रतिशत जमीन सूखी है। किसानों की आत्महत्या के पीछे कर्ज के अलावा उपजाऊ जमीन के बंजर होने से जुड़े भी कारण अहम हैं।

प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि कृषि उपज घट रही है। इससे पार पाने के लिए तमाम उपाय के साथ कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ाना आवश्यक है।

अभी बिहार में भी चार लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि बंजर है। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करने जा रही है। सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। यदि इससे ज्यादा खर्च आया तो उसे किसानों को देना पड़ेगा, जबकि कम खर्च होने पर उन्हें कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना होगा। दरअसल आर्थिक कारणों के चलते बहुत से किसान अपनी बंजर भूमि को खेती योग्य नहीं बना पा रहे थे। अब सरकार की मदद से वे आसानी से ऐसा कर सकेंगे। सरकार चाहती है कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाए। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों तक बेहतर साधन और तकनीक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान भी पहले की अपेक्षा जागरूक हुए हैं। अब वे एक ही खेत में कई बार फसल उगा रहे हैं, लेकिन अभी उन पर बाजार का दबाव है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं भी सामने हैं। 90 फीसद से ज्यादा किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी जोत का आकार एक हेक्टेयर से कम है। साथ ही अभी उन्हें जरूरत के हिसाब से उन्नत एवं प्रमाणिक बीज नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे सरकार की ओर से इस कमी को दूर करने के लिए बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग पॉलिसी बन रही है।

ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर इसे यथाशीघ्र लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त किसानों से जुड़ी कई और भी समस्याएं हैं, जिस पर काम किया जाना शेष है। जाहिर है कि हमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा।

झारखंड में खाली पड़ा है सरकार का खजाना, 5000 गायों का बंद है खाना

विकास कुमार हजारीबाग

झारखंड का खजाना खाली है। नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि वित्तीय स्थिति पर वह जल्द ही श्वेत पत्र लाएंगे। जनता को बताएंगे किस स्थिति में उन्हें राज्य सौंपा गया है। वास्तविक स्थिति श्वेत पत्र से वे जब भी स्पष्ट करें, अभी गायों के निवाले के लिए फंड न होना खजाने की स्थिति बयां करने को पर्याप्त है। राज्य के 22 निबंधित गोशाला में करीब 5000 गोवंशीय पशु हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले फंड से इनके लिए खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन पिछले छह माह से राज्य सरकार की ओर से इनकी खुराक के लिए मिलने वाली राशि बंद है। वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने पशुओं के निवाले पर संकट देखकर उनकी मदद को हाथ बढ़ाया और खाने की व्यवस्था की। हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर समेत राज्य की सभी गोशालाओं के पशुओं के लिए हर दिन चारा, उनकी दवाओं व अन्य संसाधनों के लिए गौशाला संघ को आमलोगों से मदद मांगनी पड़ रही है।

तीन माह पहले गोसेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार से 2.5 करोड़ पशुओं की खुराकी के मद में बकाया के भुगतान के लिए कहा गया था। प्रत्येक पशु के लिए 50 रुपये निर्धारित है। अब छह माह बाद बकाया बढ़कर पांच करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

- राज्य की 22 निबंधित गोशालाओं को छह माह से नहीं मिला खुराकी का पैसा
- चंदा कर किसी तरह गोवंशीय पशुओं के चारे का जुगाड़ कर रहे गोशाला से जुड़े लोग

प्रतीकात्मक

देश की सबसे पुरानी गोशाला खतरे में : 1885 में स्थापित हजारीबाग गोशाला का ही करीब 29 लाख 07 हजार रुपये खुराकी मद में बकाया है। देश की सबसे पुरानी गोशाला में से एक हजारीबाग गोशाला समिति के अध्यक्ष सुमेर सेठी के मुताबिक गोशाला में मौजूद 700 गायों के लिए खुराकी जुटाना मुश्किल हो गया है। एक दिन का खर्च 35 हजार रुपये है। कोलकाता पिजंरापोल सोसाइटी हजारीबाग में इसका संचालन कर रही है। फिलहाल आमलोगों की मदद से गोशाला में पशुओं की खुराक जुट रही है।

तस्करों से बचाए गए पशु पहुंचते हैं गोशाला : राज्य की गोशालाओं में पुलिस द्वारा तस्करों से बचाए गए गोवंशी पशु पहुंचते हैं। बकायदा इसकी एफआइआर की कॉपी गोशाला को उपलब्ध कराई जाती है। सिर्फ हजारीबाग में पिछले पांच दिनों में 153 पशु पकड़े गए हैं, जिन्हें हजारीबाग गोशाला में भेज दिया गया।

तीन माह पहले राज्य की 22 गोशाला के लिए 2.5 करोड़ की राशि खुराक मद में मांगी गई थी। पत्र लिखा गया था। लेकिन, राशि निर्गत नहीं हुई है। राशि पीएल अकाउंट में है, जिसे निकालने पर फिलहाल रोक लगी है।

- डॉ. ओपी पांडेय, सचिव, राज्य गोसेवा आयोग।

हरियाणा में बनेंगे गायों के लिए हॉस्टल

जागरण संवाददाता, हिसार : हरियाणा गो सेवा आयोग हिसार और गुरुग्राम में गो हॉस्टल बनाने की तैयारी में है। इसका लाभ उन लोगों को अधिक होगा, जो गांव से आकर शहर में बसे हैं। इनमें बड़ी संख्या में वे हैं जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सेक्टरों में रहते हैं, लेकिन नियमानुसार पशुपालन नहीं कर सकते।

गो हॉस्टल के लिए नगर निगम भूखंड मुहैया करवाएगा। सुबह शाम गोपालक स्वयं अपनी गाय का दूध निकाल सकेंगे। हॉस्टल में देसी नस्ल की गाय के रहने का प्रबंध होगा। इसके लिए हरियाणा गोसेवा आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसकी शुरुआत हिसार और गुरुग्राम से होगी। दोनों शहरों में करीब 10-10 एकड़ में गो हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसमें पहले चरण के करीब 50-50 देसी गाय के रहने के लिए प्रबंध होंगे। इन दोनों शहरों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

सोसाइटी करेगी संचालन : गो हॉस्टल का रखरखाव निजी हाथों में होगा। इसके लिए जो 50 लोग चयनित किए जाएंगे जो गोपालक होंगे। उनकी समिति बनाई जाएगी। जो इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने स्तर पर संभालेगी। निगम वहां पर चौकीदार व चारे का प्रबंध करेगा। रही बात खल व अन्य खाद्य सामग्री की तो अपने पशु के लिए पशुपालक स्वयं प्रबंध करेगा।

रेलवे इंजीनियर ने खोजा नया भविष्यवाणी सिस्टम, होगा बाधा रहित संचालन

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

रेलवे के इंजीनियर ने रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) तैयार किया है। यह बाधा रहित ट्रेन संचालन के लिए वरदान साबित होगा। यह सिस्टम सिग्नल के खराब होने से पहले ही भविष्यवाणी कर देगा। इसका परीक्षण रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) कर रहा है।

भारतीय रेल तेज गति से ट्रेन चलाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पुरानी रेललाइन हटाकर हाईस्पीड ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। बाधा रहित हाईस्पीड ट्रेन चलाने में सबसे बड़ी भूमिका सिग्नल सिस्टम व स्टेशन यार्ड में बने प्वाइंट सिस्टम की होती है। इसके लिए आधुनिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। निगरानी के बाद भी दोनों सिस्टम एकाएक खराब भी हो जाते हैं। ऐसे में हाईस्पीड ट्रेनों का बाधा रहित संचालन संभव नहीं हो पा रहा हैं। मुरादाबाद रेल मंडल में प्रवर मंडल संकेतक व दूरसंचार अभियंता नितिन प्रकाश ने बाजार में उपलब्ध डिवाइस को जोड़ कर भविष्यवाणी करने वाला सिस्टम तैयार किया है।

जुगाड़ से बनाए गए सिस्टम का नाम रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) रखा गया है। यह सिस्टम

- मुरादाबाद का सिस्टम भारतीय रेल में करेगा राज, बाधा रहित हाई-स्पीड ट्रेन संचालन हो सकेगा
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत दलपतपुर स्टेशन पर लगाया, आरडीएसओ की स्वीकृति के लिए भेजा

प्रतीकात्मक

रेलवे पर लगे सिग्नल व प्वाइंट से जोड़ा जाएगा। जो सिग्नल व प्वाइंट के खराब होने की सूचना 24 घंटे पहले मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को एसएमएस व मेल पर दे देगा। ऐसे में तकनीकी स्टाफ सिग्नल व प्वाइंट बदल देगा। फिलहाल यह सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुरादाबाद-रामपुर के बीच दलपतपुर स्टेशन पर लगाया गया है, जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसके नतीजे बहुत बेहतर आए हैं। परिणाम ठीक मिल रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) ठीक तरह के काम कर रहा है। इसका रिसर्च एंड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) अध्ययन कर रहा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद सिस्टम देशभर में लगाया जा सकता है। इससे हाईस्पीड ट्रेनें बगैर बाधा के चल सकेंगी।

सिस्टम में एक लाख रुपये का खर्च : प्रवर मंडल संकेतक व दूरसंचार अभियंता, मुरादाबाद रेल मंडल नितिन प्रकाश का कहना है कि सिग्नल खराब होने से देशभर में ट्रेनों का संचालन बाधित होता है। उपकरण में खराबी आने से पहले पहचान लिया जाए तो उसके ठीक किया जा सकता है। इससे तेज ट्रेनों को बाधा रहित चलाया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध डिवाइस को जोड़ कर यह सिस्टम तैयार किया है। इसे बनाने में एक लाख रुपये से भी कम खर्च आया है।

आसमान से वन एवं वन्यजीवों पर तीसरी आंख की निगहबानी

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड में अब वन एवं वन्यजीवों पर आसमान से 'तीसरी आंख' निगहबानी करेगी। इसके लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स अस्तित्व में आ गई है। यह फोर्स सभी वन प्रभागों में ड्रोन के जरिये वहां होने वाले कार्यों पर नजर रखेगी। साथ ही वन्यजीवों की मॉनीटरिंग पुख्ता ढंग से हो सकेगी। इस मुहिम से जंगलों में पौधरोपण, खाल-चाल निर्माण समेत दूसरे कार्यों में फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लग सकेगा। और तो और फायर सीजन में जंगल की आग पर काबू पाने में फोर्स मददगार होगी।

'जंगल में मोर नाचा किसने देखा' ये कहावत जंगलों और वन महकमे के परिप्रेक्ष्य में अक्सर कही जाती है, मगर निकट भविष्य में यह नेपथ्य में चली जाएगी। यानी जंगल भी दिखेगा और मोर नाचते यानी विभिन्न कार्य होते भी दिखेंगे। इसके लिए राज्य में शुरू की गई उत्तराखंड फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के गठन की कवायद अब आकार ले चुकी है।

फोर्स के समन्वयक डॉ.पराग धकाते बताते हैं कि अब तक 25 ड्रोन उपलब्ध हो चुके हैं। 10 वन प्रभागों में दो-दो कार्मिकों को ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर निपुण कर लिया गया है, जबकि अन्य प्रभागों में प्रक्रिया चल रही है। चार-पांच माह के भीतर सभी प्रभागों में ड्रोन की उपलब्धता फोर्स के साथ ही ऑपरेटर की तैनाती हो जाए।

- उत्तराखंड फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स हर प्रभाग में ड्रोन से तमाम कार्यों पर रखेगी नजर
- पौधरोपण समेत दूसरे कार्यों में रुकेगा फर्जीवाड़ा, वन्यजीवों की भी मॉनीटरिंग

ड्रोन फोर्स के फायदे

- द रस्थ क्षेत्रों में ड्रोन पर लगे कैमरों से आसानी से निगाह
- जंगलों में पौधरोपण की निरंतर होगी मॉनीटरिंग
- वन क्षेत्रों में अवैध पातन, अवैध खनन पर नियंत्रण
- वन्यजीव गणना में उपयोग में लाए जाएंगे ड्रोन
- जंगली जानवरों, प्रवासी परिंदों पर नजर रखने में उपयोगी

पलायन को मारेगा पर्यटन का ब्रह्मास्त्र

चंद्रशेखर वर्मा, ग्रेटर नोएडा: उत्तराखंड में गांवों से हो रहा पलायन प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है। शासन ने पलायन रोकने के लिए पर्यटन का सहारा लिया है। इसके लिए वर्ष 2021 तक गांवों में पांच हजार होम स्टे (पर्यटकों के लिए रहने, खाने आदि की व्यवस्था) तैयार करने की योजना है। करीब 2100 होम स्टे का पंजीकरण भी किया जा चुका है।

इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे साउथ एशियन ट्रैवल्स एंड टूरिज्म एक्सपो (साटे) में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के निदेशक आशीष भटगाइन व संयुक्त निदेशक पूनम चंद ने यह बातें बताई। उन्होंने बताया कि आय का साधन न होने की वजह उत्तराखंड के गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। जबकि, राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अब सरकार पलायन की समस्या दूर करने के लिए ग्रामीणों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

इसमें पर्यटकों के रहने के लिए ग्रामीण घरों को नवनिर्मित किया जाता है, जिसके लिए 40 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 33 फीसद और शहरी क्षेत्र में 25 फीसद सब्सिडी सरकार मुहैया करा रही है।

प्रदूषण से नष्ट हो रहा लाइकेन, पर्यावरण को खतरा

नईदुनिया, बिलासपुर

अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में लाइकेन (काई) की जैव विविधता एवं उनकी स्थिति का अध्ययन किया गया है। गुर घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ के वानिकी विभाग के शोधार्थी डॉ. अरविंद प्रजापति ने शोध में पाया है कि बढ़ते प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेप एवं वनक्षेत्र के दुरपयोग की वजह से शैवाल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इसका मुख्य कारण वातावरण में रासायनिक तत्वों का तेजी से बढ़ना है।

लाइकेन सल्फर डाई ऑक्साइड गैस से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यह गैस क्लोरोफिल का क्षरण करती है। लाइकेन के कई उपयोग हैं जिसमें प्राकृतिक डाई, प्राकृतिक खाद्य रंग, मसाले एवं औषधि रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अमरकंटक के कोर क्षेत्र में लाइकेन की 90 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं बफर क्षेत्र में 110 प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। लाइकेन कवक और शैवाल से बनता है। कवक और शैवाल के संयोग से बनने वाले शैवाल की आठ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अचानकमार व अमरकंटक जैसे क्षेत्र में भी काफी कमी आई है। प्रदेश में शैवाल की 138 प्रजातियों को

प्रतीकात्मक

अमरकंटक से गायब हुई ये प्रजाति

कोलेमा नाइग्रेस्केंस, लेप्टोजियम एशियाटिकम, लेप्टोजियम आस्ट्रोमेरिकेनम, लेप्टोजियम सिनेसिंस, लेप्टोजियम डेंटिक्लूकार्पन, कालोप्लेस सिटरीना, डर्मेटोकार्पोन मिनीएटम, लेप्टोलिजम कोरोन्यूलिनस।

चिन्हांकित गया है। पर्यावरण में बदलाव के प्रति संवेदनशील शैवालों की घटती संख्या खतरे की घंटी है। शोध से पता चलता है कि वातावरण में रासायनिक तत्व तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अचानकमार अमरकंटक जैव विविधता क्षेत्र में शैवाल की अधिकता वहां के भौगोलिक स्थिति और स्वच्छत वातावरण को प्रदर्शित करती है। वहां साल वृक्ष के घने वन में शैवाल की कई प्रजातियां मिली हैं। साल वन के छाल की संरचना शैवाल के उगने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। अब की स्थिति यह है कि अचानकामर के निकट बिलासपुर के बाहरी क्षेत्र में ही देखने को मिलती है।

ऐसे बनता है लाइकेन : कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाली प्रजाति को लाइकेन कहते हैं। यह एक सहजीवी है। शैवाल बेहद सूक्ष्म होते हैं। इसमें सूखे व ठंड मौसम के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और जटिल वातावरण में भी बचे रहने की योग्य होती है। यह रेगिस्तानी चट्टानों से लेकर अंटार्कटिका जैसे अति ठंडे क्षेत्र में भी पाया जाता है। वहीं, प्रदूषित जगहों पर शैवाल नहीं मिलते हैं। विविधता के कारण इसे सर्वभौमिक प्रजाति कहा जाता है। यह वृत चट्टानों या मृदा को आधार बनाकर उगते हैं। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है।

सिंथेटिक रंगों का तोड़ : शैवाल के कई उपयोग भी हैं। यह अंटार्कटिका में अल्ट्रा वायलट किरण से खुद को बचाने के लिए एक विशेष प्रकारण के जैव रासायनिक घटक का प्रयोग करता है। इस तरह इसका उत्पाद हमारे त्वचा को बचाने में भी सहायक हो सकते हैं। शैवाल के औषधीय गुण होने के साथ डाई करने में उपयोग किया जा सकता है। कुछ देशों में कपड़ों में सिंथेटिक रंगों के बजाए शैवाल से निर्मित रंगों का उपयोग होने लगा है। यह त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं होता।

वातावरण में बदलाव, जंगल में मानव की उपस्थिति व प्रदूषण के कारण शैवाल पर विपरीत असर पड़ रहा है। 10 साल के भीतर तीन बार सर्वे करने पर निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। शैवाल की आठ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जो अच्छा संकेत नहीं है। इसका संरक्षण जरूरी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण शैवाल की प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही हैं। अचानकमार और अमरकंटक के अलावा प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में इसे लेकर रिसर्च किया गया है।

- डॉ.एससी तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं गाइड - गुर घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 11 जनवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की 157 वीं जयंती

स्वामी विवेकानंद की पहली दिल्ली यात्रा

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

दिल्ली चलो का नारा देने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद (1863-1902) के विषय में लिखते हैं कि 'मैं मुश्किल से पंद्रह साल का था जब विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, तब मेरे मन में एक क्रांति हुई और सब कुछ परिवर्तित हो गया।' यही युवा संन्यासी विवेकानंद 27 वर्ष की आयु में पहली बार जनवरी 1891 के अंत में मेरठ से दिल्ली आए। स्वामी गंभीरानंद की पुस्तक 'युग नायक विवेकानंद' (प्रथम खंड) के अनुसार, 1891 की जनवरी के अंतिम भाग में एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने अकेले दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी तपस्या करने के विचार से अकेले मेरठ से निकले थे। यहां तक कि उन्होंने अपने रहने के स्थान के विषय में किसी को नहीं बताने का निश्चय किया था। पुस्तक में बताया गया है कि मेरठ के उपरांत साधारण वेशभूषा में साधारण रूप से विभूषित स्वामी जी ने हिंदू-मुस्लिम-युगों की अनेक स्मृतियों से जुड़ी इतिहास प्रसिद्ध महानगरी दिल्ली में पदार्पण किया। दिल्ली में स्वामी जी का डेरा सेठ श्री श्यामल दास का घर था। इस बारे में स्वामी गंभीरानंद लिखते हैं कि इस घर को केंद्र बनाकर वे (स्वामी विवेकानंद) अतीत काल के राजप्रासाद, दुर्ग, समाधिस्थल, परित्यक्त राजधानी के भग्न खंडहर और गुल्माच्छादित निवास-स्थान और अन्यान्य प्राचीन गौरव के समाप्त प्राय अवशेष आदि को देखने निकलने लगे। उनकी अध्यात्मानुभूति पुष्ट ऐतिहासिक चेतना ने उन्हें बता दिया कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, भारत की संस्कृति किस प्रकार अविनश्वर है और विभिन्न धाराओं के मिलन से कितनी विचित्र तथापि क्रमशः वृद्धिशील है।

पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं के इस अपूर्व लीलाक्षेत्र ने हजारों लुप्त महिमाओं की साक्ष्य अपने वक्ष में धारण कर उनके वैराग्यप्रवण मन को सहज रूप में ही बता दिया था कि सांसारिक ऐश्वर्य के क्षणभंगुर होने पर भी उसी के बीच में आत्मा की महिमा किस प्रकार चिरउज्जवल दीप्ति और विभिन्न भंगिमाओं से अपना विकास करती चली है। उनका मन उन दिनों काफी तेजपूर्ण था और दिल्ली के शीतकाल की विशुद्ध जलवायु के फलस्वरूप उनका शरीर भी स्वस्थ और सबल था। मेरठ से स्वामी जी के किसी को बिना बताए आने के कारण उनके गुरुभ्राताओं ने दस दिनों बाद दिल्ली में उन्हें खोज निकाला और उनके साथ सम्मिलित हो गए। स्वामी जी को

> विवेकानंद 27 वर्ष की आयु में पहली बार जनवरी 1891 के अंत में मेरठ से दिल्ली आए थे

उनसे मिलकर प्रसन्नता तो हुई पर उन्हें अपनी तपस्या में बाधा की आशंका हुई। उन्होंने अपने गुरुभ्राताओं से कहा, देखो भाई मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैंने तुम लोगों से कह रखा है कि मेरा पीछा मत करो। वही बात फिर कहता हूं-मैं यह नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे। मैं अभी दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं।

कोई मेरे पीछे चलने की चेष्टा न करे, कोई मुझे ढूंढ़ निकालने के लिए प्रयास न करें। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी बातों का पालन करो। मैं अपनी इच्छा से भ्रमण करूंगा-पहाड़, जंगल, मरूभूमि अथवा नगर में-चाहे जो हो, जो मुसीबत आवे। मैं चला। मेरी इच्छा है कि हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार साधना करने में लग जाए। गुरुभाइयों ने उन्हें समझाकर कहा, हम लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि तुम यहां ठहरे हो। हम लोग केवल दिल्ली नगर देखने आए थे। यहां आकर स्वामी विविदिशानंद नामक एक अंग्रेजी-भाषी साधु के विषय में खबर मिली। तब उन्हें देखने आए। अतएव, तुमसे जो मुलाकात हो गई, यह एक आकस्मिक घटना मात्र है। जैसे भी हो, स्वामी जी उस समय शांत गए और तुरंत दिल्ली त्यागकर नहीं गए। उनके दूसरे गुरु भाइयों के अलग-अलग स्थानों पर जाने के बाद दिल्ली में स्वामी जी के साथ स्वामी अखंडानंद और स्वामी अद्वैतानंद ही रह गए। तब स्वामी जी गले में टांसिल होने के कारण उस समय दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर हेमचंद्र सेन को अपना गला दिखाने गए। तब डॉक्टर सेन उनसे प्रभावित न होने के बावजूद गहन वार्तालाप के लिए उत्सुक थे। इस कारण डॉक्टर साहब ने एक दिन अपने घर पर महाविद्यालय के अनेक अध्यापकों को बुला लिया और स्वामी जी भी अपने दोनों गुरुभाइयों के साथ उस बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में शीघ्र ही विचार-विमर्श होने लगा और स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि और अगाध पांडित्य देखकर सभी चकित हो गए। इसके कुछ दिनों बाद, फरवरी 1891 में स्वामी जी दिल्ली से अलवर के लिए निकल गए। दिल्ली की प्राचीनता का स्वामी जी पर एक अमिट प्रभाव पड़ा। विदेशी भूमि की यात्रा के समय उन्हें दिल्ली के भूदृश्य के समान स्थान देखने को मिले। उन्होंने कैलिफोर्निया में 'सांता फे रूट' के बारे में सिस्टर निवेदिता को लिखा कि आज मैं जिन भूदृश्यों से होते हुए गुजर रहा हूं, वह दिल्ली के पड़ोस की तरह हैं। जहां आरंभ में एक बड़ा मरूस्थल, बेरंग पहाड़, डरावनी-कंटीली झाड़ियां और बेहद कम पानी है। यहां छोटी जल धाराएं (ठंड के कारण) जमी हुई हैं, लेकिन दिन में गर्मी है। मुझे लगता है, गर्मियों में ऐसा ही होना चाहिए। स्वामी जी को पेरिस यात्रा के समय दिल्ली की भावना की अनुभूति हुई। इस विषय पर स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का चांदनी चौक एक समय में डे लॉ कॉनकॉर्ड की तरह रहा होगा। यहां और वहां विजय स्तंभ, विजयी मेहराबें, पुरुषों और स्त्रियों तथा सिंहों की विशाल मूर्तियां मूर्तिकला के रूप में चौराहे पर सजी हुई हैं।

सामाजिक धरोहर

मराठी मानुष दिल्ली के विकास का साथी है और इस शहर के साथ रहने-जीने का भी...। हंसी-ठिठोली का भी और रीति-परंपराओं का भी। दिल्ली की बोली दिल में बसती है तो मराठी संस्कारों में। इतिहास से वर्तमान तक सब सुसज्जित है यहां इस समुदाय से। सबरंग के इस अंक में मराठी समुदाय से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

मराठा राजसी महल की वास्तुकला सी नायाब दिखती है महाराष्ट्र सदन की यह इमारत। संजय

...और दिल्ली का हो गया मराठी

दिल्ली की अलग कला संस्कृति और माहौल में मराठी रम बस चुके हैं। आप दिल्ली उनसे मुलाकात करेंगे तो आभास ही नहीं होगा कि ये मूलतः मराठी हैं। दिल्ली से दिल्लगी भी निभाई है और इसी शहर में अपने मराठी संस्कारों को भी पल्लवित किया है। जहां मराठों ने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली के विकास की नैया भी खेयी। अब इनका पहनावा...बोली...खानपान भी 'दिल्ली वाले मराठी' सा झलकता है। जो घर की चौखट तक मराठी में बात करते हैं लेकिन दिल से खालिस दिल्ली वाले हैं। जिन्हें मराठी खाना भी पसंद है और दिल्ली के छोले भटूरे भी। इतना ही नहीं मराठी युवा पीढ़ी भी अपनी कला-संस्कृति और संस्कारों को साथ लिए दिल्ली को दिल से जी रही है।

दिल्ली में मराठी समुदाय के इतिहास पर प्रशांत साठे कहते हैं कि इस समुदाय का दिल्ली में सैंकड़ों साल पुराना इतिहास है। पानीपत की लड़ाई के दौरान भी मराठा लड़े एवं फिर हारने के बाद दिल्ली समेत हरियाणा के विभिन्न हिस्सों, पहाड़ी इलाकों में जाकर रहने लगे। वहीं इतिहासकारों की मानें तो पटपड़गंज का इतिहास मराठों से जुड़ा है। अपनी राजधानी में स्वयं प्रवेश करने में असमर्थ निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वर्ष 1772 में महादजी सिंधिया की मराठा सेना इलाहाबाद से दिल्ली लाकर उसे दिल्ली की गद्दी पर फिर से बिठाया था। इसके एवज में बादशाह ने लगभग सब अधिकार मराठों को दे दिए थे। हालांकि बाद में शाह आलम ने मराठों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए लॉर्ड लेक से संरक्षण मांगा। अंग्रेज भी इसी मौके की तलाश में थे। इसका नतीजा पटपड़गंज के युद्ध के रूप में सामने आया। पटपड़गंज में 11 सितंबर 1803 को अंग्रेज जनरल गेरार्ड लेक के सैनिकों और फ्रांसिसी कमांडर लुई बॉरक्विएन के नेतृत्व में सिंधिया की मराठा सेना में एक भयंकर लड़ाई हुई। दिल्ली की इस लड़ाई में मराठों की हार ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के अवमूल्यन और अंग्रेजों के प्रभुत्व को निर्णायक रूप से तय कर दिया।

1911 के बाद बड़े पैमाने पर आए मराठी : प्रशांत साठे बताते हैं 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जिसमें राजधानी स्थानांतरित करने का ऐलान किया गया था। चूंकि सरकारी नौकरी में मराठी ज्यादा थे लिहाजा दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले समाज के लोगों का आशियाना ज्यादातर नया बाजार में होता था। यहीं पहले संगठन महाराष्ट्रीय स्नेह संवर्धक समाज की नींव पड़ी। जिस संस्था को अब 100 वर्ष हो चुके हैं। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1919 में हुई थी। दरअसल, जीआइपी रेलवे का ऑफिस उसी समय मुंबई से दिल्ली लाया गया था। चूंकि ऑफिस नया बाजार में ही था इसलिए इसमें काम करने वाले मराठी भी यहां आए। ये सभी किनारी बाजार, खारी बावली, लाहौरी गेट, चांदनी चौक में ही रहते थे। इस तरह समाज के लोगों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ती चली गई। चूंकि अधिकतर लोग एक ही पेशे में तो मिलना-जुलना...अपनी परंपराओं को जीवंत रखना सरल होता था। हालांकि जैसे जैसे आबादी बढ़ी लोग विभिन्न हिस्सों में रहना शुरू किए। उन दिनों नया बाजार वाले दफ्तर में महाराष्ट्र से आने वाले अतिथि भी ठहरते थे। आजादी के बाद सन् 1951 में समाज का कार्यक्षेत्र पहाड़गंज स्थानांतरित हुआ। एक दफा लोकमान्य तिलक जब दिल्ली आए थे तो वो भी यहीं रुके थे। उन्हें सुनने तब समाज के सभी सदस्य आए थे। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को महाराष्ट्र नहीं ले जा सकते। इसलिए महाराष्ट्र को ही दिल्ली लाते हैं। महाराष्ट्र की कला, संस्कृति तभी से दिल्ली को सुशोभित कर रही है।

अब दिल्ली-एनसीआर में सब जगह : दिल्ली-एनसीआर में यही कोई पांच लाख से ज्यादा मराठी रहते हैं। प्रविर कहते हैं कि नया बाजार, करोल बाग में रहना शुरू किए। फिर आबादी बढ़ी तो दिलशाद गार्डन, रामप्रस्थ, आनंद विहार, पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पटपड़गंज, वैशाली, वसुंधरा में रहने लगे। अभी भी करोल बाग में बड़ी संख्या में रहते हैं। पश्चिमी दिल्ली में आनंदवन, राजा गार्डन की सोसायटी में मराठी रहते हैं। नौकरी के लिहाज से देखें तो सरकारी नौकरी समेत डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी भी हैं।

संगठनों के जरिए बढ़ती प्रगाढ़ता : एक बात जो कि बहुत खास है कि मराठी, दिल्ली-एनसीआर में भले रह अलग-अलग रहे हैं लेकिन उनके बीच मेल-मिलाप बराबर है। वो भी ऐसे ही नहीं बल्कि तकरीबन 25 ऐसे मराठी संगठन हैं जो इस प्रगाढ़ता को निरंतर बनाए हुए हैं। कला-संस्कृति की गतिविधियों के माध्यम से सभी को जोड़े रखते हैं। साथ ही स्कूलों आदि का संचालन का जिम्मा भी संभालते हैं। मराठा मित्र मंडल ऐसा ही संगठन है। फैज रोड पर स्थित चौबोले पब्लिक स्कूल का संचालन भी संस्था कराती है। 12वीं तक के इस स्कूल में 8वीं तक मराठी पढ़ना अनिवार्य होता है। इसी तरह महाराष्ट्र एजुकेशनल सोसायटी पहाड़गंज में नूतन मराठी विद्यालय संभालती हैं। यह सरकारी सहायता प्राप्त है लेकिन मैनेजमेंट मराठी है। लोदी रोड पर एक वनिता समाज है। जहां मराठी समुदाय की महिलाएं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। यह कार्यक्रम लोक संगीतों पर आधारित होते हैं। एक अन्य शारदा संघ भी है। इस महिला विंग में कभी 17 से ज्यादा सदस्य थीं। एक समय महिला विंग बहुत ही सक्रिय थी। उन दिनों यूनिक प्रोग्राम उद्योग मंदिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। महिलाएं स्नैक्स, पापड़, अचार समेत अन्य महाराष्ट्र के खाद्य उत्पाद बनाती थीं। इन उत्पादों घर-घर जाकर बेचा जाता था। कहा जाता है कि उन दिनों महाराष्ट्र सरकार के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या बैठक दिल्ली में होते थे उसमें खाना यहीं से जाता था। वर्तमान में यह महिला विंग सक्रिय हो चुकी है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की कमान संभालती हैं। गुडी पहवा, चैत्र माह, गणेश उत्सव, शरद पूर्णिमा...सारे पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। सन् 1972 में समाज ने एक आडिटोरियम भी बनाया। इसका संचालन महाराष्ट्र रंगायन थियेटर ग्रुप करता है। यह सिरीफोर्ट आडिटोरियम के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा आडिटोरियम है। इसमें 748 लोगों के बैठने की क्षमता है।

धूमधाम से मनती है शिवाजी जयंती : अब मराठी समुदाय शिवाजी जयंती की भी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है जो कि 19 फरवरी को होती है। सदस्य बताते हैं कि महाराष्ट्र सदन में उनकी मूर्ति लगी हुई है। महाराष्ट्र सदन से एक जुलूस निकलता है। जिसमें हाथी, घोड़े, ढोल नगाड़े के साथ लोग शरीक होते हैं। यह जुलूस यदि अनुमति मिली तो राजपथ नहीं तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तक जाता है। इसमें नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहीं तिलक मार्ग स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा के सामने भी हर साल कार्यक्रम होते हैं। जिसमें तिलक के देश के आजादी के आंदोलनों में दिए योगदानों को याद किया जाता है।

दीवाली पाहट...खास परंपरा : दिल्ली में मराठी समुदाय की दीवाली भी बहुत खास होती है। यह सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है बल्कि इसके लिए मराठी दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहते हुए प्रशांत इसके पक्ष में कई वजहें गिनाते हैं। कहते हैं, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। दीवाली के एक दिन पूर्व अल सुबह ही संगीत कार्यक्रम आयोजित होता है। हम विगत चार सालों से यह आयोजन इंडिया गेट लॉन में आयोजित करा रहे हैं। 2019 दीवाली में सुरेश वाडेकर आए थे। जबकि उसके पहले महाराष्ट्र के बड़े कलाकार मसलन बेला शिंदे, सामी शिंदे, महेश काले शरीक हुए थे। इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद युवाओं को लोक गीतों से रूबरू कराना है। वहीं शरद पूर्णिमा को कोझागिरी पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मराठी समुदाय के लोग रात में खुले मैदान में चांद के नीचे बैठकर लोकगीत गाते हैं।

समुदाय के सांस्कृतिक महोत्सव में मराठा नाटक का मंचन करते कलाकार। सौजन्य : प्रशांत साठे

शताब्दी वर्ष में सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान मंच पर उपस्थित मराठा समुदाय के लोग। सौजन्य : प्रशांत साठे

ये बढ़ा रहे समुदाय की संस्कृति को

दिल्ली में मराठी समुदाय को तरक्की के पथ पर अग्रसर करने की बात हो या फिर कला संस्कृति का संरक्षण। ऐसे कई पुरोधा हैं जो समृद्ध कर रहे हैं। इसमें कारोबारी प्रशांत साठे, विस्वास डमडेरे, वैभव डांगे (केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सेक्रेटरी), विवेक गर्गे, प्रफुल्ल पाटिल, रमेश पाटिल, शेखर वामोरकर, असिसटेंट प्रोफेसर प्रविर चित्रे हैं। राजनेताओं की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की पढ़ाई पहाड़गंज स्थित नूतन मराठी स्कूल में हुई है। पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद महेश गिरी भी नासिक से संबंध रखते हैं। मराठी नितिन सरकारे दिल्ली में राजनीति के चेहरे हैं। अधिकारियों की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड के ज्वाइंट डॉयरेक्टर राजीव गोड़बोले हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे भी महाराष्ट्र के है। सुप्रीम कोर्ट में भी मराठी वकील हैं, जिसमें शिरिष देशपांडे, शुभ्रा प्रमुख हैं। शिक्षा विभाग के बोर्ड आफ डायरेक्टर में रजिस्ट्रार है शिवाजी भंडारकर।

राजमुकुट लगे हैं इस इमारत में

केजी मार्ग स्थित नया महाराष्ट्र सदन की इमारत अपनी उत्कृष्ट वास्तु से दर्शकों का ध्यान खींचती है। आम दिल्ली वालों की जुबान में समझें तो यह राजमुकुट वाली इमारत है। जिसके सिर पर तीन मुकुट सजे हैं। यह करीब 6.18 एकड़ में फैला है। यदि पुराने महाराष्ट्र सदन से तुलना करें तो पता चलता है कि पुराने सदन में 53 कमरे हैं। जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए सुइट्स भी हैं। वहीं नए भवन में 138 कमरे और दो सुइट हैं। पदाधिकारी बताते हैं कि इसक निर्माण 2006 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ। मराठा राजसी महल की वास्तुकला को दर्शाती इस इमारत की वास्तुकला मुंबई के पीजी पटकी ने तैयार की है। यहां सुइट्स और कमरों के अलावा, दो सभागार भी हैं, एक सांस्कृतिक केंद्र, एक पुस्तकालय, एक अति आधुनिक जिम, एक प्रशिक्षण केंद्र और एक कैंटीन है।

पदाधिकारी बताते हैं कि जिस भूमि पर ढांचा तैयार हुआ है, वह 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले कई हाथों में गई। मसलन, 1932 में, बड़ौदा के महाराजा ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के महाराजा से यह जमीन खरीदी थी। उस समय यह जमीन खाली पड़ी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय सेना ने जमीन पर कुछ निर्माण किया था। महाराष्ट्र सरकार को मालिकाना हक दिए जाने के बाद जो अस्थायी निर्माण थे वे हटा दिए गए। यह भी कहा जाता है कि एक समय यहां सरकार ने राज्य अतिथि गृह का निर्माण करने का फैसला किया था।

समुदाय से जुड़े एक शख्स कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां लगभग सभी राज्यों के गेस्ट हाउस हैं। इसका श्रेय प्रशासनिक हलकों में बिहार को दिया जाता है। दरअसल बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का जवाहरलाल नेहरु के साथ अच्छा संबंध था। वह अक्सर नेहरु से मिलने और उनके साथ किताबें साझा करने के लिए दिल्ली आते थे। 'एक बार प्रस्ताव दिया कि राज्यों के प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए दिल्ली में गेस्ट हाउस होने चाहिए। जिसके बाद ओडिशा, असम और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने इसका समर्थन किया और नेहरु ने इन गेस्ट हाउसों के लिए जमीन आवंटित करने पर सहमति जताई। अगर इस इमारती की वास्तु की बात करें तो सदन में प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले शिवाजी की प्रतिमा है। अंदर आपको महाराष्ट्र की वाडा संस्कृति की झलक मिलेगी। विशेष रूप से ऐतिहासिक शनीवर वाडा और विश्रामबाग वाडा।

विशेष सुविधाएं

- कुल क्षेत्रफल : करीब 6.18 एकड़
- कुल कमरे : 138
- कैबिनेट मंत्रियों और उच्च न्यायालय के लिए सुइट
- 8 में 3 कमरे प्रत्येक राज्य के मंत्रियों के लिए सुइट 16 प्रत्येक कमरे में दो कमरे हैं।
- विधायकों के लिए कमरे : 21
- प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारियों के लिए सुइट : 6
- अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए कमरे : 80
- 500 की बैठने की क्षमता वाला सभागार।
- 100 की क्षमता वाला प्रेस कमरा, पुस्तकालय और संग्रहालय भी।

निर्मल के चॉकलेटी और अचारी मोमोज

जायका

लाल मिर्च और लहसुन की चटखारेदार चटनी के साथ गरमागरम सोया और चिकन मोमोज...मोमोज प्रेमियों के लिए इससे जायकेदार शाम और क्या होगी। लेकिन दो-चार की बात छोड़िए अगर आपको मोमोज की 40 से अधिक वैरायटी खाने को मिल जाए तो फिर क्या कहेंगे। अचारी, इटैलियन ग्रेवी, मिंट ग्रेवी, बटर मलाई, मखनी ग्रेवी मोमोज के एक से बढ़कर एक स्वाद आपके सामने टेबल पर होंगे। बस आप करोलबाग स्थित गफ्फार मार्केट में रिजेंट मॉल के पास निर्मल मोमो प्वाइंट पहुंच जाएं। दूर से ही मोमोज की खुशबू महसूस करने लगेंगे।

10 वर्ष की उम्र से बनाने लगे थे मोमो: मजबूरी में शुरू किया गया काम किस कदर शौक बन गया इस बात को जयप्रकाश से बेहतर भला कौन समझ सकता है। 10 वर्ष की उम्र में घर की जिम्मेदारी और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए जयप्रकाश ने मोमोज बनाना शुरू कर दिया था। आज वहीं काम उनका शौक बन गया है और जो काम शौक से किया जाए उसमें स्वाद न हो भला हो सकता है। तभी तो पिछले वर्ष आइएचएम पूसा द्वारा उन्हें स्वादिष्ट कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए बेस्ट न्यूट्रिशियस फ्यूजन अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। शुरुआती दिनों में वे मोमोज बनाने के लिए सामान बाहर से लाते थे। मोमोज बेचते समय उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी कि किसी तरह उनके स्कूल व ट्यूशन की फीस निकल जाए। धीरे-धीरे जब काम चल पड़ा तब उन्होंने घर पर ही मोमोज का सारा सामान बनाना शुरू कर दिया। घर पर उनकी मां व भाभी भी इस काम में उनकी मदद करती हैं तो स्टॉल पर उनके बड़े भाई धर्मवीर उनका हाथ बंटाते हैं।

तारीफ मिली तो बढ़ा उत्साह: संघर्ष के दिनों को याद करते हुए जयप्रकाश कहते हैं कि वे स्कूल से आकर मोमोज बनाया करते थे। तब दुकान पर आने वाले ग्राहक चटखारे लेकर मोमोज खाते और जाते समय खूब तारीफ करते थे। इससे उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिली तो उन्होंने मोमोज के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। दिमाग लगाकर अलग-अलग तरह के मोमोज बनाने शुरू किए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय मोमोज को ही दे दिया। उनके हाथ के अफगानी और अचारी मोमोज लोगों को खूब पसंद आते हैं। दूर-दूर से लोग इसका स्वाद लेने पहुंचते हैं। गुरुग्राम में रहने वाले विदेशी लोग भी इनके मोमोज को खूब पसंद करते हैं। इनके पास कई प्रसिद्ध लोग भी मोमोज खाने आते हैं, जिनमें गायक वाइसी गुर्जर, सूफी गायक हमसार हयात निजामी, हैरी बरार, वैभव हंसु चौधरी आदि कलाकार शामिल हैं।

40 के अधिक वैरायटी: चॉकलेट मोमोज का स्वाद आप किसी खास अवसर पर ही ले पाएंगे। लेकिन 40 से लेकर 100 रुपये के बीच आप यहां स्टीम, फ्राइड, ग्रेवी, अफगानी, अचारी, इटैलियन ग्रेवी, मिंट ग्रेवी, बटर मलाई, बटर मसाला, मखनी ग्रेवी, कुरकुरे, पिज्जा, तंदूरी बटर, बॉम्बे चिली का स्वाद ले सकते हैं। दिल्ली फ्लेवर मोमोज की अगर बात करें तो वेज, सोया, पनीर और चिकन मोमोज मिल जाएंगे। इसके लिए चटनी घर पर ही तैयार की जाती है। इनमें डलने वाले सभी मसाले भी घर से पिसे होते हैं। मोमोज परोसने का तरीका भी ग्राहकों को पसंद है।

रितु राणा

ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है...आप तय करें किसका स्वाद पहले लेंगे। जागरण

अंग्रेज भी यहां के बागियों से थे खौफजदा

शहर के गांव

अलीपुर जाट लैंड...आर्थिक रूप से जितना समृद्ध है इसका इतिहास भी उतना ही रसूखदार। अंग्रेज इस गांव के लोगों को यूं ही बागी नहीं कहा करते थे। गांव के 78 लोग आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़े थे। दिल्ली के पहले विधानसभा क्षेत्र नरेला स्थित अलीपुर गांव ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी बगावत की कि खौफजदा अंग्रेजों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। नौजवानों के खून से सींचे इस गांव को शहीदी गांव की पहचान मिली है। 1368 में खेड़ा खुर्दा से आए श्रीपाल नाम के व्यक्ति ने इस गांव को बसाया था।

धर्मनिरपेक्षता की मिसाल: राय सिंह मान कहते हैं कि वर्ष 1947 में आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हर जगह दंगा-फसाद हो रहे थे, लेकिन इस गांव में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मुस्लिमों को ट्रेन के जरिये सुरक्षित पाकिस्तान भेजने में मदद की थी। अंग्रेजों से तो बराबर लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं की।

पांच भाइयों के नाम पर पांच पन्ना: 651 वर्ष पुराने अलीपुर गांव को नेघराज के पुत्र श्रीपाल ने बसाया था। उनके पांच भाइयों के नाम पर गांव में पांच पन्ने (मोहल्ले) बनाये गए। भरतान पन्ना, हांडी पन्ना, टोकणी पन्ना, गांधी पन्ना और जामुन तले पन्ना। पहले गांव का नाम हरिपुर रखा गया था। श्रीपाल के वंशजों से 1857 में एक महिला ने गांव की जमीन खरीद ली थी। 1860-65 के दौरान फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में महिला ने यहां की जमीन किसी शेख अली खान नामक व्यक्ति दो बेच दी। उन्होंने इस गांव का नाम अलीपुर रख दिया। लोग बताते हैं कि वर्ष 1937 तक गांव में शेख अली का परिवार रहता था।

अंग्रेजों ने क्यों कहा बागी: गांव के लोगों के मुताबिक 1857 में मेरठ क्रांति की आवाज पर यहां के लोगों ने भी अंग्रेजों का विद्रोह किया। जिस कारण यहां के लोगों को बागी कहा जाने लगा। गांव के निवासी राय सिंह मान कहते हैं रायसीना रोड से जब अंग्रेज चलते थे तो किंग्सवे कैंप से होते हुए वह सबसे पहले अलीपुर गांव स्टैंड के पास रुकते थे। यह उनका पहला पड़ाव होता था, जिस कारण गांव के लोग आज भी बस स्टैंड वाले स्थान को पड़ाव ही कहते हैं। 1857 की क्रांति में गांव के 78 नौजवान फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। तब स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में दो पेड़ हुआ करते थे कुछ को उन पर लटकाकर फांसी दी गई और कुछ को पुरानी जीटी रोड स्थित धौलाकुआं (अब यहां लिबासपुर है) पर फांसी पर चढ़ाया गया। कहते हैं वर्ष 1990 तक जब भी बारिश होती थी तो वह जमीन लाल हो जाती थी।

गांधी व नेहरु ने रखी थी विकास की नींव: मेन अलीपुर चौपाल की नींव स्वयं महात्मा गांधी ने रखी थी। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने इस गांव को प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया। अलीपुर से नरेला की ओर जाने वाली रोड की नींव भी रखी। उन्होंने अपने सिर पर टोकरी रखकर उसमें से मिट्टी गिराकर इस सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया था। दादा ईशर गांव के पहले पंचायती थे और चौधरी लायक राम कांग्रेस की पहले बोर्ड कमेटी के सदस्य बने थे।

मंदिर और ईदगाह ऐतिहासिक धरोहर: गांव में तीन चौपाल है अलीपुर गढ़ी, हांडी पन्ना व जाटव चौपाल। यहां युवा से लेकर बुजुर्ग तक बैठते हैं। गांव में 250 वर्ष पुराना है और 16 बीघा जमीन में फैला प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि वहां बैठकर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। एक राम सरोवर तालाब भी है हालांकि तालाब अब सूख चुका है लेकिन छठ पूजा के दौरान उसमें पानी भरा जाता है। शेख अली द्वारा बनवाया गया ईदगाह भी गांव में मौजूद है।

रितु राणा

अलीपुर गांव के लोग किसी भी मुद्दे पर इसी तरह मिल बैठ कर लेते हैं निर्णय। जागरण

इतिहास रचने का धनी हैं गांव

- भारत का क्रिएटिव (रचनात्मक) ब्लॉक की शुरुआत का श्रेय
- दिल्ली के सबसे पुराने थानों में से एक अलीपुर थाना, जो 1912 में बनाया गया था।
- 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में इस गांव बलबीर शहीद हो गए थे, उनके नाम पर गांव में एक सड़क भी है।
- कुमारी अरुणा 21 वर्ष 4 महीने की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की पार्षद रह चुकी हैं।

यूबीआइ और बीओबी ने ब्याज दरें घटाईं

नई दिल्ली : सरकारी कर्जदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.10 परसेंट कटौती करने की घोषणा की है। बैंक ने बताया कि नई दरें शनिवार से लागू होंगी। बैंक की नई एमसीएलआर सभी अवधि के कर्ज पर लागू होंगी। एमसीएलआर में कटौती से ऑटो, पर्सनल और होम लोन सस्ता होगा। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एमसीएलआर में कटौती करने की बात कही है। इसकी एमसीएलआर 7.60 परसेंट होगी और रविवार से प्रभाव में आएगी। (प्रेट्र)

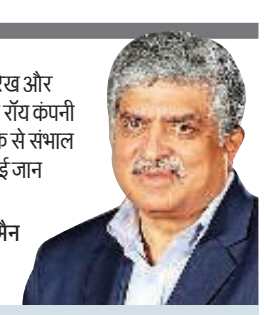

सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय कंपनी के विरासत को बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। पारेख ने कंपनी में नई जान डालने का काम किया है।
— नंदन नीलेकणि, चेयरमैन इन्फोसिस

सेंसेक्स	41,599.72	▲ 147.37
निफ्टी	12,256.80	▲ 40.90
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 40,554	▼ ₹80
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 47,695	▼ ₹200
$ डॉलर	₹ 70.94	▼ ₹0.27
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 64.91	

चीन से ज्यादा होगी पेट्रोलियम डिमांड

आइईए की रिपोर्ट ▶ तेल की बढ़ती मांग को पूरा करना भारत के लिए बड़ी चुनौती

परिस्थितियों को देखते हुए तेल का रणनीतिक भंडार बढ़ाने की जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले एक दशक में घरेलू स्तर पर तेल की आपूर्ति बढ़ाने में खास सफलता नहीं मिलने से भारत की आयातित क्रूड पर निर्भरता बढ़ने लगी है। 2020 के मध्य तक भारत में क्रूड की मांग चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय इनर्जी एजेंसी (आइईए) ने कहा है कि इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए भारत के पास तेल का रणनीतिक भंडार ज्यादा दिनों का होना चाहिए ताकि वह वैश्विक अस्थिरता का सामना कर सके। अभी भारत के पास महज 10 दिनों का रणनीतिक भंडार है, जो नाकाफी है।

एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार व सीईओ अमिताभ कांत की उपस्थिति में आइईए के अध्यक्ष फतिह बिरोल की तरफ से भारत की ऊर्जा नीति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2017 में भारत में तेल की मांग 44 लाख बैरल प्रति दिन थी जो वर्ष 2024 तक 60 लाख बैरल प्रति दिन की हो जाएगी। अभी चीन में क्रूड की मांग भारत से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन इस साल के मध्य तक भारत आगे निकल जाएगा। भारत अभी अमेरिका व चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है।

नई दिल्ली में भारत की ऊर्जा नीति पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करने के मौके पर बोलते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (मध्य में)। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल (बाएं) और नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। एएनआइ

आइईए अध्यक्ष फतिह बिरोल के मुताबिक देश में उज्ज्वला स्कीम, ज्यादा मोटर वाहन खरीदे जाने से हो सकता है कि कच्चे तेल की खपत यहां और तेज हो जाए। भारत निश्चित तौर पर अभी उस मुहाने पर जो उसे इनर्जी कंपनियों के लिए एक बेहतरीन निवेश स्थल बनाता है। सौभाग्य से भारत सरकार की नीतियां भी बेहद सकारात्मक हैं।

पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आइईए ने वर्ष 2015-2018 के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। भारत के एनर्जी सेक्टर में होने वाला निवेश काफी बढ़ चुका है। कई वैश्विक कंपनियां भारत में कारोबार शुरू कर चुकी हैं। सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है जिसे और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश चल रही है। भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी कदम बढ़ा दिया है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा।

आत्मनिर्भर होने के लिए होगी साढ़े चार करोड़ टन तिलहन की जरूरत

आम बजट से उम्मीदें

- वर्ष 2022 तक तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर होगा जोर
- आधुनिक टेक्नोलॉजी और उचित बाजार उपलब्ध कराएगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

खाद्य तेल आयात पर निर्भरता घटाने के लिए घरेलू तिलहनी फसलों की खेती पर भरोसे की जरूरत है। बजट में सरकार इस दिशा में कुछ अहम कदम उठा सकती है। इसका संकेत इसी सप्ताह रिफाइंड पाम आयल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर दे भी दिया है। 2022 तक खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कुल 4.5 करोड़ टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी।

खाद्य तेलों की घरेलू खपत 2.50 करोड़ टन सालाना है। इसमें से 1.50 करोड़ टन तेल का आयात होता है। देश में तिलहन की खेती में लगातार कमी से आयात निर्भरता बढ़ती गई। केंद्र की राजग सरकार ने पहल करते हुए 2022 तक खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पहला कदम आयात को हतोत्साहित करना है। आगामी वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट आने से पहले सरकार ने रिफाइंड पाम आयल के आयात को रोक दिया है। क्रूड पाम आयल के आयात पर भी 41.25 फीसद का शुल्क लगा दिया गया है।

देश में फिलहाल 3.10 करोड़ टन तिलहनी फसलों का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 4.50 करोड़ टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य तेलों के आयात पर लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। आत्मनिर्भर होने के लिए तिलहन की खेती पर जोर की जरूरत है। आम बजट में पुख्ता उपायों की घोषणा की जा सकती है।

भारत में जहां राइस ब्रान से 95000 टन खाद्य तेल तैयार होता है, वहीं चीन में यह दो लाख टन होता है। इसे प्रोत्साहित करने पर कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। दूसरा, खाद्य तेलों का आयात रोकने पर जोर होगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। तिलहन बाजार में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की गारंटी होनी चाहिए, ताकि किसान तिलहन खेती के प्रति आकर्षित हों। तिलहन को लेकर बनाई गई नीतियों में सुधार की जरूरत है, जिससे इसके अनुसंधान और खेती में निवेश हो सके। तिलहन खेती को लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूरी है, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। देश में क्रूड पेट्रोलियम, सोना और हीरा के बाद खाद्य तेलों के आयात पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

न्यूज गैलरी

धर्मेंद्र प्रधान करेंगे एकीकृत स्टील हब का उद्घाटन

कोलकाता : केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को घेरने वाले एकीकृत स्टील हब का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में लगभग 70 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। पूर्वी राज्यों के विकास को केंद्रित पीएम नरेंद्र मोदी की 'पूर्वोदय' परियोजना का यह अहम हिस्सा है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लगने से स्टील क्लस्टर के विकास के अलावा पूर्वी क्षेत्र में रसद और बुनियादी ढांचों का विकास तेजी से हो सकेगा। (जासं)

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से कच्चे तेल में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के भाव में 15 पैसे तक का इजाफा हुआ है। वहीं डीजल का भाव भी 11 पैसे तक चढ़ गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75.96 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 69.05 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। (आइएएनएस)

नवी टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण करेगी डीएचएफएलजीआइ

नई दिल्ली : सचिन बंसल की अगुआई वाली कंपनी नवी टेक्नोलॉजी बीमा कंपनी डीएचएफएल जरनल इंश्योरेंस (डीएचएफएलजीआइ) का अधिग्रहण करने की तैयारी में है। डीएचएफएलजीआइ, वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और नवी टेक्नोलॉजी के बीच शेयर खरीदारी समझौता हुआ है। डीएचएफएलजीआइ के 100 परसेंट शेयर खरीदकर नवी टेक्नोलॉजी इसका अधिग्रहण करेगी। (प्रेट्र)

देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई : देश का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। आरबीआइ से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 368.9 करोड़ डॉलर (करीब 26 हजार रुपये) बढ़कर 46115.7 करोड़ डॉलर (करीब 32,28,099 करोड़ रुपये) पहुंच गया। पिछले सप्ताह इसमें 252 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ था। (प्रेट्र)

शेयर बाजारों में बढ़त के साथ हुआ कारोबारी सप्ताह का अंत

- बेहतर ग्लोबल संकेतों से बढ़ा है निवेशकों का मनोबल
- कंपनियों के तिमाही नतीजों और बजट पर है निवेशकों की नजर

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सत्र की तेजी को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 147.37 अंकों की वृद्धि के साथ 41,599.72 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में इसमें 323 अंकों का उछाल देखा गया था। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 40.90 अंकों का सुधार हुआ। यह 12,256.80 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 12,311.20 का इंट्रा-डे रिकॉर्ड बनाया। इस सप्ताह सेंसेक्स में कुल 135.11 और निफ्टी में 30.15 अंकों का सुधार हुआ है।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.47 परसेंट का उछाल आया। अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स और एचयूएल के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, टाइटन और भारतीय एयरटेल के शेयरों में 1.11 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, कैपिटल गुड्स और आइटी सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी दर्ज की गई, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया में फिलहाल तनाव नहीं बढ़ने की उम्मीद से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। क्रूड ऑयल के दामों में नरमी और रुपये की मजबूती से भी घरेलू बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। रुपये में लगातार चौथे दिन डॉलर के मुकाबले मजबूती दर्ज की गई। रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 70.94 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा निवेशकों का ध्यान कंपनियों के तिमाही नतीजों और आम बजट पर भी लगा हुआ है। बाजारों को उम्मीद है कि इकोनॉमी को गति देने के लिए बजट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शुक्रवार को एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख दिखा। हांगकांग, टोक्यो और सियोल के शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं शंघाई के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए।

इन्फोसिस के शीर्ष अधिकारियों पर लगे आरोप बेबुनियाद पाए गए

- कंपनी के बोर्ड की ओर से गठित ऑडिट कमेटी कर रही थी मामले की स्वतंत्र जांच
- सीईओ पारेख और सीएफओ रॉय पर वित्तीय अनियमितताओं का लगा था आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिग्गज आइटी फर्म इन्फोसिस ने अपने शीर्ष अधिकारियों पर लगे वित्तीय अनियमितता एवं अनैतिक कारोबारी व्यवहार के आरोपों को निराधार पाया है। व्हिसलब्लोअर की शिकायत के बाद कंपनी के बोर्ड की ऑडिट कमेटी मामले की स्वतंत्र जांच कर रही थी। व्हिसलब्लोअर ने सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय पर अनैतिक कारोबारी गतिविधियों का आरोप लगाया था।

ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन डी. सुंदरम ने कहा, 'ऑडिट कमेटी ने व्हिसलब्लोअर की शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया और मामले की विस्तृत जांच की। इसमें स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद ली गई। जांच में ऑडिट कमेटी को ऐसी किसी गतिविधि के सबूत नहीं मिले।' पिछले साल अक्टूबर में व्हिसलब्लोअर ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। शिकायतों की जांच के लिए ऑडिट कमेटी ने शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स से स्वतंत्र कानूनी सलाह ली थी। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने कहा कि सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय कंपनी की समृद्ध विरासत के बेहतर संरक्षक हैं। नीलेकणि ने पारेख की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने संगठन में नई जान डालने का काम किया है और कंपनी बोर्ड उनकी भूमिका को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है।

यह है मामला : पिछले साल अक्टूबर में व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया था कि उस पर जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए वीजा लागतों को कम दिखाने का दबाव बनाया गया। व्हिसलब्लोअर ने 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को नजरअंदाज करने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया था। उसका कहना था कि शीर्ष अधिकारियों ने मुनाफा बढ़ाकर शेयरों की कीमत ऊंची बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए।

शुद्ध मुनाफा 23 परसेंट बढ़ा

बेंगलुरु, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान इन्फोसिस के शुद्ध मुनाफे में 23.7 परसेंट का इजाफा हुआ है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4,466 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में मुनाफा 3,610 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का राजस्व 7.9 परसेंट बढ़कर 23,092 करोड़ रुपये रहा, सालभर पहले यह 21,400 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 10 से 10.5 परसेंट राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस बीच शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में दो परसेंट का उछाल देखा गया। बीएसई में कंपनी के शेयर 1.47 परसेंट की वृद्धि के साथ 738.25 रुपये के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में इसके शेयर 1.71 परसेंट उछाल के साथ 740 रुपये के भाव पर बंद हुए।

एसईजेड नीति में बदलाव की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वैश्विक बाजारों में मिल रही चुनौती से निर्यातकों को बचाने के लिए सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) नीति में सिरे से बदलाव पर विचार कर रही है। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार एसईजेड पर बाबा कल्याणी की रिपोर्ट की शेष सिफारिशों पर अमल सुनिश्चित करना चाहती है।

मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार उन सभी सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है जिनसे मौजूदा वैश्विक माहौल में निर्यातकों के लिए कारोबार करना आसान हो सके। इस संबंध में गुरुवार को वाणिज्य व उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक लंबी बैठक कर एसईजेड से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया। मंत्रालय के बयान के मुताबिक कल्याणी समिति की कई सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है। इनमें मेक इन इंडिया अभियान के तहत नेट फॉरेन एक्सचेंज के कंप्यूटेशन का प्रस्ताव भी शामिल है। कल्याणी समिति का गठन मंत्रालय ने मौजूदा एसईजेड नीति की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया था। समिति ने नवंबर, 2018 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं।

पिछले छह महीने में 30 फीसद कम बिका सोना

चेन्नई, प्रेट्र : पिछले छह महीने में सोने की मांग में 30 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने यह जानकारी दी। इस अवधि में कुछ कारोबारियों ने कामकाज बंद करने का भी फैसला किया। उन्होंने कहा कि सेक्टर में आयात शुल्क और जीएसटी कम करने की मांग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष पहले ही उठाई जा चुकी है।

पद्मनाभन ने दावा किया कि आयात शुल्क बढ़ने और अधिक जीएसटी होने के चलते सोने की तस्करी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ग्राहक दुबई, नेपाल, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि आगामी बजट में सोने का आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए।

इस बीच, सराफा बाजारों में गिरावट का रुख बना हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली के प्रमुख सराफा बाजारों में सोना 80 रुपये गिरकर 40,554 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। इसके अलावा चांदी के दाम में भी 200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। यह 47,695 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बोली गई।

तीन महीने की गिरावट के बाद सुधरा कारखानों का उत्पादन

- नवंबर, 2019 में आइआइपी में दर्ज की गई 1.8 फीसद की वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तीन महीने लगातार उत्पादन में गिरावट के बाद नवंबर, 2019 में कारखानों में थोड़ी रौनक लौटी। इस महीने देश के कारखानों के उत्पादन में 1.8 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार से यह वृद्धि देखी गई।

सरकार की तरफ से शुक्रवार को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े (आइआइपी) जारी किए गए। सालभर पहले यानी नवंबर, 2018 में कारखानों के उत्पादन में 0.2 फीसद की वृद्धि देखी गई थी। नवंबर, 2019 में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में हालात कुछ सुधरे हैं। इस सेक्टर के उत्पादन में समीक्षाधीन अवधि में 2.7 फीसद की वृद्धि हुई है। सालभर पहले इसी अवधि में इसमें 0.7 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी।

इसके विपरीत बिजली उत्पादन में पांच फीसद की कमी हुई है। साल 2018 के नवंबर में बिजली के उत्पादन में 5.1 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। खनन सेक्टर की वृद्धि दर नवंबर, 2019 में 1.7 फीसद रही।

प्रतीकात्मक फोटो

नवंबर, 2018 में यह 2.7 फीसद थी।

हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले निवेश से जोड़कर देखे जाने वाले कैपिटल गुड्स सेक्टर में उत्पादन की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। नवंबर, 2019 में इस क्षेत्र के उत्पादन में 8.6 फीसद की गिरावट देखी गई है। सालभर पहले इसी अवधि में इस सेक्टर के उत्पादन में 4.1 फीसद की कमी आई थी। मांग की कमी के चलते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के उत्पादन में भी नवंबर, 2019 में कमी आई। इस सेक्टर के उत्पादन में 1.5 फीसद की गिरावट हुई है।

यस बैंक के हालात से चिंतित स्वतंत्र निदेशक उत्तम अग्रवाल का इस्तीफा

- स्वतंत्र निदेशक अग्रवाल ने सेबी चेयरमैन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की
- बैंक ने कहा, निदेशक बनाए रखने को लेकर समीक्षा का सामना कर रहे थे उत्तम
- इस्तीफे के बाद बैंक के शेयर पांच परसेंट तक लुढ़के

नई दिल्ली, प्रेट्र : यस बैंक के स्वतंत्र निदेशक उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने बैंक के खराब कामकाज और प्रशासनिक हाल पर चिंता जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। वहीं बैंक का कहना है कि निदेशक बनाए रखने को लेकर उत्तम पहले से ही आरबीआइ के निर्देशों के अनुरूप 'फिट एंड प्रॉपर' स्टेटस रिव्यू का सामना कर रहे थे। हालांकि बैंक ने कहा है कि अग्रवाल की ओर से उठाई गई चिंताओं पर गौर किया जाएगा। अग्रवाल बैंक की ऑडिट कमेटी के प्रमुख भी थे।

अग्रवाल ने पत्र लिखकर सेबी प्रमुख अजय त्यागी से बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप की मांग भी की है। अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह से सीईओ और एमडी रवनीत गिल सहित शीर्ष अधिकारी बैंक का कामकाज चला रहे हैं, वह चिंताजनक है। उन्होंने बैंक के छोटे-बड़े खाताधारकों, निवेशकों और साझेदारों के हित में आवाज उठाने और अव्यवस्था को सुधारने की हरसंभव कोशिश करने की बात कही है।

सेबी को लिखे गए पत्र में अग्रवाल ने कहा है कि बैंक के सीईओ ने पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को हुई बैठक में एक ग्लोबल निवेशक से 120 करोड़ डॉलर (करीब 8,500 करोड़ रुपये) निवेश का आश्वासन मिलने की बात मौखिक रूप से कही। लेकिन इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। अग्रवाल ने कहा कि बैंक के सीईओ की इस भ्रामक घोषणा के चलते कुछ लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचा और निवेशकों को गलत जानकारी देकर धोखे में रखा गया।

स्वतंत्र निदेशक अग्रवाल के अचानक इस्तीफे की खबर के बाद बैंक के शेयरों में पांच परसेंट से अधिक की गिरावट देखी गई। बीएसई में यस बैंक के शेयर 5.29 गिरकर 44.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। एनएसई में भी बैंक के शेयरों में गिरावट आई। एनएसई में बैंक के शेयर 4.96 परसेंट तक टूट गए।

यस बैंक में राणा कपूर की हिस्सेदारी खत्म

मुंबई, आइएएनएस : यस बैंक में राणा कपूर की हिस्सेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। कपूर ने पिछले कुछ महीनों के दौरान धीरे-धीरे बैंक में अपने और अपनी सहायक कंपनियों के सभी शेयर बेच दिए हैं। इसके साथ ही बैंक में वोटिंग सहित उनके सारे अधिकार खत्म हो गए हैं। यस बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि राणा कपूर की समूची 3.92 परसेंट और उनके स्वामित्व वाली यस कैपिटल की 0.8 परसेंट हिस्सेदारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब बैंक में पब्लिक की हिस्सेदारी 91.67 परसेंट हो गई है। गौरतलब है कि यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर कहा करते थे कि वह बैंक में अपने शेयर कभी नहीं बेचेंगे। यस बैंक के शेयरों को वह हीरा कहते थे।

बिगड़े हाल

सभी तरह के वाहनों की बिक्री में तकरीबन 14 फीसद की गिरावट, चालू वर्ष के दौरान बीएस-6 की वजह से महंगे होंगे वाहन

बीते साल को भुला देना चाहेगा घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछला वर्ष संभवतः देश के ऑटोमोबाइल उद्योग के इतिहास में सबसे खराब रहा है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 2020 में भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले इस सेक्टर की बिक्री में खास वृद्धि के संकेत नहीं मिल रहे हैं। खास तौर पर उत्सर्जन के लिए तय नवीनतम बीएस-छह मानक लागू होने के बाद वाहनों की कीमतों में आठ से 10 फीसद की वृद्धि होने का असर भी सेक्टर की बिक्री पर दिखाई देगा। यह बात ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़े संगठन सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स) ने कही है।

2019 के दौरान देश में सभी तरह के वाहनों की बिक्री में 13.77 फीसद की कमी आई। सालभर पहले के 2,67,58,787 वाहनों की तुलना में 2019 में 2,30,73,438 वाहन बिके। हालांकि ऑटो बाजार की इस मंदी जैसे हालात के बावजूद देश की कार कंपनियों में आगामी ऑटो शो (ऑटो एक्सपो-2020) को लेकर उत्साह है। चीन की ऑटो कंपनियों की तरफ से भी इसमें बड़े पैमाने पर शिरकत करने की तैयारी है।

देश की आर्थिक विकास दर में सुधार के बाद ही सेक्टर को राहत की उम्मीद। प्रतीकात्मक फोटो

सियाम के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने 1997 से कार उद्योग का डाटा जुटाना शुरू किया है और उसके बाद से किसी भी वर्ष में ऐसी मंदी नहीं दिखी है। उसके पहले के वर्षों में भी शायद ऐसी मंदी दिखी हो जब भारत जैसे मध्यम वर्ग वाले देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14.19 फीसद की गिरावट देखी गई हो। इसके पहले 2013 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 7.49 फीसद की सबसे बड़ी गिरावट हुई थी। भारत में रोजगार में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले दोपहिया वाहन ही खरीदता है। ऐसे में ये आंकड़े पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताते हैं। पैसेंजर कारों की बिक्री में भी 12.75 फीसद की गिरावट हुई है। 2019 में कुल 29,62,052 कारों की बिक्री हुई है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री 8.54 लाख रही। इसमें 15 फीसद की गिरावट देखी गई।

चालू वित्त वर्ष में यह मंदी दूर होने के सवाल पर सियाम के अध्यक्ष रंजन वढेरा ने कहा कि अभी तक इसके संकेत नहीं मिले हैं। आर्थिक विकास दर की रफ्तार पूरी तरह से नीचे है जो सीधे तौर पर ज्यादातर वाहनों की बिक्री से जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास दर बढ़ने के साथ ही वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। दूसरी समस्या यह है कि दो महीने बाद से बीएस-छह वाहनों की बिक्री शुरू होगी। बीएस-छह मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें कम से कम आठ से 10 फीसद बढ़ेंगी। इससे बिक्री पर उलटा असर दिख सकता है।

ऑटो एक्सपो का उत्साह कायम

इस मंदी से ऑटो एक्सपो पर पड़ने वाले असर पर सियाम अध्यक्ष रंजन वढेरा ने जवाब दिया, 'कार उद्योग मुसीबत में है लेकिन ऑटो एक्सपो को लेकर कंपनियों के बीच उत्साह बना हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों व एसयूवी को लेकर कुछ अहम घोषणाएं होंगी। साथ ही बीएस-6 को लेकर भी कंपनियां अपनी रणनीति दिखाएंगी।' टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को बताया कि वह आगामी ऑटो एक्सपो के दौरान 26 वाहनों का प्रदर्शन करेगी। वहीं, फॉक्सवैगन ने बताया है कि वह चार नए एसयूवी भारतीय बाजार के लिए इसमें पेश करेगी। मारुति सुजुकी की तरफ से कम से कम आधा दर्जन नए वाहनों का प्रारूप पेश किया जाएगा। ह्यूंडई की तरफ से भी नई क्रेटा, आइ-20 व चार नए वाहन पेश करने की तैयारी है।

इलेक्रामा 2020 में दिखेगी ऊर्जा क्षेत्र के नए युग की झलक

नई दिल्ली, (वि.) : इलेक्रामा 2020 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले वर्षों में इलेक्रामा ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में एक नॉलेज-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 18 से 22 जनवरी, 2020 के बीच यह आयोजन होगा। इलेक्रामा 2020 के चेयरमैन अनिल साबू ने कहा कि यहां भारतीय कंपनियों की उच्च गुणवत्ता और अन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाता है। इलेक्रामा 2020 में 60 देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 120 देशों के विजिटर हिस्सा लेंगे। एक लाख वर्गमीटर से ज्यादा में होने वाली इस प्रदर्शनी में स्पेशल पैवेलियन और कांफ्रेंस की व्यवस्था रहेगी। इस बार की थीम इलेक्ट्रिसिटी के नए युग के विकास पर केंद्रित है। यह आयोजन इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से किया जाता है।

231 के मुकाबले 330 मतों से आखिरकार ब्रेक्जिट को मंजूरी प्रदान कर दी है ब्रिटेन की संसद ने। इस महीने के आखिर तक ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बन जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन की जनता ने 2016 में हुए जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट पर मुहर लगाई थी।

अकबरुद्दीन ने कहा– पाकिस्तान का मालवेयर लेने वाला कोई नहीं है

- पाक ने सुरक्षा परिषद में फिर उठाया कश्मीर मामला
- भारत ने पड़ोसी देश को बताया बुराई का प्रतीक
- कहा–फिर झूठ का प्रचार कर रहा है पड़ोसी देश

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन। एएनआइ

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर पलटवार करते हुए भारत ने कहा कि वह खुद बुराई का प्रतीक है और उसका मालवेयर लेने वाला कोई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने जो खुद बुराई का प्रतीक है। उसने आज फिर झूठ का प्रचार किया है, जिसे हम तिरस्कार के साथ खारिज करते हैं।

सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उपयोग विषय पर खुली बहस के दौरान अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान को मेरा सरल जवाब है कि भले ही देर हो चुकी है, वह अपने आप को ठीक कर ले। उसका मालवेयर लेने वाला यहां कोई नहीं है।

अकबरुद्दीन का यह कड़ा प्रतिवाद पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम द्वारा जम्मू-कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद आया। अकरम ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 हटाने, कश्मीर में संचार माध्यमों पर प्रतिबंध और भारत द्वारा किए गए हवाई हमले के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस से भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक लड़ाई रोकने के लिए दृढ़ता से काम करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की असफल कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना पूरी तरह उसका घरेलू मामला है।

अकबरुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि यह ध्यान देने की बात है कि 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद पहचान और वैधता के संकट से जूझ रही है। इसके अलावा प्रासंगिकता और प्रदर्शन का सवाल भी इसके सामने है। आतंकी नेटवर्क का वैश्वीकरण, नई प्रौद्योगिकियों वाले हथियार, विध्वंस के लिए राज्य का सहारा लेने वालों का मुकाबला करने में असमर्थता परिषद की कमियों को दिखा रही है।

हैरी–मेगन मामले के समाधान में जुटीं महारानी एलिजाबेथ

- कहा– हफ्तों नहीं, कुछ दिनों में हल निकालें शाही परिवार के सभी सदस्य
- दंपती के शाही परिवार की भूमिका से हटने के एलान से आहत हैं सभी

लंदन, आइएएनएस : प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन के एलान से ब्रिटेन के शाही परिवार में उभरे संकट को दूर करने के लिए 93 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सामने आना पड़ा है। उन्होंने शाही परिवार के सभी सदस्यों को हिदायत दी है कि वे हैरी-मेगन मामले का हफ्तों नहीं बल्कि कुछ दिनों में व्यावहारिक समाधान निकालें। ड्यूक और डचेज ऑफ ससेक्स की उपाधि रखने वाले हैरी और मेगन ने शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य की भूमिका से हटने का एलान कर सबको चौंका दिया है। उनके इस फैसले से ना सिर्फ महारानी बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी आहत बताए जा रहे हैं।

ब्रिटेन की मेट्रो न्यूज वेबसाइट ने बकिंघम पैलेस सूत्रों के हवाले से बताया है कि शाही परिवार हैरी और मेगन को मनाने के प्रयास में जुट गया है। हैरी और मेगन ने बुधवार को कहा था, 'हम शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से हटना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए काम करना चाहते हैं। महारानी को हमारा पूरा समर्थन मिलता रहेगा।' खबर यह भी है कि इस शाही जोड़े ने महारानी के मना करने के बावजूद सार्वजनिक तौर पर अपने इस फैसले की घोषणा की।

ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम के दौरान प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन। फाइल/ रायटर

पिता और भाई को दस मिनट पहले मिली थी जानकारी : ईवनिंग स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार, हैरी के पिता प्रिंस चार्ल्स और भाई प्रिंस विलियम को ड्यूक व डचेज ऑफ ससेक्स के फैसले की जानकारी उनका बयान जारी होने से महज दस मिनट पहले मिली थी। प्रिंस चार्ल्स को उम्मीद है परिवार में उभरा यह संकट जल्द ही दूर हो जाएगा।

बेटे आर्ची के साथ रहने कनाडा गईं मेगन

शाही परिवार में उपजे विवाद के बीच मेगन अपने आठ माह के बेटे के साथ रहने के लिए कनाडा चली गई हैं। हैरी और मेगन के बेटे आर्ची हैरिसन का जन्म गत वर्ष छह मई को हुआ था। डेली मेल अखबार के अनुसार, हैरी और मेगन कनाडा में छह हफ्ते की छुट्टियां बिताने के बाद आर्ची को नैनी (आया) के पास छोड़कर पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन लौटे थे। पूर्व अमेरिकी टीवी अभिनेत्री मेगन गुरुवार को फिर कनाडा चली गईं।

न्यूज गैलरी

ट्रंप ने किम को भेजा जन्मदिन का बधाई संदेश

सियोल : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आठ जनवरी को उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग–उन के जन्मदिन पर उन्हें बधाई संदेश भेजा था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग यूई–योंग ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर बातचीत के लिए योंग इस हफ्ते अमेरिका गए थे। योंग के अनुसार, बीते बुधवार को वाशिंगटन में उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी। योंग ने कहा, ट्रंप को किम का जन्मदिन याद था। उन्होंने अपना बधाई संदेश मुझे किम तक पहुंचा देने को कहा था। योंग ने हालांकि इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह लिखित संदेश था या इसमें जन्मदिन की शुभकामनाओं के अलावा कुछ और भी शामिल था। ट्रंप से मुलाकात के बाद इसी दिन योंग ने उत्तर कोरिया पर विशेष अमेरिकी दूत स्टीफन बीगन से भी मुलाकात की थी। (रायटर)

सिंगापुर को एफ–35 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका

सिंगापुर : अमेरिकी सरकार ने सिंगापुर को एक दर्जन अत्याधुनिक एफ–35 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अमेरिका से 2.75 अरब डॉलर (करीब 20 हजार करोड़ रुपये) के इस रक्षा सौदे की घोषणा सिंगापुर ने पिछले साल की थी। रक्षा विभाग पेंटागन से अनुमोदन मिलते ही सौदे के मसौदे को गुरुवार को अमेरिकी संसद की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। मसौदे पर संसद की जल्द मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा, सिंगापुर अमेरिका का रणनीतिक साझीदार और सुरक्षा सहयोगी है। इसके अलावा एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर की भूमिका अहम है। सिंगापुर एफ–35 लड़ाकू विमान से लैस होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का चौथा देश होगा। (आइएएनएस)

अमेरिका में धोखाधड़ी का भारतीय ने कुबूला जुर्म

न्यूयॉर्क : अमेरिका में कॉल सेंटर के जरिये लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले भारतीय हितेश मधुभाई पटेल (43) ने ह्यूस्टन की अदालत में अपना जुर्म स्वीकार लिया। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, हितेश ने भारत में संचालित अपने कॉल सेंटर के जरिये अमेरिकियों से बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की थी। वह अन्य लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद स्थित कॉल सेंटर से फोन कर अमेरिकी लोगों को डरा–धमका कर धन ऐंठने का काम करता था। फोन पर कॉल सेंटर के लोग खुद को अमेरिकी अधिकारी बताते थे। इसके बाद अमेरिका में रह रहे अपने लोगों के माध्यम से हितेश धन की अवैध वसूली करता था। पिछले साल हितेश को सिंगापुर में पकड़ा गया था, जहां से उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। (आइएएनएस)

ट्रंप के अधिकार पर रोक का प्रस्ताव पारित

बड़ा मामला ▸ प्रतिनिधि सभा ने ईरान से युद्ध के प्रति जताई अनिच्छा

सीनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आएगी कमी

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से युद्ध के प्रति अपनी अनिच्छा जता दी। सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमला करने के अधिकार पर भी प्रतीकात्मक रोक लगा दी। यह प्रस्ताव अभी सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में भी जाना है, जहां इसके पारित होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर वहां भी यह प्रस्ताव पारित हो गया तब भी राष्ट्रपति के पास इसकी अनदेखी करते हुए युद्ध की घोषणा करने का अधिकार रहेगा।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में कमोबेश पार्टी लाइन पर ही मतदान हुआ। ट्रंप के अधिकार पर रोक के समर्थन में 224 मत पड़े जबकि विरोध में 194 मत पड़े। हां, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के तीन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। इनमें से एक मैट गेट्ज को ट्रंप का प्रबल समर्थक माना जाता है। संसद में अपने भाषण में मैट ने कहा, यह प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रंप की किसी मायने में आलोचना नहीं करता बल्कि मध्य-पूर्व की लड़ाई में फिर से फंसने से बचाना चाहता है। हमारे सैनिकों के पास लड़ने और बलिदान करने का हौसला है लेकिन हम उनके हौसले का सम्मान करते हुए उन्हें नए युद्ध में जाने से रोकना चाहते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

संसद में युद्ध छेड़ने के राष्ट्रपति के अधिकार पर बहस चल रही थी तो बाहर ट्रंप ने कहा, उन्हें हमला करके युद्ध छेड़ने का शौक नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो वह उसके विषय में संसद से मशविरा करेंगे। ट्रंप ने बुधवार को ही संकेत दिया था कि वह ईरान से युद्ध नहीं करने जा रहे लेकिन इसके लिए ईरान को भी संयम दिखाना होगा। बता दें कि इस महीने के प्रारंभ में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था।

अज्ञात विमानों से सीरिया में हमला, आठ मिलिशिया मरे

बेरुत, एपी : सीरिया में इराक सीमा से सटे क्षेत्र में अज्ञात विमानों ने शुक्रवार को कई ठिकानों पर हमला किया। हमले में ईरान समर्थित आठ इराकी मिलिशिया मारे गए। सीरियाई कार्यकर्ता और इराकी अधिकारियों ने इजरायली विमानों से हमला होने का संदेह जताया है।

मानवाधिकार पर नजर रखने वाले सीरियाई संगठन ने कहा कि विमानों ने बौकामाल इलाके में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाया। सीरिया में युद्ध का दस्तावेज तैयार कर रहे ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा कि विमानों ने मिलिशिया के अन्य ठिकानों, हथियारों और वाहनों को भी निशाना बनाया। एक इराकी सुरक्षा अधिकारी और मोबलाइजेशन फोर्स के नाम से ज्ञात ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने मिसाइल ले जा रहे दो वाहनों को भी निशाना बनाया। यह हमला इजरायली विमानों ने किया होगा, लेकिन अधिकारियों ने इसका कोई सुबूत नहीं दिया। इजरायली सेना ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

सैनिकों की वापसी पर अमेरिका का वार्ता से इन्कार

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका ने शुक्रवार को इराक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें इराकी धरती से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए वार्ता का अनुरोध किया गया था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने वार्ता के लिए इराकी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेजने के लिए कार्यक्रम मांगा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टगस ने कहा, इस समय फौज वापसी पर वार्ता के लिए किसी प्रतिनिधिमंडल का आना हमारे रणनीतिक सहयोग के लिए उचित नहीं होगा।

जर्मनी ने ठुकराया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अनुरोध

बर्लिन, एएफपी : ईरान के साथ शक्तिशाली देशों के 2015 में हुए परमाणु समझौते को जर्मनी अभी भी बनाए रखना चाहता है। जर्मनी ने यह इच्छा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध को दरकिनार कर जताई है जिसमें यूरोपीय देशों से ईरान के परमाणु समझौते से अलग हटने के लिए कहा गया था। समझौते पर जर्मनी के अलावा यूरोपीय देश फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दस्तखत किए थे।

'ईरानी मिसाइल ने ही मार गिराया था यूक्रेनी विमान'

- कनाडाई पीएम के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी जताया अंदेशा

ओटावा, एजेंसियां : ईरान की राजधानी तेहरान में बीते बुधवार को हुए यूक्रेनी विमान हादसे के पीछे मिसाइल हमले के अंदेशे को बल मिलने लगा है। अमेरिका के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी यही अंदेशा जताया है। ट्रूडो ने कहा, विभिन्न खुफिया सूत्रों का संकेत है कि सतह से हवा में मार करने वाली ईरानी मिसाइल टोर ने ही विमान को मार गिराया था। इस घटना को लेकर अटकलें नहीं लगाने की अपील करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी यही अंदेशा जताया है। जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि मिसाइल हमले में ही विमान गिरने की आशंका है। इस बीच अमेरिका ने विमान हादसे पर यूक्रेन को अहम डाटा मुहैया कराया है।

तेहरान से कीव के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737-800 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार 63 कनाडाई नागरिकों समेत 176 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा इराक में दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले के कुछ समय बाद ही हुआ था। कनाडाई प्रधानमंत्री के इस बयान से पहले गुरुवार को एक वीडियो सामने आया, जिसमें विमान से कोई चीज टकराते दिखी। इस वीडियो में कोई चीज तेज गति से आती दिखी और फिर तेज रोशनी हुई। इसके कुछ सेकेंड बाद तेज धमाका सुना गया। सोशल मीडिया में पोस्ट की गई कुछ फुटेज से भी यही संकेत मिलता है कि ईरानी मिसाइल ने गलती से विमान को मार गिराया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के साथ ही मित्र देशों की खुफिया जानकारियों के आधार पर कहा, 'हम जानते हैं कि यह गलती से हो सकता है। लेकिन कनाडा के नागरिकों का यह सवाल है, जिसका उन्हें जवाब पाने का हक है।' डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे तकनीकी गड़बड़ी की बात पर यकीन नहीं है।

ईरान ने हादसे की जांच के लिए बोइंग को बुलाया

तेहरान, एपी : ईरान ने विमान हादसे की जांच के लिए बोइंग को आमंत्रित किया है। ईरान ने यह कदम पश्चिमी देशों के नेताओं के इस अंदेशे के बाद उठाया है कि ईरान की मिसाइल ने अनजाने में विमान को मार गिराया। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली आबिदजादा ने हालांकि इस अंदेशे को खारिज करते हुए कहा, यकीनन ऐसा नहीं हुआ था। इस बीच खबर यह भी है कि अब तक इन्कार करता आ रहा ईरान विमान के ब्लैक बॉक्स का डाटा देने को तैयार हो गया है।

आतंकी फंडिंग मामले में पाक अदालत में गवाहों से जिरह पूरी

- मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर आतंकी फंडिंग का है आरोप

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह पूरी कर ली है। जिन लोगों से जिरह की गई है, उनमें राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं।

आतंकरोधी अदालत-1 ने सईद और उसके सहयोगियों-हाफिज अब्दुल सलाम, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ 11 दिसंबर को आतंकी फंडिंग का अभियोग लगाया था। छह घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि सईद और उसके सहयोगियों के वकीलों ने लाहौर के आतंकरोधी अदालत-1 में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह पूरी कर ली। अभियोजन पक्ष ने बड़ी संख्या में गवाह पेश किया था। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने बचाव पक्ष के वकीलों-नसीरुद्दीन नय्यर और मुहम्मद इमरान फजल गुल को शुक्रवार से अपने गवाह पेश करने के लिए कहा।

इसके अतिरिक्त आतंकरोधी अदालत-2 ने जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद और हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की के खिलाफ भी गवाहों का बयान दर्ज किए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित कर दी। राजस्व अधिकारियों ने लाहौर में जमात के केंद्रों, मदरसों और मस्जिदों का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। गवाहों ने कोर्ट को सईद द्वारा आतंकवाद के लिए धन एकत्रित करने की जानकारी दी। इस दौरान अदालत के बाहर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।

हाफिज सईद। फाइल

दुबई में रहने वाले भारतीयों को मिलेगा तत्काल पासपोर्ट

दुबई, आइएएनएस : दुबई और उत्तरी अमीरात में रहने वाले भारतीय अनिवासियों को अब आवेदन के दिन ही तत्काल पासपोर्ट मिल सकेंगे। हालांकि इसमें अधिक शुल्क सहित कुछ शर्तें शामिल होंगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान गुरुवार को यह घोषणा भारत के महावाणिज्य दूत विपुल ने की। उन्होंने कहा कि दोपहर से पहले बीएलएस इंटरनेशनल के कार्यालय में आवेदन करने पर ही तत्काल पासपोर्ट जारी किया जा सकेगा।

बता दें कि दुबई के अली खलीज सेंटर स्थित बीएलएस इंटरनेशनल भारतीय पासपोर्ट और वीजा आवेदनों के लिए आउटसोर्स प्रदाता कंपनी है। महावाणिज्य दूत ने कहा कि 24 घंटे में तत्काल पासपोर्ट जारी करने की सेवा पहले से ही जारी है अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। अब हम आवेदन के दिन ही तत्काल पासपोर्ट जारी कर देंगे, लेकिन इसके लिए दोपहर 12 बजे से पहले आवेदन करना होगा। ऐसी स्थिति में हम शाम तक तत्काल पासपोर्ट जारी कर देंगे। दूतावास को प्रतिदिन पासपोर्ट के लिए 850 आवेदन मिलते हैं।

'मंगेतर ने ही रची थी सिख युवक की हत्या की साजिश'

- सात लाख रुपये में भाड़े के हत्यारों को दी थी सुपारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
- पहले थी शादी को राजी, फिर मुस्लिम लड़के से प्यार के चलते बदला इरादा

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान की पुलिस ने दावा किया है कि सिख युवक परविंदर की हत्या की साजिश उसकी 18 साल की मंगेतर प्रेम कुमारी ने रची थी। उसने इसके लिए भाड़े के हत्यारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में युवती ने बताया कि वह परविंदर से शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

पिछले शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शादी की खरीदारी करने मलेशिया से आए परविंदर की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिख युवक की हत्या की भारत ने भी कड़ी निंदा की थी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। इस घटना के एक दिन पहले ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ ने हमला कर दिया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि परविंदर और प्रेम कुमारी एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनकी सगाई सहमति से हुई थी। दोनों ने 28 जनवरी को होने वाली शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन बाद में प्रेम कुमारी की दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हो गई जो उसकी सहेली का भाई था। इसके बाद प्रेम कुमारी ने अपने दोस्त के माध्यम से भाड़े के हत्यारों से संपर्क किया और परविंदर को मारने के लिए सात लाख रुपये की सुपारी दी। कुछ पैसा उसने एडवांस भी दिया जबकि बाकी पैसा हत्या के बाद देने को कहा था। पुलिस ने बताया कि प्रेम कुमारी ने परविंदर को मरदान बुलाया और उसे अपने घर ले गई जहां प्रेम के दोस्त ने अपने साथियों संग मिलकर परविंदर की हत्या कर दी। बाद में हत्यारे परविंदर के शव को पेशावर लाए और एक खेत में फेंक दिया। पुलिस को पांच जनवरी को उसका शव मिला था। प्रेम कुमारी का परिवार मरदान के मोहल्ला शेरदाद अबद में रहता है। उसके पिता हिंदू और मां सिख हैं। पुलिस इस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

पाकिस्तान की मस्जिद में विस्फोट, डीएसपी समेत 15 की मौत

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को मस्जिद में हुए बम विस्फोट में एक पुलिस अधिकारी समेत 15 लोग मारे गए और 20 घायल हुए हैं। तीन दिन पहले नजदीक के क्वेटा शहर में भी बम विस्फोट की घटना हुई थी जिसमें दो लोग मारे गए थे।

गौसाबाद की मस्जिद में किस तरह का बम फटा, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। क्वेटा के डीआइजी अब्दुल रज्जाक चीमा ने विस्फोट में डीएसपी अम्मानउल्ला के मारे जाने की पुष्टि की है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच का काम शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ मिलकर सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। घटनास्थल के टीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि विस्फोट शक्तिशाली था जिसके चलते मस्जिद की इमारत को काफी नुकसान हुआ है और उसका बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि सच्चा मुस्लिम कभी भी मस्जिद को निशाना नहीं बना सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

चिंताजनक

आग प्रभावित इलाकों में अगले कुछ घंटे चुनौतीपूर्ण, सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया

ऑस्ट्रेलिया में ढाई लाख लोगों से घर छोड़ने को कहा गया

सिडनी, रायटर : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण विक्टोरिया प्रांत के ढाई लाख लोगों से घर छोड़ देने को कहा गया है। अगले कुछ घंटे चुनौती भरे होने के कारण सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने इसकी पुष्टि की है। जलवायु परिवर्तन पर सरकारी निष्क्रियता के विरोध में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। गत अक्टूबर से अब तक जंगलों में लगी आग की चपेट में आकर 27 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। आग से एक करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन प्रभावित है, जो दक्षिण कोरिया के क्षेत्रफल के बराबर है।

विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्यूज ने कहा, हालांकि मेलबर्न में बारिश हुई है और अगले सप्ताह अच्छे मौसम की उम्मीद है, लेकिन अब भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। शनिवार सुबह तक तेज हवाएं चलने की उम्मीद के चलते अगले कुछ घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे हाई अलर्ट पर रहें और अगर कहा जाए तो घरों को छोड़ दें। प्रशासन ने विक्टोरिया में रहने वाले दो लाख चालीस हजार लोगों को आपातकालीन मैसेज भेजकर घर छोड़ने को कहा है। न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के लोगों को भी घर छोड़ने के बारे में सोचने के लिए कहा गया है।

विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे पशु-पक्षी : वन्यजीव बचाव समूह 'वायर्स' के लिए काम करने वाली सारा प्राइस को जब कुछ दिनों पहले अंगारों में मृत पड़ी मादा कंगारू की थैली में एक शावक जिंदा मिला तो उन्हें उसका नाम 'चांस' रखना उचित लगा। अब 'चांस' धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस आग से पशु-पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। सिडनी विश्वविद्यालय के मैथ्यू क्रोसर ने बताया कि आग लगने के बाद बहुत से जानवर भोजन और आश्रय की कमी के चलते मर गए। मेंढक, कीड़े और सरीसृप वर्ग के तमाम जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ रैली : जंगलों की आग से प्रदूषण की गहन समस्या का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल ठोस कदम उठाए जाने की मांग को लेकर जलवायु कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर–पोस्टर लिए हुए थे। आग की वजह से दक्षिण–पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दो हजार से अधिक घर जल गए हैं, जबकि कंगारू द्वीप में हजारों कोआला मारे जा चुके हैं। एएफपी

अफगानिस्तान में फिर गिने जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए वोट

- 18 प्रांतों के 1,645 मतदान केंद्रों में शनिवार से शुरू होगा काम

काबुल, आइएएनएस : राष्ट्रपति चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों के बीच अफगानिस्तान के स्वतंत्र निर्वाचन शिकायत आयोग (आइईसीसी) ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग 18 प्रांतों के 1,645 मतदान केंद्रों में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डाले गए वोटों को अब फिर गिनेगा। यह काम शनिवार से शुरू होगा।

आयोग के प्रवक्ता कासिम इलयासी ने गुरुवार को कहा, संदिग्ध मतपत्रों और बिना किसी वजह के वोट निरस्त करने जैसे कारणों के चलते मतों की दोबारा गिनती करने का निर्णय लिया गया है। जिन मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती दोबारा की जानी है, वे नांगरहार, कुनार और निमरोज में पड़ते हैं। आठ अन्य प्रांतों में अनियमितता की जांच चल रही है। आइईसीसी को दो सप्ताह में अपना काम पूरा करके पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र चुनाव आयोग के साथ साझा करना होगा। राष्ट्रपति चुनाव के प्रारंभिक नतीजे पिछले साल 19 अक्टूबर को घोषित किए जाने थे। लेकिन अनियमितताओं के आरोपों के चलते इसमें देरी हुई। अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक अंतिम परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जा सकते जब तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हो जाता। पिछले साल 28 सितंबर को हुए चुनाव के नतीजे गत दिसंबर में जारी किए गए।

राष्ट्रपति मुहम्मद अशरफ गनी को प्रारंभिक परिणामों में 50.64 फीसद वोट मिले थे और वे दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वहीं गनी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और सरकार के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला को 39.52 प्रतिशत वोट मिले थे। हिज्ब-ए-इस्लामी पार्टी के गुलबुद्दीन हिकमतयार सिर्फ 3.85 फीसद वोट हासिल कर सके थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। बाद में चार लोग मुकाबले से हट गए थे।

ये भी जानिए

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 चौके पूरे किए। वह ऐसा करने वाले पहले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। भारत के ही रोहित शर्मा 234 चौकों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं।

भारत ने श्रीलंका को धो दिया

भारत ने 2-0 से अपने नाम की सीरीज, तीसरा टी-20 मैच 78 रनों से जीता

पुणे, प्रेट्र : जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, भारत ने कमजोर श्रीलंका को आसानी से पराजित करते हुए तीन टी-20 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। वह तो शुक्र है कि गुवाहाटी में हुआ पहला मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था नहीं तो श्रीलंका को और ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ता। भारत ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में 78 रनों से जीत हासिल की। इंदौर में दूसरा मैच सात विकेट से जीतने वाली भारतीय टीम अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त थी कि उसने रिषभ पंत, कुलदीप यादव और शिव दुबे की जगह संजू सैमसन, युजवेंद्रा सिंह चहल और मनीष पांडे को मौका देना मुनासिब समझा। श्रीलंका ने भी अपनी टीम में दो बदलाव करके एंजेलो मैथ्यूज को अंतिम एकादश में जगह दी लेकिन उसकी टीम के लिए यह दांव भी उल्टा पड़ा। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम सिर्फ 15.5 ओवर में 123 रनों पर सिमट गई। नवदीप सैनी ने तीन विकेट चटकाए।

राहुल और धवन की तूफानी पारी : भारतीय ओपनर केएल राहुल (54) और शिखर धवन (52) ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। इन दोनों के सामने तो श्रीलंकाई कप्तान और यॉर्कर किंग लसित मलिंगा भी बेबस नजर आ रहे थे। अच्छी लय में दिख रहे धवन को स्पिनर संदाकन लक्षण ने दनुष्का गुणातिलका के हाथों कैच कराकर भारत को पहला झटका दिया। धवन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 36 गेंदों पर सात चौके और एक छक्का लगाया। धवन के आउट होने के बाद चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे संजू सैमसन भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। उन्हें वनिंदु हसरंगा ने पगबाधा आउट किया। रिषभ पंत की जगह मौका पाए सैमसन के पास अच्छा मौका था लेकिन वह दो गेंदों पर एक छक्के की मदद से छह रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके ऊपर कुछ करने का दबाव साफ नजर आ रहा था। इसके बाद भारत ने जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवाए। राहुल के रूप में भारत ने अपना तीसरा तो अय्यर के रूप में चौथा विकेट गंवाया। इन दोनों को संदाकन ने ही आउट किया। संजू और मनीष पांडेय को मौका देने के चक्कर में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान विराट कोहली उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। वह 26 रन बनाकर रनआउट हुए। वाशिंगटन सुंदर खाता भी नहीं खोल पाए। मनीष पांडे ने मौके का फायदा उठाया और 18 गेंदों पर चार चौकों की मदद से शानदार 31 रन बनाए। श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत इतनी खराब थी कि भारतीय गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने भी आखिरी क्षणों में हाथ खोलते हुए सिर्फ आठ गेंदों पर पर दो छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 22 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से संदाकन लक्षण ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए।

श्रीलंका की लचर बल्लेबाजी : लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। उसने 26 रन पर ही चार विकेट गंवा दिए। भारत की तेज गेंदबाजी तिकड़ी जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी ने शीर्ष तीन विकेट हासिल किए। मेहमानों के पास इसका कोई तोड़ नहीं था और यहीं से उसकी हार तय हो गई थी। 16 महीने बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेलने उतरे पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज (31) ने धनंजय डिसिल्वा (57) ने कुछ कोशिश की लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद सबकुछ खत्म हो गया। इन दोनों के अलावा कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका।

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 में अविष्का फर्नांडो का विकेट हासिल करने के बाद शार्दुल ठाकुर (बीच में) को बधाई देते भारतीय टीम के खिलाड़ी। एपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : श्रीलंका (गेंदबाजी) मैन ऑफ द मैच : शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द सीरीज : नवदीप सैनी

भारत 201/6 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लोकेश राहुल स्टं. परेरा बो. संदाकन	54	36	05	01
धवन का. गुणातिलका बो. संदाकन	52	36	07	01
संजू सैमसन एलबीडब्ल्यू बो. हसरंगा	06	02	00	01
मनीष पांडे नाबाद	31	18	04	00
श्रेयस अय्यर का. एवं बो. संदाकन	04	02	01	00
कोहली रन आउट (गुणातिलका/परेरा)	26	17	02	01
वाशिंगटन सुंदर का. संदाकन बो. कुमारा	00	01	00	00
शार्दुल ठाकुर नाबाद	22	08	01	02

अतिरिक्त : (लेबा-2, वा-4) 6

कुल : 20 ओवर में छह विकेट पर 201 रन

विकेट पतन : 1-97 (धवन, 10.5), 2-106 (संजू, 11.3), 3-118 (राहुल, 12.3), 4-122 (अय्यर, 12.5), 5-164 (कोहली, 17.3), 6-164 (सुंदर, 17.4)

गेंदबाजी :
लसित मलिंगा 4-0-40-0
एंजेलो मैथ्यूज 3-0-38-0
धनंजय डिसिल्वा 1-0-13-0
लाहिरु कुमारा 4-0-46-1
वनिंदु हसरंगा 4-0-27-1
लक्षण संदाकन 4-0-35-3

श्रीलंका 123 (15.5 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
गुणातिलका का. सुंदर बो. बुमराह	01	02	00	00
अविष्का फर्नांडो का. अय्यर बो. ठाकुर	09	07	00	01
कुशल परेरा बो. सैनी	07	10	01	00
ओशादा फर्नांडो रन आउट (पांडे)	02	05	00	00
एंजेलो मैथ्यूज का. पांडे बो. सुंदर	31	20	01	03
धनंजय डिसिल्वा का. बुमराह बो. सैनी	57	36	08	01
दासुन शनाका का. एवं बो. ठाकुर	09	09	00	01
वनिंदु हसरंगा रन आउट (चहल)	00	02	00	00
लक्षण संदाकन स्टं. संजू बो. सुंदर	01	02	00	00
लसित मलिंगा का. कोहली बो. सैनी	00	01	00	00
लाहिरु कुमारा नाबाद	01	01	00	00

अतिरिक्त : (बा-1, वा-4) 5

कुल : 15.5 ओवर में 123 रन पर ऑलआउट

विकेट पतन : 1-5 (गुणातिलका, 0.6), 2-11 (अविष्का, 1.3), 3-15 (ओशादा, 3.1), 4-26 (कुशल, 5.1), 5-94 (मैथ्यूज, 11.2), 6-110 (दासुन, 13.3), 7-110 (हसरंगा, 13.5), 8-118 (संदाकन, 14.6), 9-122 (धनंजय, 15.3)

गेंदबाजी :
जसप्रीत बुमराह 2-1-5-1
शार्दुल ठाकुर 3-0-19-2
नवदीप सैनी 3.5-0-28-3
वाशिंगटन सुंदर 4-0-37-2
युजवेंद्रा चहल 3-0-33-0

परिणाम : भारत 78 रन से जीता

कॉटरेल के छक्के से एक विकेट से जीता वेस्टइंडीज

ब्रिजटाउन (बारबाडोस), एएफपी : शेल्डन कॉटरेल (नाबाद 07) के छक्के की बदौलत वेस्टइंडीज ने गुरुवार को केनसिंगटन ओवल में दूसरे वनडे में आयरलैंड पर एक विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत से वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। उसने मंगलवार को इसी मैदान पर शुरुआती मैच पांच विकेट से जीता था। कॉटरेल ने 49वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मार्क एडेयर पर कवर की ओर छक्का जड़कर विजयी रन जुटाया, जिससे कैरेबियाई टीम ने नौ विकेट पर 242 रन बनाकर जीत हासिल की। कॉटरेल के अलावा पुछल्ले बल्लेबाज हेडन वाल्श ने अपने करियर के सातवें वनडे में नाबाद 46 रन की पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई।

आयरलैंड ने सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के 63 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 237 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। स्टर्लिंग ने अपने 24वें वनडे अर्धशतक में एक छक्का और सात चौके जमाए। वेस्टइंडीज के लिए तेज गेंदबाज अल्जारी जोसफ ने 32 रन देकर चार विकेट झटके और दो कैच भी लपके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम एक समय तीन विकेट पर 140 रन बना चुकी थी, लेकिन बारिश के कारण उत्पन्न हुई बाधा से उसकी लय टूट गई और उसने महज आठ रन के अंदर तीन विकेट खो दिए। निकोलस पूरन (52) और कप्तान कीरोन पोलार्ड (40) बारिश की बाधा के बाद एक भी रन जोड़े बिना पवेलियन लौट गए। पोलार्ड से बड़ी पारी की उम्मीद थी।

इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। पूरन ने 44 गेंद में छह चौके की मदद से अपना छठा वनडे अर्धशतक पूरा किया। ऑफ स्पिनर सिमी सिंह ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। पोलार्ड ने 32 गेंद में दो चौके और चार छक्कों के सहारे 40 रन बनाए। उन्हें बैरी मैकार्थी ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। खारे पियरे (18) ने आठवें विकेट के लिए वाल्श का साथ निभाया और 52 रन जोड़े। तीसरा और अंतिम मैच रविवार को ग्रेनाडा में खेला जाएगा।

सबसे तेज 11000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले कप्तान बने विराट कोहली

पुणे : विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कोहली ने लक्षण संदाकन की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर 11,000 का आंकड़ा पार किया। कोहली विश्व क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि महेंद्र सिंह धौनी ने हासिल की थी, जिन्होंने 324 पारियों में यह कीर्तिमान बनाया था। कोहली ने मात्र 196 पारियों में 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन बना डाले और इस सूची में पहले नंबर पर आ पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले कप्तानों की सूची में कोहली के बाद दूसरे नंबर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने 253 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ग्रीम स्मिथ (265), चौथे पर एलन बॉर्डर (316), पांचवें पर धौनी (324), और छठे नंबर पर स्टीफन फ्लेमिंग (333) हैं।

चार साल बाद टीम इंडिया के लिए टी-20 खेलने उतरे संजू के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड

पुणे : विकेटकीपर संजू सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ अंतिम एकादश में जगह बनाने के साथ ही दो मैचों के बीच सर्वाधिक मैचों में बाहर रहने का नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। सैमसन ने अपना एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 19 जुलाई 2015 को जिंबॉब्वे के खिलाफ हरारे में खेला था। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। इस बीच भारत ने 73 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और अब जाकर सैमसन को अवसर मिला है। इस तरह से भारत की तरफ से दो मैचों के बीच सर्वाधिक मैचों से बाहर रहने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड उमेश यादव के नाम पर था जो 2012 से 2018 के बीच 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेले थे। उनके बाद दिनेश कार्तिक (56) और मुहम्मद शमी (43) का नंबर आता है। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो डेनली के नाम पर है जो 2010 से 2018 के बीच 79 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर रहे थे। इंग्लैंड के ही लियाम प्लंकेट 74 मैचो के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

दिमाग से निकालना होगा बुमराह का हौव्वा : फिंच

मुंबई, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने शुक्रवार को कहा कि भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा वे अपने दिमाग में जसप्रीत बुमराह का हौव्वा नहीं बनाए रखें।

फिंच के अनुसार, भारत का यह प्रमुख तेज गेंदबाज सम्मान का हकदार है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान दें। फिंच ने कहा, 'मेरा मानना है कि खिलाड़ी जितना अधिक उनका सामना करेंगे उतना उन्हें पता चलता रहेगा कि वह कैसी गेंदबाजी करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इसको लेकर ज्यादा हौव्वा ना बनाएं।'

विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ पारी का आगाज करते हुए फिंच को बुमराह का सामना करना होगा। फिंच ने कहा, 'वह निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाज हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं कि जब आप उनके खिलाफ नहीं खेल रहे हो तो आप उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना पसंद करेंगे। वह तेज और आक्रामक गेंदबाज हैं और वह अपनी रणनीति पर बहुत अच्छी तरह से अमल करते हैं।'

बुमराह तीन महीने तक चोट से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम 14 जनवरी से मुंबई में शुरू होने वाली सीरीज में उनका सामना करने को लेकर सतर्क है। फिंच ने कहा, 'हम एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में क्या हैं, हमें इस पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक खिलाड़ी के कमजोर और मजबूत पक्ष होते हैं। इसलिए हमें मानसिक तौर पर इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।' दूसरा वनडे 17 जनवरी को राजकोट और तीसरा वनडे 19 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मार्नस लाबुशाने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे में पदार्पण के लिए तैयार हैं और उनका बुमराह की अगुआई वाले आक्रमण से रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। फिंच ने कहा, 'हां, यह मुकाबला रोमांचक होगा। हमने पिछले 12 महीनों में मार्नस के खेल में आमूलचूल सुधार देखा है और यह उनके स्कोर और टेस्ट क्रिकेट में छोड़े गए प्रभाव से भी पता चलता है। सीमित ओवरों में उनका घरेलू रिकॉर्ड शानदार है। उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज की उनकी फॉर्म वनडे में भी बरकरार रहेगी।' फिंच ने कहा कि भारत में उनके खिलाड़ियों को बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, 'भारत में आपको वास्तव में अपने बेसिक्स के साथ अनुशासित होना होगा।

फिंच ने कप्तानी के मामले में शून्य को भर दिया : मैकडोनाल्ड

मुंबई, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का मानना है कि आरोन फिंच एक क्रिकेटर के तौर पर काफी परिपक्व हो गए हैं और उन्होंने सीमित ओवरों में कप्तानी को लेकर पैदा हुए शून्य को भर दिया है। भारत के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज में जस्टिन लैंगर की जगह मैकडोनाल्ड कोच की भूमिका निभाएंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा, 'मेरा मानना है कि पिछले तीन साल में आरोन फिंच नेतृत्वकर्ता के रूप में काफी आगे बढ़े हैं। कप्तानी के मामले में ऑस्ट्रेलिया में जो शून्य पैदा हुआ था वह उन्होंने भर दिया है। उनका कप्तान के रूप में विकास शानदार है। खिलाड़ियों को लेकर उनकी समझ लाजवाब है। टीम में निरंतरता की बात करते हैं तो उनके पास लगभग एक ही टीम है। विश्व कप के बाद से एक-दो ही बदलाव हुए हैं। वह एक क्रिकेटर के रूप में परिपक्व हुए हैं।

कोहली की तरह सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं लाबुशाने

नई दिल्ली, प्रेट्र : फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज उन्हें विराट कोहली और स्टीव स्मिथ का अनुकरण करने की मुहिम में बड़ा मौका प्रदान करेगी। लाबुशाने ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार टेस्ट शतक जमाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक और एक दोहरा शतक पूरा किया। अब देखना होगा कि उन्हें भारत के वनडे दौरे पर इस प्रारूप में पर्दापण करने का मौका मिल पाता है या नहीं। हालांकि, 22 वर्षीय यह खिलाड़ी अपनी लेग ब्रेक से अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय में सभी प्रारूपों में निरंतरता उनका अहम लक्ष्य होगा। लाबुशाने ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा कि आप उन खिलाड़ियों को देखिए जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं। स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियम्सन, जो रूट, ये सभी लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, पिछले पांच-छह वर्षों से वे लगातार ऐसा कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ एक प्रारूप में नहीं है, बल्कि दो या काफी प्रारूपों में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए गुरुवार रात को यहां पहुंच गई। लाबुशाने ने 14 टेस्ट में 1,459 रन बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन गर्मियों में मैंने कुछ सफलता हासिल की, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती और अधिक निरंतर होना है और अच्छा प्रदर्शन कर रन जुटाना है। अगर मैं ऐसा करना जारी रखता हूं तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए बड़ी चुनौती होने वाली है।

भारत के खिलाफ अहम भूमिका निभाएंगे स्पिनर : कमिंस

सिडनी, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को उम्मीद है कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी टीम के स्पिनर अहम भूमिका अदा करेंगे। हालांकि, उन्हें नहीं लगता कि सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान उन्हें खुरदुरी पिच मिलेगी। कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के रवाना होने से पहले कहा, 'मुझे लगता है कि स्पिनर दुनिया में किसी और जगह से ज्यादा भारत में बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वनडे के लिए स्पिन लेती हुई खुरदुरी पिच मिले।' ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पांच मैचों की वनडे सीरीज में 3-2 से जीत हासिल की थी। कमिंस ने कहा, 'पिछली सीरीज में हम दो स्पिनरों के साथ खेले थे और वे भी दो स्पिनरों के साथ उतरे थे, इसलिए निश्चित रूप से स्पिनर अहम होंगे, खासकर बीच के ओवरों में।' ऑस्ट्रेलियाई टीम दो विशेषज्ञ स्पिनरों बायें हाथ के स्पिनर एश्टन एगर और लेग स्पिनर एडम जांपा के साथ जा रही है।

भोकानल पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करे आरएफआइ : बत्रा

ओलंपिक डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने शुक्रवार को भारतीय नौकायन महासंघ (आरएफआइ) से कहा कि वह दत्तू भोकानल पर लगाए गए दो साल के प्रतिबंध की समीक्षा करे, क्योंकि पहली बार गलती करने वाले के लिए यह बहुत कड़ी सजा है।

भोकानल 2018 एशियन गेम्स के दौरान रेस के बीच में ही रुक गए थे। विश्व चैंपियनशिप की पूर्व कांस्य पदक विजेता लंबी कूद की एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने पत्र लिखकर इस मामले पर आइओए का ध्यान दिलाया। इसके बाद बत्रा ने हस्तक्षेप किया। आइओए एथलीट आयोग की अध्यक्ष अंजू ने आगामी टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए भोकानल के प्रतिबंध की अवधि को कम करने के लिए कहा। आरएफआइ अध्यक्ष राजालक्ष्मी देव को लिखे पत्र में बत्रा ने कहा, 'मैं आपसे इस मामले पर दोबारा विचार का अनुरोध करता हूं क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आरएफआइ को एक खिलाड़ी को पहली बार गलती के लिए छह महीने से ज्यादा समय के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है यदि यह जानबूझकर नहीं किया गया है।'

भोकानल एशियन गेम्स में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय चौकड़ी में एक सदस्य थे, लेकिन वह सिंगल्स स्कल्स स्पर्धा के दौरान रेस में बीच में ही रुक गए थे। भोकानल ने कहा कि वह नाव से गिर गए थे जो पलट गई थी और उस दिन वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। आरएफआइ ने पिछले साल उन्हें दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और भोकानल के स्पष्टीकरण को भी खारिज कर दिया था।

ड्रोन हमले को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल

टोक्यो, आइएएनएस : जापान की पुलिस टोक्यो ओलंपिक के दौरान ड्रोन से होने वाले संदिग्ध आतंकी हमले को तकनीक की मदद से नाकाम करने की कोशिशों में जुटी है। इसके लिए खेल परिसरों के आसपास डिटेक्शन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यह टूर्नामेंट 24 जुलाई से 29 अगस्त तक होगा। हाल ही में जापान की राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी आतंकी हमलों को लेकर चेतावनी जारी की थी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस जो उपकरण लगा रही है वो ड्रोन से निकलने वाले सिग्नल को कैच करेंगे। इससे पता लगाया जा सकेगा कि वह कहां और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए भी खास तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इनमें अपने ड्रोन से जाल फेंककर आतंकी ड्रोन को जाम करना शामिल है। इससे उड़ रहे ड्रोन का उसे संचालित कर रहे व्यक्ति से संपर्क टूट जाएगा। ऐसे ही एक उपकरण के बारे में निजी कंपनियों ने पेशकश की है, जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे ड्रोन का पता लगा लेगा। ड्रोन से संबंधित कानून में पिछले साल मई में ओलंपिक के 24 स्थानों को जोड़ा गया है। इन इलाकों में अवैध रूप से उड़ रहे उपकरण को जब्त करने का पुलिस को अधिकार दिया गया है।

ओलंपिक के दौरान साइबर हमलावर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक अधिकारियों ने कहा था कि कुछ फर्जी ईमेल का पता चला है, जो स्टाफ सदस्यों की ओर से आए थे। ये ईमेल दुनिया भर के मीडिया हाउसों को भेजे जाने वाले थे।

वाह रे डीडीसीए | **राज्य क्रिकेट संघ के चयनकर्ताओं का नया करनामा**

दो दिन में डीडीसीए ने बनाईं दो टीमें

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

हाल ही में वार्षिक आम सभा (एजीएम) में पदाधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की का गवाह बने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के चयनकर्ताओं ने नया कारनामा किया जिसके कारण उन्होंने दो दिन में दिल्ली की अंडर-19 टीम दो बार चुनी।

गुरुवार को आशु दानी की अध्यक्षता वाली डीडीसीए की जूनियर चयनसमिति की बैठक हुई जिसमें शनिवार से बंगाल के खिलाफ होने वाले कूच बिहार ट्रॉफी के मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही होगा। इसी स्टेडियम में गुरुवार को हुई बैठक में दानी के अलावा चयनकर्ता प्रदीप चावला और करुण दुबे भी शामिल थे। इस टीम में यश ढुल, सौरव डागर, तेजस्वी, सुमित चिकारा, सनथ सांगवान, कमल बैरवा, अर्चित बख्शी, सिद्धार्थ साहनी, शुभम शर्मा, विवेक यादव, मयंक मलहोत्रा, आयुष सिंह, दिविज मेहरा, केशव डबास और प्रभजोत सिंह को चुना गया लेकिन अर्चित बख्शी, सिद्धार्थ साहनी व शुभम शर्मा का बीसीसीआइ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी इन तीनों को चुन लिया गया।

- बीसीसीआइ से रजिस्ट्रेशन के बिना ही खिलाड़ियों का नाम डाल दिया लिस्ट में
- बाद में मजबूरी में तीन खिलाड़ियों को बदलकर बनानी पड़ी नई टीम

आशु दानी पहले भी कई बार चयनकर्ता रह चुके हैं ऐसे में उन्होंने ये नादानी में तो नहीं किया होगा। इसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की गुजारिश बीसीसीआइ से की गई लेकिन बोर्ड ने इससे इन्कार कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को फिर आनन-फानन में नई टीम चुनी गई। इसमें अर्चित, साहनी और शुभम की जगह सिद्धार्थ सिंह बेनीवाल, अनीश गौतम और आर्यन राणा के नाम डाला गया। शुक्रवार कोई हुई बैठक में डीडीसीए के निदेशक (क्रिकेट) संजय भारद्वाज और संयुक्त सचिव राजन मनचंदा भी शामिल थे। डीडीसीए के एक पूर्व सदस्य ने कहा कि जरूर इस घटना के पीछे कोई न कोई गोलमाल होगा।

जब संजय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुरुवार की बैठक में मैं नहीं था और पता नहीं कैसे उन खिलाड़ियों का चयन हुआ जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हालांकि हमने काफी कोशिश की उन तीन लड़कों के रजिस्ट्रेशन कराने की लेकिन बात नहीं बनी। क्योंकि मैच शनिवार से ही शुरू हो रहा है ऐसे में हमारे पास उन तीन लड़कों को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इसलिए हमने टीम बदल दी।

सीबीआइ ने राष्ट्रीय खेल संघों से मांगी जानकारी

नई दिल्ली, जेएनएन : सीबीआइ ने अपनी नई स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी यूनिट (एसआइयू) के लिए शुक्रवार को खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) से जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। एनएसएफ के सभी प्रमुखों को मिली सूचना के मुताबिक, सीबीआइ की स्पेशल क्राइम-2 ब्रांच के प्रमुख जगरूप एस गुसिन्हा ने सभी जानकारी उपलब्ध कराए जाने की अंतिम तारीख 17 जनवरी मुकम्मल की है। इनमें पंजीकरण संख्या और पते के अलावा दफ्तर के पदाधिकारियों और सदस्यों की जानकारी भी मांगी गई है।

गुसिन्हा ने पत्र में लिखा कि खेलों के विकास को ध्यान में रखकर स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी यूनिट और सीबीआइ की स्पेशल क्राइम-2 की स्पेशल जांच-4 सेल की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखकर, युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय खेल संघों, संघों और समितियों से जानकारी इकट्ठा करना आवश्यक है। एनएसएफ से संबद्ध सदस्यों, गतिविधियों और टूर्नामेंट के साथ-साथ उपलब्धियों के बारे में विवरण हासिल करना आवश्यक है।

बोपन्ना-कूलहोफ ने जीता खिताब

कतर ओपन के पुरुष डबल्स का खिताब जीतने के बाद विजेता ट्रॉफी के साथ भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के वेस्ले कूलहोफ। एएफपी

दोहा, प्रेट्र : भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के वेस्ले कूलहोफ की जोड़ी ने शनिवार को ब्रिटेन के ल्यूक बैमब्रिज और मेक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज को हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स का खिताब जीता। बोपन्ना और कूलहोफ ने फाइनल मुकाबले को 3-6, 6-2, 10-6 से अपने नाम किया। इससे पहले शुक्रवार को इन दोनों ने हेनरी कोंटिनेन और फ्रैंको स्कुगोर की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। बोपन्ना और कूलहोफ ने फिनलैंड और क्रोएशिया की जोड़ी को सेमीफाइनल में 7-5, 6-2 से शिकस्त दी थी। बैमब्रिज और गोंजालेज की जोड़ी ने दूसरे सेमीफाइनल में डेनमार्क के फ्रेजरिक नेल्सन और जर्मनी के टिम पुएट्ज को 2-6, 6-2, 10-4 से हराया था।

अगर आप पूछेंगे कि कितने लोग पांच दिन के टेस्ट मैच को घटा कर चार दिन का करना चाहते हैं तो ज्यादा लोग मना करेंगे। मेरा मानना है कि हमें पूरी पिक्चर देखनी चाहिए।
– एंड्रयू स्ट्रॉस, निदेशक, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड

पांच बार के विश्व चैंपियन आनंद पर रहेंगी निगाहें

विज्क आन जी (नीदरलैंड्स) : पांच बार के विश्व चैंपियन भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद शनिवार से यहां शुरू होने वाले टाटा स्टील मास्टर्स सुपर टूर्नामेंट में दमदार खिलाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे जिसमें मैग्नस कार्लसन जैसे धुरंधर भी शामिल हैं। 50 वर्षीय आनंद ने 1989 में यहां पदार्पण किया था। वह पिछले 31 वर्षों में इस टूर्नामेंट में 18वीं बार शिरकत कर रहे हैं और यहां पांच बार के विजेता हैं।

न्यूज गैलरी

वीर लेंगे जोशी की जगह

नई दिल्ली : भारतीय अंडर-19 टीम के ऑलराउंडर दिव्यांश जोशी आगामी जूनियर क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गए हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के पहले वनडे मुकाबले के दौरान चोट लगी थी। दिव्यांश को फील्डिंग करते समय कंधे में चोट थी। अब अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने दिव्यांश की जगह महाराष्ट्र के सिद्धेश वीर को टीम में जगह दी है। प्रियम गर्ग की अगुआई वाली भारतीय अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है। (प्रेट्र)

रिद्धिमा ने जीता खिताब

बेंगलुरु : रिद्धिमा दिलावरी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को महिला प्रो गोल्फ टूर के पहले चरण का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने एक अंडर 215 के कुल स्कोर से रोचक जीत दर्ज की। पिछले साल पांच खिताब जीतने वाली रिद्धिमा ने प्रणवी उर्स को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। रिद्धिमा ने तीसरे और अंतिम दौर में 74 का कार्ड खेला जिससे वह कुल एक अंडर के स्कोर पर रहीं जबकि प्रणवी 73 के कार्ड से इवन पार 216 का स्कोर बना पाईं। (प्रेट्र)

हैदराबाद में होंगे मुकाबले

बेंगलुरु : प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) का अंतिम चरण बेंगलुरु के बजाय हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा क्योंकि स्थानीय टीम बेंगलुरु रैप्टर्स ने स्थल की अनुपलब्धता के कारण सेमीफाइनल और फाइनल सहित सभी मैचों की मेजबानी करने में असमर्थता जतायी है। पीबीएल 2020 में 21 मुकाबले होंगे जो 20 जनवरी से देश के कई शहरों में 21 दिन तक खेले जाएंगे। बेंगलुरु रैप्टर्स को पांच से नौ फरवरी के बीच अंतिम चरण की मेजबानी करनी थी। (प्रेट्र)

इंडिया-सी ने जीती ट्रॉफी

कटक : शेफाली वर्मा के नाबाद अर्धशतक के दम पर इंडिया-सी ने इंडिया बी को आठ विकेट से हराकर महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी जीत ली। 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया सी ने 28 गेंद पहले ही दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। (आइएएनएस)

बचकानी गलतियों की वजह से एटलेटिको से हारा बार्सा

मेसी ने कहा, गलतियों की वजह से हार पर दुख जताया

फुटबॉल डायरी

जेद्दा, एएफपी : स्पेनिश सुपर कप के एक बेहद रोचक सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना रीयल मैड्रिड से होगा। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी टीम के इस प्रदर्शन से निराश दिखे और कहा कि उनकी टीम बचकाना गलतियों की वजह से हारी।

किंग अब्दुल्लाह स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में बार्सिलोना की टीम निर्धारित समय से नौ मिनट पहले तक 2-1 से आगे थी और उसका जीत तय लग रहा था लेकिन इसके बाद एटलेटिको ने जोरदार वापसी की। अब मैड्रिड के दो दिग्गज क्लबों के बीच रविवार को फाइनल खेला जाएगा। मुकाबले के पांचों गोल दूसरे हाफ में हुए। पहला हाफ गोलरहित रहने के बाद दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में कोके ने स्थानापन्न के तौर पर उतरने के 21 सेकेंड के बाद ही गोल करके एटलेटिको को बढ़त दिलाई। इसके बाद मेसी (51वें मिनट) और एंटोनी ग्रीजमैन (62वें मिनट) के गोल ने बार्सिलोना को बढ़त दिलाई लेकिन एलवेरो मोराता (81वें मिनट) ने पेनाल्टी किक के जरिये गोल करके एटलेटिको को बराबरी पर ला खड़ा किया और फिर निर्धारित समय से चार मिनट पहले एंजेल कोरिया ने उसके लिए निर्णायक गोल दागा। इस मुकाबले के दौरान बार्सिलोना के दो गोल को ऑफ साइड होने की वजह से वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से रेफरी ने अयोग्य करार दिया। इस हार के साथ ही मौजूदा सत्र में रीयल और बार्सिलोना के बीच एक और एल क्लासिको देखने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं।

मेसी भड़के : हार के बाद मेसी ने कहा यह शर्मनाक है क्योंकि हम कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गए और बचकानी गलतियां की। हमें मुकाबले को अपने पक्ष में खत्म करना चाहिए था। यह हमारे लिए झटका है क्योंकि हम बेहतर खेल रहे थे। साथ ही बार्सिलोना के मैनेजर ईर्नेस्टो वाल्वर्डे ने भी इस हार पर निराशा जाहिर की।

टॉटनहम के सामने लिवरपूल की चुनौती

लंदन : पिछले चैंपियंस लीग के फाइनल में लिवरपूल और टॉटनहम के भिड़ंत की यादें सात महीने बाद शनिवार को ताजा होंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शनिवार को तालिका में 13 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर चल रही लिवरपूल की टीम टॉटनहम से उसके घर में लोहा लेने उतरेगी। उधर नए मैनेजर जोस मौरिन्हो के मार्गदर्शन में टॉटनहम खुद को रास्ते पर लाने की जुगत में दिखाई दे रहा है। ईपीएल में शनिवार को होने वाले अन्य अहम मुकाबलों में चेल्सी का मुकाबला बर्नले से, लीसेस्टर का साउथैंप्टन से, मैनचेस्टर युनाइटेड का नॉर्विक सिटी से और आर्सेनल का क्रिस्टल पैलेस से होगा।

केन तीन महीने के लिए बाहर

लीड्स : इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटनहम के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन चोट के कारण तीन महीने के लिए मैदान से बाहर हो गए हैं। टॉटनहम को इंग्लिश प्रीमियर लीग के अपने पिछले मुकाबले में साउथैंप्टन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी जहां हैमस्ट्रिंग इंजुरी की वजह से केन को मैदान से बाहर आना पड़ा था। अब केन के बगैर ही इंग्लिश फुटबॉल टीम को यूरो कप में उतरना होगा।

स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में गोल खाने के बाद निराश बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियो मेसी ● रायटर

रानी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित

30 जनवरी को ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर होगा फैसला। 25 खिलाड़ियों को किया गया है नामित

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : हॉकी की संचालन संस्था एफआइएच ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द इयर' के लिए नामित किया है। हॉकी इंडिया ने इसके लिए अपनी कप्तान को शुभकामनाएं देते हुए खुशी जताई है।

हॉकी इंडिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महासंघों द्वारा इस पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों को नामित किया गया है और एफआइएच ने रानी के शानदार प्रदर्शन और उनकी अगुआई करने की काबिलियत को देखकर उनका नाम इस पुरस्कार के लिए शामिल किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुहम्मद मुश्ताक अहमद ने कहा, 'हॉकी इंडिया रानी के 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट (डब्ल्यूजीए) ऑफ द इयर 2019' के लिए नामित किए जाने की खबर से बहुत खुश है। वह देश में कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। हम सभी हॉकी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि वह रानी के लिए वोट करें और 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियों में जुटी भारतीय हॉकी टीम का समर्थन करते रहें।' विजेता का फैसला ऑनलाइन वोटिंग में किया जाएगा जो 30 जनवरी को समाप्त होगी। रानी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के पहली बार लगातार ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। डब्ल्यूजीए का यह छठा संस्करण है। पिछले साल 159,348 वोटों के साथ रूस की एरोबिक जिम्नास्टिक्स जोड़ी मारिया चेरनोवा और जॉर्जी पेटरेइया ने यह अवॉर्ड जीता था। उन्होंने इस कड़ी में अमेरिकन पावरलिफ्टर जेनिफर थॉमसन को पछाड़ा था। थॉमसन ने 152,865 वोट हासिल किए थे।

रानी रामपाल ● फोटो, ट्विटर

प्रियंका और जतिन की सुनहरी शुरुआत

खेलो इंडिया यूथ गेम्स

गुवाहाटी, आइएएनएस : असम की राजधानी गुवाहाटी में रंगारंग समारोह के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का शुक्रवार को आगाज हुआ। अपने राज्य त्रिपुरा की दिग्गज भारतीय जिमनास्ट दीपा करमाकर को आदर्श मानने वालीं प्रियंका दासगुप्ता ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रियंका ने लड़कियों की अंडर-17 ऑलराउंड जिम्नास्टिक्स स्पर्धा में सुनहरी सफलता हासिल की। इसी तरह उत्तर प्रदेश के जतिन कुमार कनौजिया ने पुरुषों के अंडर-17 वर्ग में जिम्नास्टिक्स की ऑल राउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया।

वहीं आस्मी अंकुश बडाडे और श्रेया प्रवीन भांगले ने लड़कियों की अंडर-19 वर्ग की रिदिमिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में शुरुआती दोनों स्थानों पर कब्जा जमाया। वहीं उपाषा तालुकदार ने तीसरा स्थान हासिल करके मेजबान असम को इस आयोजन का पहला पदक दिलाया। तालिका में महाराष्ट्र की मैत्री अमित और निश्का चिंतामणी ने उपाषा से बेहतर स्थान हासिल किया लेकिन एक जिम्नास्टिक्स स्पर्धा में एक राज्य से केवल एक एथलीट द्वारा पदक जीतने के नियम के वजह से उपाषा को कांस्य पदक मिला।

रंगारंग आगाज : इससे पहले खेल मंत्री किरन रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का रंगारंग आगाज किया। राज्य के इंदिरा गांधी स्टेडियम में करीब 25000 दर्शकों की मौजूदगी में वन इंडिया के नारे के साथ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय एथलीट ने मशाल वाहक बनीं। तीसरे संस्करण में देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 6800 एथलीट इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मशहूर संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने जादुई आवाज से समा बांध दिया।

बंगाल की जिमनास्ट हुई चोटिल : खेलो इंडिया की पूर्व संध्या पर अभ्यास करते हुए बंगाल की जिमनास्ट को गर्दन में चोट लग गई जिसकी वजह से इस एथलीट को बाहर होना पड़ा। अदिता मंडल को एमआरआइ रिपोर्ट देखने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

सिंधू और साइना की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त

कुआलालंपुर, प्रेट्र : ओलंपिक पदक विजेता भारतीय शटलर पीवी सिंधू और साइना नेहवाल शुक्रवार को यहां मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं जिससे इस टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी खत्म हो गया। महिला सिंगल्स में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधू को शीर्ष वरीय ताई जु यिंग से जबकि साइना को स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से पराजय का सामना करना पड़ा। 2012 के लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना कहीं भी मारिन की बराबरी करती नहीं दिखीं जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी की चुनौती 21-8, 21-7 से समाप्त कर दी।

असम की तीरंदाज की गर्दन से तीर निकाला

एम्स ट्रॉमा सेंटर में चार घंटे की सर्जरी में डॉक्टरों ने निकाला तीर, शिवांगिनी ने डॉक्टर से पूछा, कब तक शुरू कर सकती हूं तीरंदाजी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : असम की 12 वर्षीय तीरंदाज शिवांगिनी गोहिन की शुक्रवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई। करीब चार घंटे तक चली सर्जरी में उनके कंधे व गर्दन में फंसे तीर के 15 सेंटीमीटर हिस्से को निकाला गया।

सर्जरी के कुछ समय बाद उन्हें होश भी आ गया। फिर भी उन्हें देखभाल के लिए आइसीयू में रखा गया है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। वह बातचीत भी कर रही हैं। उन्होंने सर्जरी करने वाले एम्स के न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार गुप्ता से पूछा कि मैं कब तक दोबारा तीरंदाजी शुरू कर पाऊंगी। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि वह तीन माह में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बाद तीरंदाजी शुरू कर सकेंगी। यह जवाब सुनकर वह बेहद खुश हुईं। शिवांगिनी को एयर एंबुलेंस से दिल्ली लाकर गुरुवार रात करीब आठ बजे एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। इसके बाद रात में उनकी कई जांच की गईं।

सीटी स्कैन व एंजियोग्राम भी कराया गया। डॉ. गुप्ता ने कहा कि तीरंदाजी के प्रोफेशनल खिलाड़ी अभ्यास के लिए जो तीर इस्तेमाल करते हैं वह उसके कंधे में धंसा हुआ था, जो कार्बन एल्यूमिनियम का बना हुआ था। यह तीर 65 सेंटीमीटर का था। उसका 15 सेंटीमीटर हिस्सा दायें कंधे में धंस गया था, जो गर्दन के सर्वाइकल वटिब्रा सी-7-टी1 (स्पाइनल कॉर्ड के हिस्सा) को तोड़ते हुए फेफड़े के बायें हिस्से तक पहुंच गया था।

इसके अलावा यह तीर मस्तिष्क में खून आपूर्ति करने वाली धमनी को छूते हुए अंदर गया था। गनीमत है कि यह धमनी क्षतिग्रस्त नहीं हुई व फेफड़े को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यदि कोई उसे खींचकर निकालने की कोशिश करता तो स्पाइनल कॉर्ड व धमनी क्षतिग्रस्त हो सकती थीं। इस वजह से हाथ-पैर पैरालाइज हो सकते थे व जान को भी खतरा था। शिवांगिनी का सुबह छह बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। करीब सुबह 10 बजे सर्जरी पूरी हुई।

विविध

संगम पर उमड़ी आस्था, लाखों ने लगाई डुबकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

माघ मेला में पौष पूर्णिमा पर शुक्रवार को शीतलहर के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। देर शाम मेला प्रशासन ने लगभग 23 लाख श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही तंबुओं की नगरी में एक माह का कल्पवास शुरू हो गया। कुंभ के बाद माघ मेला के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का स्नान भोर से ही शुरू हो गया था। शंखनाद, घंटा-घड़ियाल और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ त्रिवेणी में स्नान शुरू हुआ तो दिन भर सिलसिला चलता रहा।

स्नान के लिए गुरुवार शाम से ही संगम की रेती पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। आधी रात के बाद भारी तादाद में लोग संगम तट पहुंच चुके थे। भोर में स्नान शुरू होने पर घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा नजर आया। सुबह भी स्नान घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ रही। दोपहर में मौसम खुला और धूप निकलने पर स्नानार्थियों की संख्या और बढ़ गई। सुबह 10 बजे तक प्रशासन ने लगभग 15 लाख लोगों के स्नान का दावा किया था। सकुशल स्नान के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसर मेला क्षेत्र में डटे रहे। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के साथ अर्द्ध सैनिक बल तैनात हैं।

पौष पूर्णिमा के स्नान पर श्रद्धालुओं पहले आचमन किए, उसके बाद डुबकी लगाई। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। संगम पर जल की पर्याप्त उपलब्धता के चलते धारा भी तेज रही। सुरक्षा के लिए वाटर बैरिकेडिंग की गई थी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने उमड़े श्रद्धालु। शरद मालवीय

- हर-हर महादेव के जयघोष के साथ भोर से ही शुरू हुआ स्नान

23 लाख श्रद्धालुओं के शाम तक स्नान करने का प्रशासन का दावा

03 लाख के करीब कल्पवासी, साधु-संतों ने शुरू किया कल्पवास

06 सेक्टरों में, 25 सौ बीघा क्षेत्रफल में बसाई गई तंबुओं की नगरी

05 हजार के करीब पुलिस, पीएसी व अर्द्धसैनिक बलों के जवान तैनात

पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर शुक्रवार को भोर से शाम तक लगभग 23 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। मेलार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्था रही। स्नान घाटों पर जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थीं।
– रजनीश कुमार मिश्र, मेलाधिकारी

'लक्ष्मी की वकील को क्यों नहीं दिया श्रेय'

जासं, नई दिल्ली : छपाक फिल्म में एसिड हमले की शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता को कोई श्रेय नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से पूछा कि एसिड हमले की शिकार हुई लक्ष्मी का मुकदमा लड़ने वाली अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को फिल्म में श्रेय क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने फिल्म में इनपुट दिए और पूरी फिल्म इसी घटना पर आधारित है। पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे शनिवार को सुनाएगी।

गुरुवार को पटियाला हाउस की एक अदालत ने फिल्म में अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय देने का आदेश दिया था। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यहां तक पूछा कि आखिर अधिवक्ता को श्रेय देने में समस्या क्या है और क्यों वे इससे जुड़ी जानकारी लेने के लिए उनके (अपर्णा के) पास गए थे। निर्देशक मेघना गुलजार के अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ था और इनपुट लेना का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उक्त व्यक्ति को इसका श्रेय दिया जाए।

दोस्त को वीसी बनवाने को शाह बनकर की राज्यपाल से बात

नईदुनिया, भोपाल

- मप्र में राजभवन फोन लगाकर मित्र को जबलपुर के आयुर्विज्ञान विवि का कुलपति बनाने को कहा
- शक होने पर राज्यपाल ने पुष्टि कराई, एसटीएफ ने आरोपित विंग कमांडर व उसके दोस्त को किया गिरफ्तार

एयरफोर्स के विंग कमांडर कुलदीप वाघेला ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनकर मोबाइल पर बात की। वाघेला ने राज्यपाल को आदेशात्मक लहजे में अपने मित्र डॉ. चंद्रेश कुमार शुक्ला को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने को कहा। गड़बड़ी की आशंका पर गृह मंत्री शाह के बंगले पर इस फोन के बारे में सत्यापन कराया गया। फोन शाह के यहां से नहीं किए जाने पर मामला एसटीएफ को सौंपा गया। इसके बाद दिल्ली में पदस्थ विंग कमांडर कुलदीप वाघेला व डॉ. चंद्रेश कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसटीएफ एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) अशोक अवस्थी ने बताया कि जबलपुर के मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए कई लोगों ने बायोडाटा दिए थे। कुलपति चयन के लिए सर्च कमेटी ने साक्षात्कार भी लिए थे। इसमें भोपाल के साकेतनगर में रहने वाले डेंटल सर्जन डॉ. चंद्रेश कुमार शुक्ला भी शामिल थे। चयन प्रक्रिया के बीच डॉ. शुक्ला ने अपने मित्र और एयरफोर्स में विंग कमांडर कुलदीप वाघेला से चर्चा की। शुक्ला ने वाघेला से कहा कि कुलपति बनने के लिए किसी बड़े व्यक्ति से फोन कराना पड़ेगा। दोनों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से राज्यपाल की बात कराना तय हुआ। बाद में दोनों ने खुद ही शाह बनकर राज्यपाल से बात करने की साजिश रची।

अवस्थी के मुताबिक, चंद्रेश और वाघेला के बीच तीन जनवरी को बात हुई। चंद्रेश ने राजभवन फोन लगाकर शाह के बंगले से बात करने का हवाला दिया। राजभवन के कर्मचारी को बताया कि मंत्रीजी राज्यपाल से बात करना चाहते हैं। राज्यपाल टंडन के लाइन पर आते ही विंग कमांडर ने उनसे खुद को शाह बताकर बात की। राज्यपाल से कहा कि जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉ. चंद्रेश कुमार शुक्ला की कुलपति के रूप में नियुक्ति होना है।

सूत्रों के अनुसार, चंद्रेश के कॉल रिकॉर्ड में सामने आया कि जिस समय राजभवन के फोन पर कथित रूप से शाह की बात हुई थी, उसी समय उसकी विंग कमांडर वाघेला से चर्चा हुई। इसके आधार पर एसटीएफ ने दिल्ली स्थित एयरफोर्स हेडक्वार्टर में पदस्थ वाघेला की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी, लेकिन वहां उसे पकड़ने के लिए कई घंटे लगे। सेना के उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद वाघेला को एसटीएफ की टीम भोपाल लाई। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

26 किमी बाद ही हादसा

- प्रथम पृष्ठ से आगे

शुक्रवार रात करीब 8 बजे विमल चतुर्वेदी बस सर्विस की स्लीपर बस कन्नौज के गुरसहायगंज से जयपुर के लिए चली थी। बताते हैं कि बस में गुरसहायगंज से 12 यात्री बैठे थे। इससे आगे छिबरामऊ में भी कई सवारियां बैठीं। बस में कुल यात्रियों की संख्या लगभग 35 बताई जा रही है। इनमें से कुछ यात्री बालाजी दर्शन करने तो कुछ रोजगार की तलाश में जयपुर जा रहे थे। हालांकि बस में कितने यात्री सवार थे, इसकी किसी ने आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। गुरसहायगंज से बस अभी 26 किमी ही चल पाई थी कि छिबरामऊ से पांच किमी आगे जीटी रोड पर ग्राम घिलोई के पास कोहरे की वजह से यह भयानक हादसा हो गया।

यातायात बाधित : हादसे के बाद जीटी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं। कानपुर से एडीजी और कमिश्नर भी घटनास्थल पर पहुंचे। मंडलायुक्त सुधीर एम बोबडे ने बताया कि घटना कैसे हुई इसकी जांच होगी। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कितने यात्रियों की मौत हुई है, अभी यह कंफर्म नहीं है।

डीटीसी व आरटीओ करेंगे जांच : उप्र के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने हादसे की जांच कानपुर के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (डीटीसी) और संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को सौंपी है। उन्होंने दोनों अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर हर पहलू की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

कन्नौज के डीएम और एसपी मौके पर हैं। इस मामले में लगातार उनसे जानकारी ली जा रही है। बस संचालक की लापरवाही की बात सामने आई है। मुकदमा दर्ज करके जांच कराई जाएगी।
– प्रेम प्रकाश, एडीजी

कन्नौज में शुक्रवार को बस और ट्रक की भीषण टक्कर के बाद धू-धू कर जलते दोनों वाहन। जागरण

पकड़ा गया प्रीति चड्ढा का हत्यारोपित पति

नईदुनिया, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बेटी प्रीति चड्ढा की अबूधाबी (यूएई) में हुई संदिग्ध हालत में मौत की जांच कर रही पुलिस ने आरोपित पति सिंधु घोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूएई से भारत पहुंचते ही मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे पकड़ लिया और एसपी को इसकी सूचना दे दी।

वरिष्ठ पत्रकार प्राण चड्ढा की बेटी प्रीति दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर प्रमुख के पद पर कार्यरत थीं। कोलकाता निवासी सिंधु घोष दुबई में पायलट है। प्रीति ने करीब तीन साल पहले उससे शादी की थी। शादी के बाद उसके मन में लालच आ गया। वह हमेशा प्रीति पर अपने पिता के नाम की जमीन की हिस्सेदारी की मांग करने के लिए दबाव डालता था। सिंधु बेहिसाब रकम खर्च करता और प्रीति के डेबिट कार्ड वगैरह को जबरिया ले लेता। जब तक प्रीति उसे रकम देती रहती, रिश्ता ठीक रहता।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में देर रात से हल्की वर्षा तथा हिमपात शुरू होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। ठिठुरनभरी सुबह में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। शीतल हवाओं के साथ दिन ठंडा रहेगा।

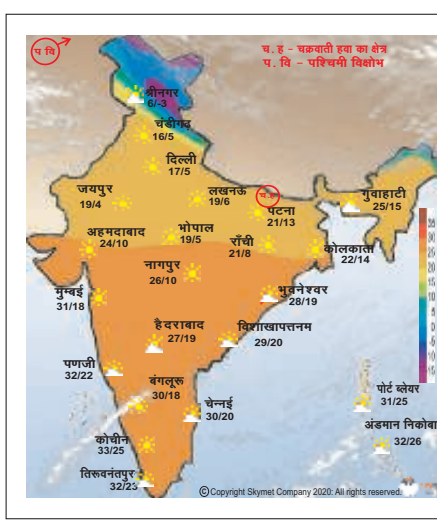

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/19/आंबा	अहमदाबाद	26/06/सा
कोलकाता	23/13/सा	बड़ोदा	28/12/सा
चेन्नई	30/21/सा	नागपुर	26/10/आंबा
हैदराबाद	27/18/आंबा	इन्दौर	23/10/सा
बंगलूरू	30/17/सा	रांची	28/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/24/सा	पटना	27/14/व
गुवाहाटी	26/16/सा	जमशेदपुर	30/15/आंबा
गंगटोक	07/-7/सा	पुणे	30/17/आंबा

हवाई और अमेरिका के बीच अकेले पहली बार भरी गई उड़ान

आज ही 1935 में एमेलिया इयरहार्ट ने हवाई द्वीप के व्हीलर फील्ड से उड़ान भरी और अगले दिन कैलिफोर्निया पहुंची। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली शख्सियत रहीं। अटलांटिक महासागर को विमान से पार करने वाली पहली महिला भी थीं।

मधुमेह के रोगियों को पहली बार इंसुलिन दी गई

आज ही के दिन 1922 में मधुमेह के रोगियों के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया गया था। इसुंलिन की खोज सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग के साथ चार्ल्स एच बेस्ट और जेजेआर मैकलियोड ने टोरंटो विश्वविद्यालय में 1921 में की। जेम्स बी कोलिप ने इसे शुद्ध किया था।

बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैलाश सत्यार्थी

आज ही के दिन 1954 में बाल अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्यप्रदेश के विदिशा में हुआ था। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के करियर को छोड़कर बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। यह संगठन बच्चों को बालश्रम से मुक्ति दिलाकर उनका पुनर्वास कराता है। बाल श्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून की मांग पर 1998 में वैश्विक मार्च निकाला। जिसमें उन्होंने 103 देशों की यात्रा कर 80 हजार किमी की दूरी तय की। उन्हें 2014 में नोबेल मिला। सत्यार्थी अब तक 88 हजार बाल श्रमिकों को मुक्त करा चुके हैं।

पिघलते ग्लेशियर से पाकिस्तान का भविष्य खतरे में

- रोजाना चार मीटर की दर से हसनाबाद गांव की तरफ बढ़ रहा
- धारणा के विपरीत कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित इस ग्लेशियर में हो रही वृद्धि

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रतीकात्मक

इस्लामाबाद, एएफपी : विशाल शिस्पर ग्लेशियर (हिमनद) के कारण पाकिस्तान के हसनाबाद गांव के लोगों का एक-एक दिन डर के साये में बीत रहा है। उनकी जिंदगी पर खतरा किस कदर मंडरा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह ग्लेशियर रोजाना करीब चार मीटर की दर से उनकी ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां दुनियाभर में ज्यादातर ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं। वहीं उत्तरी पाकिस्तान की कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित यह ग्लेशियर बढ़ रहा है। जिसकी वजह से सैकड़ों टन बर्फ और मलबा सामान्य दर से दस गुना तेजी से नीचे आ रहा है। जिससे इस गांव के लोगों और उनके घरों को खतरा पैदा हो गया है।

ग्रामीण बसीर अली के मुताबिक उन लोगों का जीवन, उनकी संपत्तियां और जानवर खतरे में हैं। ग्लेशियर की झीलों, बर्फ और चट्टानों के गिरने से आई बाढ़ व स्वच्छ और सुलभ पानी की कमी इसके रास्ते में रहने वाले लोगों के जीवन को गंभीर खतरे में डाल रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) पाकिस्तान के इग्नेस आर्टा ने कहा, जब एक ग्लेशियर झील फटती है तो यह ना केवल बर्फ, पानी और मलबा अपने साथ लाती है, बल्कि बहुत सारा कीचड़ भी गिरता है। इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में यह अपने मार्ग के बीच आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है।

बर्फ के पिघलने पर निर्भर है सिंधु का प्रवाह : उन्होंने बताया कि सिंधु का प्रवाह बर्फ के पिघलने पर निर्भर है और पाकिस्तान के ग्लेशियरों में होने वाला परिवर्तन इसे प्रभावित करता है। इसका असर ना केवल उसके बेसिन में रहने वाले लोगों पर पड़ता है, बल्कि पूरे राष्ट्र पर पड़ता है जो अपने भोजन के लिए इसके पानी पर निर्भर है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक जलस्तर में बदलाव से पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देशों को सिंधु और उसकी सहायक नदियों की आवश्यकता है।

सिंधु के पानी पर निर्भर है पाकिस्तान की 90 फीसद खेती : कराकोरम में के2 सहित दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद यहां सबसे ज्यादा बर्फ है। तिब्बत से निकलने के बाद सिंधु भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। अरब सागर तक पहुंचने से पहले कई सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की 90 फीसद खेती इसी नदी के पानी पर निर्भर है। विशेषज्ञों ने 2025 तक पाकिस्तान में पानी की कमी की चेतावनी दी है, जिसमें हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना एक महत्वपूर्ण कारण है। वैज्ञानिक हालांकि अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि कराकोरम में ग्लेशियर कैसे बढ़ रहे हैं।

शिस्पर ग्लेशियर विश्व का 38वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह काराकोरम पर्वतमाला की पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो पीओके के गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र में आता है।

फिल्म रिव्यू

एसिड हमला सिर्फ चेहरे पर नहीं, जिंदगी पर होता है

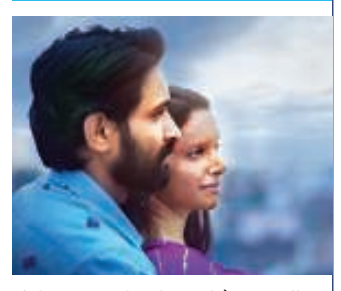

छपाक

निर्देशन : मेघना गुलजार
प्रमुख कलाकार : दीपिका पादुकोण, विक्रांत मेस्सी
अवधि : 2 घंटे 3 मिनट

देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध मसलन बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सुर्खियों में छाए रहते हैं। निर्भया कांड के बाद आरोपियों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश दिखा था। वहीं, एसिड हमलों को पहले गंभीर अपराध नहीं माना जाता था, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे। इसके खिलाफ नए सख्त कानून बनने के बावजूद एसिड हमले थम नहीं रहे हैं। दुखद बात यह है कि इन हमलों की शिकार लड़कियों की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभावों को अनदेखा कर दिया जाता है। मेघना गुलजार और दीपिका पादुकोण ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए एसिड हमले की शिकार लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित होकर 'छपाक' बनाई है। दिल्ली निवासी लक्ष्मी का सपना गायिका बनने का था, मगर एसिड अटैक ने चेहरे के साथ उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उस समय 15 साल की लक्ष्मी से 32 साल का युवक शादी करना चाहता था। शादी से इन्कार के बाद 2005 में उस युवक ने लक्ष्मी पर एसिड फेंक दिया था।

हालांकि 'छपाक' लक्ष्मी की बायोपिक नहीं है। उसमें एसिड हमले की शिकार कुछ और लड़कियों की कहानी भी पिरोई गई है। फिल्म का मकसद इस घिनौने अपराध की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है, ताकि किसी और लड़की का चेहरा न बिगड़े। उसे देखकर कोई डरे नहीं। कहानी का आगाज दिल्ली में निर्भया कांड को लेकर उपजे रोष से होता है। वहीं से संकेत दिया जाता है कि एसिड अटैक को कमतर आंका जाता है, जबकि उसकी सजा आजीवन लड़की को भोगनी पड़ती है। उसका इलाज महंगा होता है। बिगड़े नैन-नक्श के कारण कोई उन्हें काम नहीं देता। उनके लिए सरकार ने भी कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई है। 19 वर्षीय मालती (दीपिका पादुकोण) पर पड़ोस में रहने वाला युवक बशीर खान एसिड फेंक देता है। वह मालती से एकतरफा प्यार करता है, जबकि मालती उसे भैया बुलाती है। कई सर्जरी होने के बावजूद मालती परिवार का सहारा बनने की कोशिश करती है। वह नौकरी ढूंढ़ती है। हर बार चेहरा उसमें आड़े आता है। वह एसिड हमले के पीड़ितों के सहायतार्थ एनजीओ चलाने वाले अमोल (विक्रांत मेस्सी) के संपर्क में आती है। मालती उसके साथ काम करने लगती है। साथ ही बशीर के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती है।

हिंदी में पहली बार एसिड हमले पर कोई फिल्म बनी है। इससे पहले मलयालम में फिल्म 'उयरे' बन चुकी है। इसी विषय पर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस को ऑस्कर अवार्ड मिला था। बहरहाल, एसिड हमले जैसे विषय पर फिल्म बनाने के लिए मेघना और दीपिका के साहस की दाद देनी होगी। उन्होंने इस गंभीर अपराध की ओर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। हालांकि लक्ष्मी का चेहरा जरूर बिगड़ा, लेकिन हौसला मजबूत रहा। उन्होंने अपने हमलावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। उसे दस साल की सजा हुई। फिल्म का मकसद नेक है। हालांकि इतने संवेदनशील मामले की स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर है। मेघना कोर्टरूम ड्रामा को झकझोरने वाला नहीं बना पाई हैं। वहीं प्रॉस्थेटिक मेकअप के चलते दीपिका के लिए मालती बन पाना आसान रहा है। उन्होंने एसिड पीड़िता के दर्द, चिंताओं और सामाजिक प्रताड़ना को संवेदनशीलता के साथ उकेरा है। बतौर निर्माता यह उनकी पहली फिल्म है। विक्रांत अपने किरदार के साथ न्याय करते दिखे हैं। गुलजार द्वारा लिखा टाइटिल सांग कोई चेहरा मिटा... कर्णप्रिय और मर्मस्पर्शी है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

इधर-उधर की

शोधकर्ताओं का दावा, बिल्ली पालने वाले कम जाते हैं चर्च

न्यूयॉर्क, एजेंसी : हम अपने घरों में कुत्ते, बिल्लियों को पालते हैं। उन्हें घुमाने ले जाते हैं, साथ में खेलते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें लेकर के अपने धार्मिक विश्वासों का आकलन नहीं करते हैं। हालांकि एक हालिया सर्वे ने बिल्ली पालने वाले लोगों के धार्मिक स्वभाव संबंधी एक निष्कर्ष पेश किया है। अमेरिका में बिल्ली पालने वाले करीब दो हजार लोगों पर हुए शोध में बताया गया है कि जो लोग बिल्ली पालते हैं वे कम धार्मिक होते हैं। शोध के मुताबिक जिनके पास दो पालतू होते हैं वे कभी चर्च नहीं जाते हैं। जबकि विश्वास करने वाले लोगों के पास 1.4 पालतू होते हैं। सर्वे के निष्कर्षों के मुताबिक बिल्ली पालने वाले लोगों में पूजा के प्रति एक नकारात्मकता होती है। ओकलाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैमुअल पेरी का कहना है कि हम हमेशा बिल्लियों के प्यार को जीतना चाहते हैं। हालांकि जब हमें लगता है कि वह हम से नाराज हैं, तो हम परेशान हो उठते हैं।

एआइ से होगा ब्रेन कैंसर का इलाज

तकनीक ▶ स्पेन की उप्सला यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई एल्गोरिद्म

सीएनआर 2 नामक प्रोटीन को सक्रिय करने से रुकती है कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि

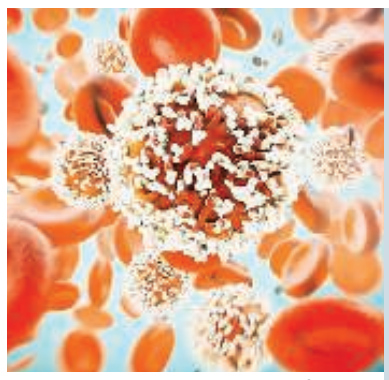

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी होने लगा है और इसके प्रभावी परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई एल्गोरिद्म विकसित की है, जिसकी मदद से न्यूरोब्लास्टोमा जैसे ब्रेन कैंसर का उपचार किया जा सकेगा। यह बच्चों में होने वाले सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक है। इस कैंसर की कोशिकाएं विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र को अपना निशाना बनाती हैं और तनाव की स्थिति में खतरनाक प्रतिक्रिया देती हैं।

नए उपचार के बारे में जर्नल नेचर कम्यूनिकेशन में विस्तार से बताया गया है। यह उपचार नर्वस सिस्टम में सीएनआर 2 (कैनाबिनोइड रिसेप्टर 2) नामक प्रोटीन को सक्रिय करने पर आधारित है। यानी कैंसर के उपचार के नए तरीके में दवाओं के जरिये सीएनआर 2 को सक्रिय जाता है और इसके सक्रिय होते ही कैंसर कोशिकाओं पर इसका असर देखने को मिलता है। इस दौरान या तो उनकी वृद्धि रुक जाती है या वे खत्म होने लगते हैं। स्वीडन के उप्सला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने एक नई एल्गोरिद्म विकसित की है। इसमें यूरोपीय और अमेरिकी अस्पतालों और विश्वविद्यालयों से बड़े पैमाने पर आनुवंशिक और ड्रग डाटा को जोड़ने पर पता चला कि यह एल्गोरिद्म उपचार के नए सुझाव दे सकती है, जिसके जरिये रोगों के बुनियादी तंत्र को प्रभावित किया जा सकता है और इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि रोग ठीक हो जाए।

जेब्रा फिश पर किया अध्ययन : उप्सला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक स्वेन नेलैंडर ने कहा, हम आश्चर्यचकित थे जब एल्गोरिद्म ने न्यूरोब्लास्टोमा के उपचार के लिए सीएनआर 2 को सिमुलेट करने जैसा तरीका सुझाया। इस संदर्भ में अब तक किसी ने चर्चा तक नहीं की थी। इसलिए हमने प्रयोगशाला में आगे इसकी जांच करने का फैसला किया है। जब वैज्ञानिकों ने दवा का नई विधि के तहत परीक्षण किया तो इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले। जेब्रा फिश पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि सीएनआर2 को सिमुलेट करने पर ट्यूमर की वृद्धि रुक गई और कैंसर कोशिकाएं भी धीरे-धीरे कम होने लगी।

एग्लोरिद्म को और एडवांस बनाने में जुटे शोधकर्ता : शोधकर्ताओं का कहना है कि बीते कुछ वर्षों से स्मार्ट एग्लोरिद्म का कैंसर के अध्ययनों में महत्व काफी बढ़ गया है और आने वाले वर्षों में इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से कैंसर के पीड़ितों को बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। शोधकर्ता अब इस एग्लोरिद्म को और एडवांस बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि अन्य प्रकार के कैंसरों का भी इसके जरिये उपचार किया जा सके।

प्रोस्टेट कैंसर की पहचान करेगा नया एआइ सिस्टम

लंदन, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने प्रोस्टेट कैंसर की पहचान और ग्रेडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आधारित एक नई विधि विकसित की है। इस एआइ सिस्टम से इस बीमारी की सटीक पहचान और उपचार के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रोस्टेट कैंसर की पहचान और ग्रेडिंग में एआइ सिस्टम को दुनिया के अग्रणी यूरो-पैथोलॉजिस्ट जितना ही बेहतर पाया गया है। यह हालांकि प्रारंभिक नतीजा है। इस पर अभी और शोध की जरूरत है। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर मार्टिन एक्लुंद ने कहा, 'हमारे अध्ययन के नतीजों से जाहिर होता है कि प्रोस्टेट कैंसर की पहचान और इसकी ग्रेडिंग करने के लिए एआइ सिस्टम को उसी स्तर पर तैयार करना संभव है, जिस स्तर पर अग्रणी विशेषज्ञ अपने काम को अंजाम देते हैं। इससे यूरो-पैथोलॉजिस्ट के काम का बोझ कम होगा और वे दूसरे गंभीर मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।'

शोध अनुसंधान

ऑटिज्म पीड़ित हर चौथे बच्चे का नहीं हो पाता उपचार

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि आठ साल से कम उम्र के ऑटिज्म पीड़ित हर चौथे बच्चे का उपचार नहीं हो पाता। ऑटिज्म पीड़ितों को दूसरे लोगों से बातचीत और घुलने-मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के रटगर्स न्यूजर्सी मेडिकल स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर वाल्टर जाहोरोडनी ने कहा कि ऑटिज्म के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद अश्वेत लोगों में कई मामलों का उपचार नहीं हो पाता। वर्ष 2014 में शोधकर्ताओं ने आठ साल के दो लाख 66 हजार बच्चों के चिकित्सा और शिक्षा रिकार्ड का विश्लेषण किया था। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि कितने बच्चों में ऑटिज्म विकार की पहचान और उपचार नहीं हुआ था। इसमें पाया गया कि करीब 25 फीसद बच्चों में इस विकार की पहचान तक नहीं हुई थी। -एएनआइ

राज्य दिवस समारोह

भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सबसे ताकतवर नेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की (मध्य में) ने शुक्रवार को चीन के सीमावर्ती क्षेत्र म्यांतिना पहुंचकर 72 वें काचिन राज्य दिवस समारोह में शिरकत की। पारंपरिक पोशाक पहने सू की इस इस क्षेत्र में पहली बार आई हैं। इस मौके पर लोगों ने उनका हवाई अड्डे पर काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। म्यांमार की प्रतिष्ठित नेता की इस यात्रा को काफी अहमियत दी जा रही है। एएफपी

श्रीलंका में मनाया वार्षिक परेरा उत्सव

श्रीलंका में केलानिया के ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में वार्षिक परेरा उत्सव परेड के दौरान फायर डांस करता आर्टिस्टों का समूह। इस मंदिर में पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गजराज की पूजा की जाती है। इसके बाद पूर्णिमा पर श्रद्धालु यहां एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि यहां भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए पहुंचे थे। परेरा उत्सव देश के प्रमुख उत्सवों में से एक है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

रितिक के जन्मदिन पर उनकी मां ने लिखी भावुक पोस्ट

अभिनेता रितिक रोशन ने शुक्रवार को 46वां जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर उन्हें खूब बधाइयां मिलीं। अलग हो चुकीं पत्नी सुजैन ने रितिक के साथ दोनों बेटों की फोटो साझा करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे रितिक... आप अद्भुत इंसान हैं।' साथ ही हैशटैग के साथ लिखा 'बेस्ट डैडी अवार्ड'। इस मौके पर रितिक की मां पिंकी ने वर्ष 2013 में रितिक की ब्रेन सर्जरी के दौरान की तस्वीरें साझा कीं। फिल्म 'बैंग बैंग' की शूटिंग में उनके सिर में चोट लगी थी। पिंकी ने लिखा, 'मैं आज इन अनदेखी फोटो को साझा कर रही हूं। इस समय भले ही मेरा मन दुख और चिंता के कारण भारी बना हुआ है, लेकिन यह सब अटूट प्रेम के कारण है... हम अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब उनकी लगन, ताकत और हिम्मत उनके माता-पिता से भी आगे निकल जाती है? क्या होता है, जब आप हिम्मत और प्रेरणा के मामले में जो बनना चाहते थे, वह आपके बेटे के रूप में आपकी आंखों के सामने हो? डुग्गू के ब्रेन सर्जरी के लिए जाने से पहले मुझे चक्कर आ रहा था। मैं बेहोश हो रही थी और मेरे लब पर दुआएं थीं। मैंने उसमें अपनी परछाईं देखी और पाया कि उसकी ताकत मुझमें हौसला भर रही है। उसके दिमाग की शक्ति किसी सुपरपावर से कम नहीं है। उसकी यह खास बात आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। उन आंखों और तस्वीरों में देखें। क्या लगता है कि उसकी ब्रेन सर्जरी होने वाली है? नहीं। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। यह छोटा बच्चा, जिसे मैंने नौ महीने अपनी कोख में पाला, जन्म दिया और उसे अपनी बांहों में रखा, वह अब मुझे अपनी सारी शक्ति और प्रेम लौटा रहा है।'

दीपिका के फैन हो गए रणवीर

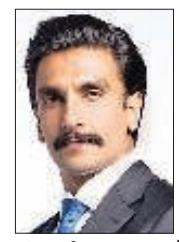

दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' पर दीपिका के पति रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी दीपिका और मेघना गुलजार की जमकर तारीफ की है। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'मेघना, तुम्हारी फिल्म लोगों को आशा और हिम्मत देती है। यह मानवता का सबसे अच्छा और बुरा हिस्सा दिखाती है। इसकी कहानी अंदर तक झकझोर देती है।' रणवीर ने दीपिका के लिए लिखा- 'मेरी बेबी! मैंने आपको इस किरदार के लिए मेहनत करते देखा है। आप इस फिल्म की आत्मा हो। यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। इसी इरादे और ईमानदारी के साथ काम करती रहो। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। आपने जिस तरह से अपना किरदार निभाया, मैं पूरी तरह आपका फैन हो गया हूं। मालती के साथ जो आपने हासिल किया, वह चौंका देने और हैरान करने वाला है। आई लव यू बेबी। मुझे आप पर कभी इससे ज्यादा गर्व नहीं हुआ।'

'कंट्री ऑफ ब्लाइंड' को कान ले जाएंगी हिना खान

पिछले वर्ष अपनी फिल्म 'लाइन्स' के लिए हिना खान ने कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार शिरकत की थी। वहां से हिना के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में उतरने के रास्ते खुल गए हैं। हिना की आगामी फिल्मों में विक्रम भट्ट की 'हैक्ड' के साथ इंडो-अमेरिकन फिल्म 'कंट्री ऑफ ब्लाइंड' भी शामिल है। यह फिल्म एचजी वेल्स के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन राहत काज्मी कर रहे हैं। हिना की मानें तो वह इस साल इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में लेकर जा सकती हैं। फिल्म में हिना एक नेत्रहीन लड़की बनी हैं। हिना का कहना है कि वह अलग तरह का किरदार है। एक कलाकार क्या-क्या कर सकता है, यह उसकी शक्ल से पता नहीं चलता। वह तब दिखाई देता है, जब वह उस किरदार में उतरता है।

अगले साल की ईद भी होगी सलमान खान की फिल्म के नाम

फिल्मों की घोषणाएं करने का अच्छा मंच बन गया है सोशल मीडिया। बात की जाए सलमान खान की तो वह अक्सर अपनी फिल्मों की घोषणा सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में करते आए हैं। सलमान ने अभी से अगले साल की ईद अपनी फिल्म के नाम कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी अगली फिल्म का नाम 'कभी ईद कभी दीवाली' होगी। फिल्म की कहानी साजिद नाडियाडवाला की है, निर्माण भी साजिद ही करेंगे। निर्देशन की बागडोर फरहाद सामजी संभालेंगे। फरहाद सामजी ने शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि 'कभी ईद कभी दीवाली का निर्देशन करने के लिए वह उत्सुक हैं'। फिल्मों की घोषणा करने का यह अंदाज सलमान खान का पुराना रहा है। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' जब किन्हीं कारणों से रुक गई थी, तब भी सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म की घोषणा करते हुए लिखा था, 'इतना मत सोचना मेरे बारे में। दिल में आता हूं और ईद पर भी।' जिस फिल्म का जिक्र सलमान ने किया था, वह फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' थी।

चिंताजनक

लुप्त होने की ओर बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र का द्वीप माजुली

नदी का आक्रामक प्रवाह बना निवासियों के जीवन के लिए खतरा, जलवायु परिवर्तन के कारण बदल गया है बाढ़ का रूप

- विशेषज्ञों की चेतावनी 2040 तक पूरी तरह लुप्त हो जाएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप
- नदी के रौद्र रूप के लिए मानवीय कुप्रबंधन है जिम्मेदार

पिछले 12 वर्षों में माजुली से 10,000 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। फाइल

माजुली, एएफपी : एक समय ब्रह्मपुत्र के हृदय में बसा माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता था। आज उसका अस्तित्व संकट में है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सबसे बड़ा नदी द्वीप 2040 तक पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। नदी का आक्रामक प्रवाह यहां के निवासियों के जीवन पर खतरा पैदा कर रहा है।

ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में है और वहां से हिमालय के बीच से बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी तक करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह विशाल नदी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण सालाना मानसून में बदलाव आया है। नदी में आने वाली बाढ़ का रूप काफी बदल गया है। इस दौरान नदी लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है।

नदी के इस स्वभाव के लिए काफी हद तक मानवीय कुप्रबंधन भी जिम्मेदार है जिससे समस्या बढ़ती चली जा रही है। हालत यह है कि माजुली के करीब 170,000 निवासियों का भविष्य अंधकारमय हो चला है। बाढ़ बहुत बड़े क्षेत्र को डुबो रही है और लंबे समय तक क्षेत्र में पानी जमा रहता है। इससे फसलें जहां कमजोर होती हैं, वहीं जमीन भी अपनी उर्वर क्षमता खो रही है।

इस द्वीप के निवासियों में से अधिकांश हिंदू धर्म के विशेष तौर तरीकों का पालन करने वाली जनजाति के लोग हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही यह समुदाय अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों की ओर चला जाता है, लेकिन जैसी स्थिति बनती जा रही है उसमें उनके पलायन के लिए कोई जगह शेष नहीं रह जाएगी।

सरसों और धान की खेती करने वाले किसान सुनील मिलि ने कहा, 'हम नदी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन यह हमारी सारी जमीन निगल लेगी। हम तो बस ब्रह्मपुत्र से दया की भीख ही मांग सकते हैं ताकि हम अपनी पूर्व की पीढ़ियों की ही तरह यहां शांति से अपना जीवन गुजार सकें।'

अब आधा से भी कम रह गया है यह द्वीप : 1890 में इस नदी द्वीप का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर था। ब्रह्मपुत्र का तेज प्रवाह इसके आधा से ज्यादा क्षेत्रफल को लील चुका है और अब यह मात्र 515 वर्ग किलोमीटर रह गया है। माजुली द्वीप संरक्षण एवं विकास परिषद के अनुसार अगले 15-20 वर्षों में यह नदी द्वीप पूरी तरह नष्ट हो सकता है। पिछले 12 वर्षों में 10,000 परिवार यहां से विस्थापित हो चुके हैं।